



सत्यमेव जयते



छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ में अलाभकारी संस्थाओं पर रिपोर्ट  
(1957 से 2008)

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,  
(कौशिल्या भवन, महिला पालिटेक्निक परिसर, बैरन बाजार)  
छत्तीसगढ़, रायपुर  
फोन नं. 0771-2331317



## प्राक्कथन

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के दिशा निर्देशानुसार, राज्य स्तर पर यह प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय आय में अलाभकारी संस्थाओं के योगदान के महत्व पर प्रकाश डालने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं पर यह सर्वेक्षण कार्य दो चरणों में कराया गया। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य इन पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कार्यकलापों व गतिविधियों, उत्पादन, रोजगार एवं अन्य वित्तीय पहलुओं पर आंकड़ों का संग्रहण करना था।

सर्वेक्षण के प्रथम चरण में विभिन्न अधिनियमों के तहत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की राज्य स्तरीय सूची तैयार की गई तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इन्हें विशेष पहचान क्रमांक प्रदान किया गया। प्रथम चरण के फ्रेम के आधार पर ही दूसरे चरण का सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया गया, जिसका उद्देश्य फील्ड ऑपरेशन के जरिए क्रियाशील पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की बिन्दुवार जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूचियों में इकट्ठा करना था। प्रदेश में द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 2009-10 में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थ अमले की सहायता से शुरू किया गया। यह रिपोर्ट द्वितीय चरण सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रविष्टियों के उपरांत प्राप्त संकलित प्रतिवेदनों पर आधारित है।

क्षेत्र से आंकड़ों के संग्रहण में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा यथोचित प्रयास किया गया, विशेष रूप से क्रियाशील अलाभकारी संस्थाओं द्वारा सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ जबकि पंजीबद्ध किन्तु स्थान परिवर्तित, विलुप्त एवं अक्रियाशील अलाभकारी संस्थाओं को खोजने में बहुत समय एवं श्रम का अपव्यय हुआ, क्योंकि ऐसी संस्थाओं का पता लगाने हेतु बारंबार प्रयास करने पर भी वांछित जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकी। मैं मैदानी स्तर पर, इस सर्वे कार्य में सहयोग देने वाले सभी सहायक सांख्यिकी अधिकारियों एवं खंड स्तरीय अन्वेषकों के साथ ही आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस सर्वेक्षण कार्य में समन्वय, डाटा के कम्प्यूटरीकरण और राज्यस्तरीय रिपोर्ट तैयार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहना करता हूँ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय  
रायपुर, छत्तीसगढ़.

अमिताभ पांडा  
संचालक



## विषय-सूची

क्र.	अध्याय विवरण	पृ. क्र.
1.	अलाभकारी संस्थाएं – एक परिचय	01
2.	अलाभकारी संस्थाएं अन्य संस्थागत क्षेत्रों से अलग कैसे है ?	02
3.	अलाभकारी संस्थाएं – पंजीयन हेतु अधिनियम	03
4.	अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के दौरान देखी गई कठिनाइयां	04
5.	छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं-संक्षिप्त विवरण	5-6
6.	छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सक्रिय (Traced) अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का वितरण	7-9
7.	छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र स्थान (ग्रामीण/शहरी) के अनुसार विवरण	10-12
8.	छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं पंजीयन वर्षवार विवरण	13-15
9.	सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का विवरण	16-18
10.	छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियाकलाप/प्रयोजनों के अनुसार पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का विवरण	19-23
11.	संस्थाओं का क्षेत्र जिसमें वे सेवारत है (शासकीय/उद्योग/गृहकार्य) के अनुसार वर्गीकरण	24-26
12.	छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में प्रबंधन समिति के सदस्यों का विवरण	27-28
13.	छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का लेखा विवरण	29-30
14.	छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में स्वयं सेवकों की संख्या (प्रबन्ध समिति के सदस्यों सहित)	31-34
15.	छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण अनुसार मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों (पूर्णकालिक/अल्पकालिक) का विवरण	34-37
16.	छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण अनुसार संलग्न कुल सदस्यों का विवरण	38-39
17.	छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण अनुसार संलग्न कुल सदस्यों की संख्या में विशेषज्ञों की संख्या	40-41
18.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के आय के स्रोत का विवरण	42-45
19.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं को प्राप्त विविध अनुदानों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण	46-49
20.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के व्ययों का विवरण	50-52
21.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के भौतिक परिसंपत्तियों का विवरण	53-55
22.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के फण्ड का वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश का विवरण	56-58
23.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि का जिलेवार विवरण	59-60
24.	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कुल निधि, (अंतिम अवशेष)	60-62
25.	Overview of the Survey - (Annexures-I )	63-76
26.	छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण हेतु निर्धारित अनुसूचियां (Annexures-II) एवं अनुदेशों (Annexures-III) की प्रतियां	



## अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण वर्ष 2010-2011 के महत्वपूर्ण तथ्य

क्र.	सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण तथ्य	संख्या	प्रतिशत
1	छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	39901	100
2	भेंट की गई कुल पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	13386	33.55
3	कुल सक्रिय कुल पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	3926	9.84
4	ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कुल पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	2202	56.08
5	शहरी क्षेत्र में कार्यरत कुल पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	1404	36.67
6	ग्रामीण या शहरी स्थिति स्पष्ट नहीं- पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	284	7.23
7	राज्य गठन से पूर्व (1957-2000) पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	557	14.18
8	राज्य गठन के पश्चात् (2000-2010) पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	3112	79.27
9	पंजीयन वर्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं- पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	257	6.55
10	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860, के तहत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	2888	73.56
11	पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1950, के तहत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	49	1.25
12	सो.रजि. एक्ट-1860 एवं पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1950, के तहत पंजीकृत संस्थाएं	29	0.74
13	रजिस्ट्रेशन एक्ट की स्थिति स्पष्ट नहीं- पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	960	24.45
14	सामाजिक सेवाक्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	1214	30.92
15	शिक्षा एवं शोध कार्य के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	617	15.72
16	संस्कृति एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	366	9.32
17	स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	297	7.56
18	लोकोपकार के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	292	7.44
19	व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	224	5.71
20	आवास एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	116	2.95
21	धर्म के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	77	1.96
22	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	27	0.69



सत्यमेव जयते

23	अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप एवं विधि के क्षेत्र में कार्यरत अलाभकारी संस्थाएं	1	0.03
24	क्रियाकलाप की स्थिति स्पष्ट नहीं—पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	694	6.98
25	एक क्रियाकलाप में संलग्न पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	2881	73.38
26	दो क्रियाकलापों में संलग्न पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	770	19.61
27	तीन या तीन से अधिक क्रियाकलापों में संलग्न पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	275	7.01
28	शासकीय क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	459	11.69
29	औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	551	14.04
30	पारिवारिक क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	2104	53.59
31	कार्य-क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	812	20.68
32	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में प्रबंध समिति के कुल सदस्य	36997	100
33	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में प्रबंध समिति के पुरुष सदस्य	19596	52.97
34	पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में प्रबंध समिति के महिला सदस्य	17401	47.03
35	लेखा तैयार व उपलब्ध—पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	765	19.49
36	लेखा तैयार व उपलब्ध नहीं— पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	675	17.19
37	लेखा अंकेक्षित नहीं—पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	2197	55.96
38	लेखा तैयार नहीं— पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं	289	7.39

## छ.ग. में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण – द्वितीय चरण

### अध्याय 1

#### अलाभकारी संस्थाएं – एक परिचय

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलाभकारी संस्थाओं की वृद्धि एवं महत्व के दृष्टिगत एवं सार्वजनिक/आर्थिक क्षेत्र में अभिवृद्धि हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकी प्रभाग, योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत समस्त पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की सूची का कम्प्यूटरीकरण करने एवं सर्वेक्षण द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों की सूचनाएं एकत्र करने का निर्णय लिया गया। जिसमें प्रथम चरण में सभी पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकृत सूची का संधारण किया गया एवं द्वितीय चरण में इन्हीं सुचीबद्ध पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण कार्य में सम्मिलित किया गया है।

- अलाभकारी संस्थाओं का आशय व्यक्ति, व्यक्ति समूह, व्यवसायिक समूह अथवा सरकार से बिना किसी लाभ-हानि, की प्रत्याशा के राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन कार्य हेतु विधि द्वारा स्थापित संस्थाएं होती हैं। इनके कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्यकारिणी के



सदस्य एवं स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं, किन्तु कुछ बड़ी अलाभकारी संस्थाएं, वैतनिक कर्मचारियों द्वारा भी संचालित होती हैं। इन संस्थाओं की बचत, संस्था के सदस्यों, प्रबंधकों अथवा अन्य लोगों के बीच वितरित ना कर, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता है। इन संस्थाओं को राज्य करों से छूट प्राप्त होती है।

- अलाभकारी संस्थाएं वे संगठन हैं जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ अर्जित करना नहीं होता है और ना ही ये वाणिज्यिक उद्देश्यों अथवा कारणों से प्रेरित होती है।
- वर्तमान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सकल घरेलु उत्पाद में इस क्षेत्र का अंशदान ज्ञात करना है।
- अलाभकारी संस्थाओं की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका है, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, जो आर्थिक आंकड़ों के संकलन रिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया को समूचे विश्व में निर्देशित करती है, के अनुसार, आय के मुख्य स्रोत के आधार पर ये संगठन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में क्रियान्वित हैं। इनके आय के स्रोत मुख्यतः संस्थागत फीस एवं सरकारी सहायता हैं।
- अलाभकारी संस्थाओं के पास वर्ष के दौरान अधिशेष राशियां हो सकती है, लेकिन अधिशेष राशि को संगठन के मालिक, सदस्य, संस्थापक या शासी बोर्ड आपस में वितरित न करते हुए संगठन के मूल उद्देश्य में पुनः उपयोग करते हैं।
- अलाभकारी संस्थाएं वे कानूनी और सामाजिक संस्थाएं हैं, जिन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है किन्तु इन संस्थाओं को यह छूट प्राप्त नहीं है, कि वे उन इकाइयों जिनके द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं वित्तिय सहायता प्राप्त करती हो, के लिए आय का स्रोत बने या वित्तिय लाभ पहुंचाएं। व्यवहार में, अलाभकारी संस्थाएं अपने उत्पादक गतिविधियों के लिए अधिशेष या घाटा उत्पन्न करने को बाध्य हैं लेकिन किसी भी अधिशेष को अन्य संस्थागत इकाइयों द्वारा आपस में विनियोजित नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी संस्थाओं की सैटेलाइट कार्यकारी परिभाषा निम्नलिखित है:-

- संगठन
- गैरलाभ के लिए, कानून और कस्टम द्वारा, लाभ के गैर वितरण के लिए
- संस्थागत रूप से सरकार से अलग
- स्वशासी
- गैर अनिवार्य



## अध्याय 2

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं अन्य संस्थाओं से अलग कैसे है?

अलाभकारी संस्थाओं की सबसे बुनियादी विशेषता यह है कि वे अपने लाभ का वितरण नहीं करती। मुनाफे का सृजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, न ही मुख्य रूप से व्यावसायिक लक्ष्यों और हितों से निर्देशित हैं। अलाभकारी संस्थाओं का गठन किया जा सकता है:-

1. व्यक्तियों या निगमों के लाभ के लिए जो उन्हें नियंत्रित एवं वित्तिय सहायता देते हैं।
2. धर्मार्थ या कल्याणकारी कारणों से, जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराने हेतु।
3. सशुल्क स्वास्थ्य सुविधा एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए लेकिन लाभ अर्जित करने के लिए नहीं।

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) द्वारा अलाभकारी संस्थाएं अन्य प्रमुख प्रकार की संस्थागत इकाइयों यथा – निगम, सरकारी एजेंसी, और घरेलु क्षेत्र से भिन्न परिभाषित किया गया है।

- निगम, अलाभकारी संस्थाओं से अलग है कि वे बाजार के उत्पादन में लगे हुए हैं और अपने मालिकों के लिए वित्तिय लाभ पैदा करने में सक्षम हैं।
- सरकारी इकाइयां, अलाभकारी संस्थाओं से अलग है कि वे अनुठी तरह की कानूनी इकाइयां हैं जो विधायी प्रक्रिया द्वारा स्थापित की गई हैं। जिनके पास दिए गए क्षेत्र के भीतर विधायी, न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकार हैं।
- घरेलु क्षेत्र की परिवारिक संस्थाएं, भी अलाभकारी संस्थाओं से अलग है क्योंकि वे एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समुह है जो एक ही आवासीय क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो अपनी आय एवं धन सामुहिक रूप से इकठठा करते हैं, प्राप्त आय तथा निश्चित सेवा एवं वस्तुओं का सामुहिक रूप से उपभोग करते हैं।



### अध्याय 3

## अलाभकारी संस्थाएं— पंजीयन हेतु अधिनियम

भारत में हालांकि अलाभकारी संस्थाएं विभिन्न अधिनियमों/प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत की जाती हैं। प्रमुख पंजीकरण अधिनियम हैं:—

- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860,
- भारतीय न्यास अधिनियम 1882,
- धर्मार्थ न्यास अधिनियम 1920,
- पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950,
- धार्मिक अधिनियम 1954,
- भारतीय कम्पनीज़ एक्ट 1956,
- वक्फ अधिनियम, 1995,

उपरोक्तानुसार विविध अधिनियमों में से यह सर्वेक्षण केवल सोसाइटीस् रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860—ए के अधीन पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं को ही इस सर्वेक्षण क्षेत्र की परिधि में लिया गया है, इसका मुख्य कारण यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सभी पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के लगभग 90 प्रतिशत संस्थाएं इस एक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में अविभाजित राज्य मध्य प्रदेश के नियम एवं निर्देशिका के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं का पंजीयन कार्य किया जा रहा है, जो कि केन्द्रीय सोसाइटीस् रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन है।





#### अध्याय 4

### छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के दौरान उत्पन्न कठिनाइयां

- यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य होने के बाद भी, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा पंजीकरण कार्यालय को कभी अपने कार्यालय में हुए स्थान परिवर्तनों से अवगत नहीं कराया गया। अतएव इनके कार्यालय के पते में हुए परिवर्तन, संस्था से जुड़े अधिकारियों/पदाधिकारियों की संरचना एवं नाम में परिवर्तन आदि— कुछ मामलों में हुए परिवर्तनों को रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचित किया गया किन्तु प्रशासनिक कारणों से ऐसे व्यवस्थित तंत्र का अभाव है जो पंजीकरण के बाद की अवधियों में होने वाले इन परिवर्तनों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर उन्हें अद्यतन स्थिति में संधारित करे। परिणामस्वरूप संस्थाओं के अस्तित्व में होने के बाद भी सर्वेक्षण अन्वेषकों द्वारा इन्हें खोजा नहीं जा सका।
- छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम के तहत संस्थाओं का पंजीकरण केवल एक ही चरण का कार्य है। एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण कई संस्थाएं गैर क्रियाशील अथवा निष्क्रिय हो गई हैं। पंजीकरण अधिकारियों द्वारा रिकार्ड की अद्यतन स्थिति हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं, अतः मौजूदा आंकड़े जमीनी स्तर पर व्याप्त वास्तविक तस्वीर पेश करने में असमर्थ है।



## अध्याय 5

### छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाएं—संक्षिप्त विवरण

प्रदेश में, पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के प्रथम चरण में सूचिबद्ध 39901 संस्थाएं जो रजिस्ट्रार फर्मस् एवं सोसायटी कार्यालय द्वारा अपनी स्थापना से वर्ष 2007-08 तक की अवधियों में पंजीकृत की गई हैं, को शामिल किया गया है। अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण से संबंधित मुख्य पहलु यथा सर्वेक्षण डिजाइन एवं स्वीकार किए गए संकल्पनाओं की इस अध्याय में व्याख्या की गई है।

#### ● संदर्भ अवधि :-

इस संदर्भ में निर्धारित अनुसूचियों में आंकड़े एकत्रित करने के लिए समयावधि 01/04/2007 से 31/03/2008 निर्धारित की गई थी किन्तु राज्य में यह सर्वेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पन्न कराया गया, अतएव राज्य में मौजूद अलाभकारी संस्थाओं से इसी संदर्भावधि में उपलब्ध लेखा विवरणों को भी मान्य किया गया। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी संस्थाएं थीं, जिन्होंने किसी भी वर्षों में लेखा विवरण पुस्तिका का संधारण नहीं किया था, उनके लेखाओं की जानकारी साक्षात्कार के माध्यम से, मौखिक सूचनाओं के आधार पर एकत्रित की गई।

#### ● अनुसूचियों के प्रकार :-

संस्था के रोजगार एवं वित्तीय मानकों के संग्रहण के लिए तीन प्रकार की अनुसूची 1. परिचयात्मक अनुसूची 2.0:I, 2. विस्तृत आंकड़े अनुसूची 2.0:D, 3. मुख्य आंकड़े अनुसूची 2.0:K तैयार किए गए हैं। प्रथम चरण के कार्य में प्रदेश में समस्त पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का कम्प्यूटराइजेशन कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई-दिल्ली के निर्देशन में पूर्ण किया गया है, जिसमें सूचिबद्ध 39901 अलाभकारी संस्थाएं जो रजिस्ट्रार फर्मस् एवं सोसायटी कार्यालय द्वारा पंजीकृत की गई थी, को ही द्वितीय चरण के सर्वेक्षण कार्य के लिए फ्रेम के तौर पर प्रयुक्त किया गया।

द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में इन्हीं सूचिबद्ध 39901 अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण, जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से समस्त खोजी (TRACE) गई संस्थाओं की परिचयात्मक अनुसूची 2.0:I, में जानकारी एकत्रित की गई, तदुपरांत जिन संस्थाओं के वित्तीय लेखा विवरण उपलब्ध थे उनके विस्तृत आंकड़े अनुसूची 2.0:D में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई तथा वे संस्थाएं जहां के वित्तीय आंकड़ों का लेखा जोखा तैयार/उपलब्ध नहीं थे, उन संस्थाओं के मुख्य आंकड़े अनुसूची 2.0:K प्राप्त किये गये। इस प्रकार सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में उपरोक्त संस्थाओं का अन्वेषकों द्वारा दौरा कर सक्रिय संस्थाओं का पता लगाया गया तथा उनकी वित्तीय स्थिति एवं रोजगार संबंधी जानकारियों का एकत्रीकरण किया गया।

#### सर्वेक्षण कार्य में प्रयुक्त अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- परिचयात्मक अनुसूची 2.0:I** (Identification schedule 2.0:I) – यह अनुसूची संस्था का नाम, पंजीकरण का वर्ष, संस्था का स्थिति कोड ( ग्रामीण-1, शहरी-2), संस्था का पूर्ण पता, गतिविधियां/उद्देश्य और कोड, क्षेत्र जिसमें वे सेवारत हैं, प्रबंधन मंडल में सदस्यों की संख्या, संस्थाओं की लेखा स्थिति आदि प्रारंभिक परिचयात्मक जानकारियां ही समाहित की गई।
- विस्तृत लेखा अनुसूची 2.0:D** (Detailed Data schedule 2.0:D) – यदि सोसाइटी के लेखों की स्थिति कोड 1 है: अर्थात् यदि लेखा तैयार और उपलब्ध है, तो इस अनुसूची में डाटा का संग्रहण किया गया, जिसमें रोजगार संबंधी आंकड़ें-वेतनभोगियों तथा स्वयंसेवकों की संख्या और वित्तीय जानकारियां जैसे- आय के स्रोत, खर्च की मदे, नवीन भौतिक वस्तुएं तथा संदर्भित वर्ष अप्रैल 2007 – मार्च 2008 के लिये सोसाइटी के लिये भौतिक वस्तुओं का स्टॉक आदि को सम्मिलित किया गया।



c) **लेखा अनुसूची 2.0:K** (Key Data schedule 2.0:K) – यदि सोसाइटी के लेखों की स्थिति कोड 2 या 3 है अर्थात् लेखा तैयार है परन्तु उपलब्ध नहीं है या लेखा तैयार नहीं है, तो संस्थाओं के भौतिक एवं वित्तीय जानकारियों का संग्रहण इस अनुसूची में किया गया। इस अनुसूची में अपेक्षाकृत कम मदों में जैसे रोजगार, व्यय तथा आय से संबंधित आंकड़ें संग्रहित किये।

राज्य में प्रथम चरण की समाप्ति के पश्चात् वर्ष 2009-10 में निम्न उद्देश्यों को लेकर द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया—

1. सक्रिय पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के मूल्यांकन के लिये।
2. संस्थाओं का वितरण—
  - स्थान के अनुसार— ग्रामीण/शहरी स्थिति।
  - उद्देश्य के अनुसार— स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक आदि।
  - क्षेत्र जिसमें वे सेवारत हैं – शासकीय, औद्योगिक, घरेलू आदि।
3. संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तु अथवा सेवाओं के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिये।
4. वर्ष के दौरान भौतिक वस्तुओं पर किये गये कुल निवेश का मूल्यांकन करने के लिये।
5. खर्च का वितरण
  - उद्देश्य के अनुसार
  - क्षेत्र जिसमें वे सेवारत हैं, के अनुसार



## अध्याय 6

### छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सक्रिय (TRACED) अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का वितरण

सर्वेक्षण के प्रथम चरण में अलाभकारी संस्थाओं के पंजीकरण कार्य हेतु अधिकृत विभागीय कार्यालयों में उपलब्ध सोसाइटियों के मूल रिकॉर्ड से जिलेवार 39901 पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया।

सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा निर्धारित तीन अनुसूचियों में इन पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के बिन्दुवार परिचायात्मक, विषय में वित्तीय एवं रोजगार संबंधी आंकड़ें एकत्रित किये गए। राज्य में प्रथम चरण के दौरान सूचीबद्ध कुल 39901 पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में से 3926 संस्थाएं खोजी गईं अथवा क्रियाशील पाई गईं, जो कि कुल पंजीकृत संस्थाओं का मात्र 9.84% है। इस प्रकार राज्य में कुल 3926 पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के आंकड़ें केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के निर्देशन में जि. यो. एवं सां. कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा कम्प्यूटरीकृत किए गए।

क्र.	संक्षिप्त विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	प्रथम चरण के दौरान पंजीकृत अलाभकारी संस्थायें	39901	—
2	द्वितीय चरण के दौरान खोजी गईं पंजीकृत अलाभकारी संस्थायें	3926	09.84
3	सर्वे की गईं पंजीकृत अलाभकारी संस्थायें	3926	09.84

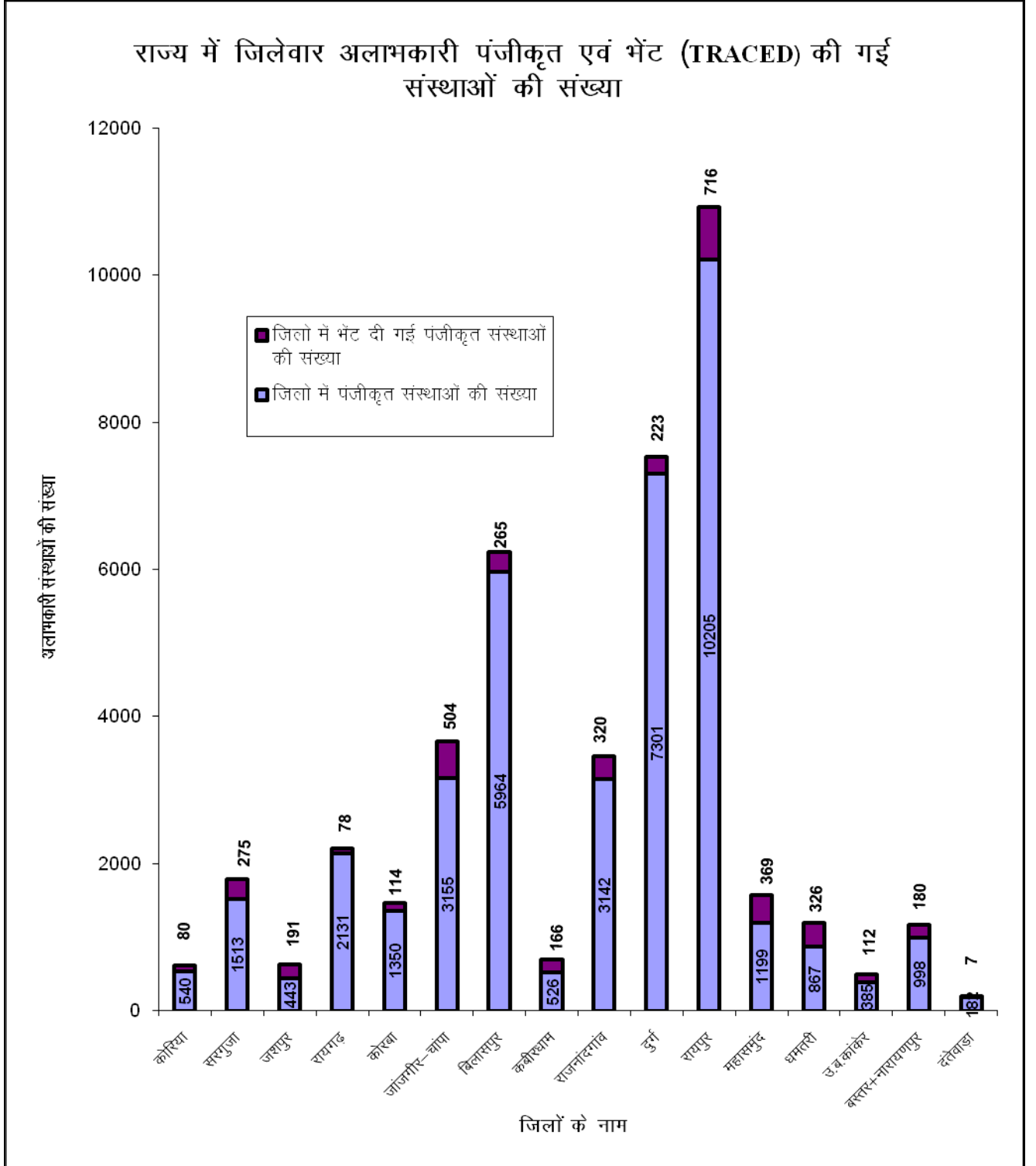


**तालिका क्रमांक-1**  
**छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार अलाभकारी पंजीकृत एवं भेंट (TRACED) की**  
**गई संस्थाओं की संख्या**

क्रं	जिलों के नाम	जिलो में पंजीकृत संस्थाओं की संख्या	जिलो में (TRACED) भेंट दी गई पंजीकृत संस्थाओं की संख्या	जिलो में (TRACED) भेंट दी गई पंजीकृत संस्थाओं की संख्या का प्रथम फेज में सूचिबद्ध कुल पंजीकृत संस्थाओं से प्रतिशत
1	कोरिया	540	80	15%
2	सरगुजा	1513	275	18%
3	जशपुर	443	191	43%
4	रायगढ़	2131	78	4%
5	कोरबा	1350	114	8%
6	जांजगीर-चांपा	3155	504	16%
7	बिलासपुर	5964	265	4%
8	कबीरधाम	526	166	32%
9	राजनांदगांव	3142	320	10%
10	दुर्ग	7301	223	3%
11	रायपुर	10205	716	7%
12	महासमुंद	1199	369	31%
13	धमतरी	867	326	38%
14	उ.ब.कांकेर	385	112	29%
15	बस्तर+नारायणपुर	998	180	18%
16	दंतेवाड़ा	182	7	4%
	<b>योग</b>	<b>39901</b>	<b>3926</b>	<b>9.84%</b>



चित्र क्रमांक-1  
छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार अलाभकारी पंजीकृत एवं भेंट (TRACED) की गई संस्थाओं की संख्या





## अध्याय-7

### छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं के कार्यक्षेत्र स्थान (ग्रामीण/शहरी) के अनुसार विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के दौरान खोज की गई कुल 3926 संस्थाओं में से 2202 (56%) संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1440 (37%) संस्थाएं शहरी क्षेत्र में पायी गई, इन पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में से 284 (7%) संस्थाओं के कार्यस्थल के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। जिलेवार प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाएं जशपुर जिले में 73.29% तथा सबसे कम दुर्ग जिले में 4.48% में पाई गई। जबकि शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में सबसे अधिक अनुपात कोरिया जिले में 68.42% तथा सबसे कम दुर्ग जिले में 5.38% में पाई गई, जबकि दुर्ग जिले से 90.13% संस्थाओं के विषय में सर्वेक्षण के दौरान यह जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी कि वे ग्रामीण है या शहरी।

#### तालिका क्रमांक-2

#### छत्तीसगढ़ राज्य में भेंट दी गई अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं की क्षेत्रवार संख्या (ग्रामीण एवं शहरी)

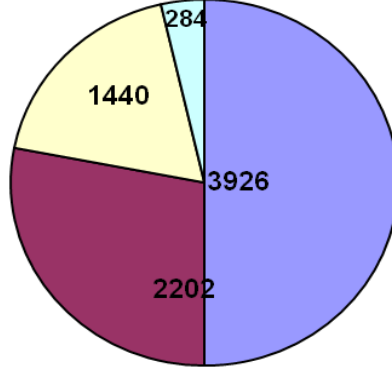
संस्था की ग्रामीण/नगरीय स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या						
कुल संस्थाएं	ग्रामीण	प्रतिशत	नगरीय	प्रतिशत	स्थिति स्पष्ट नहीं	प्रतिशत
3926	2202	56%	1440	37%	284	7%

#### चित्र क्रमांक-2

#### छत्तीसगढ़ राज्य में भेंट दी गई अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं की क्षेत्रवार संख्या (ग्रामीण एवं शहरी)



संस्था की ग्रामीण/नगरीय स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या



- संस्था की ग्रामीण/नगरीय स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या कुल संस्थाएं
- संस्था की ग्रामीण/नगरीय स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या ग्रामीण
- संस्था की ग्रामीण/नगरीय स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या नगरीय
- संस्था की ग्रामीण/नगरीय स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या स्थिति स्पष्ट नहीं





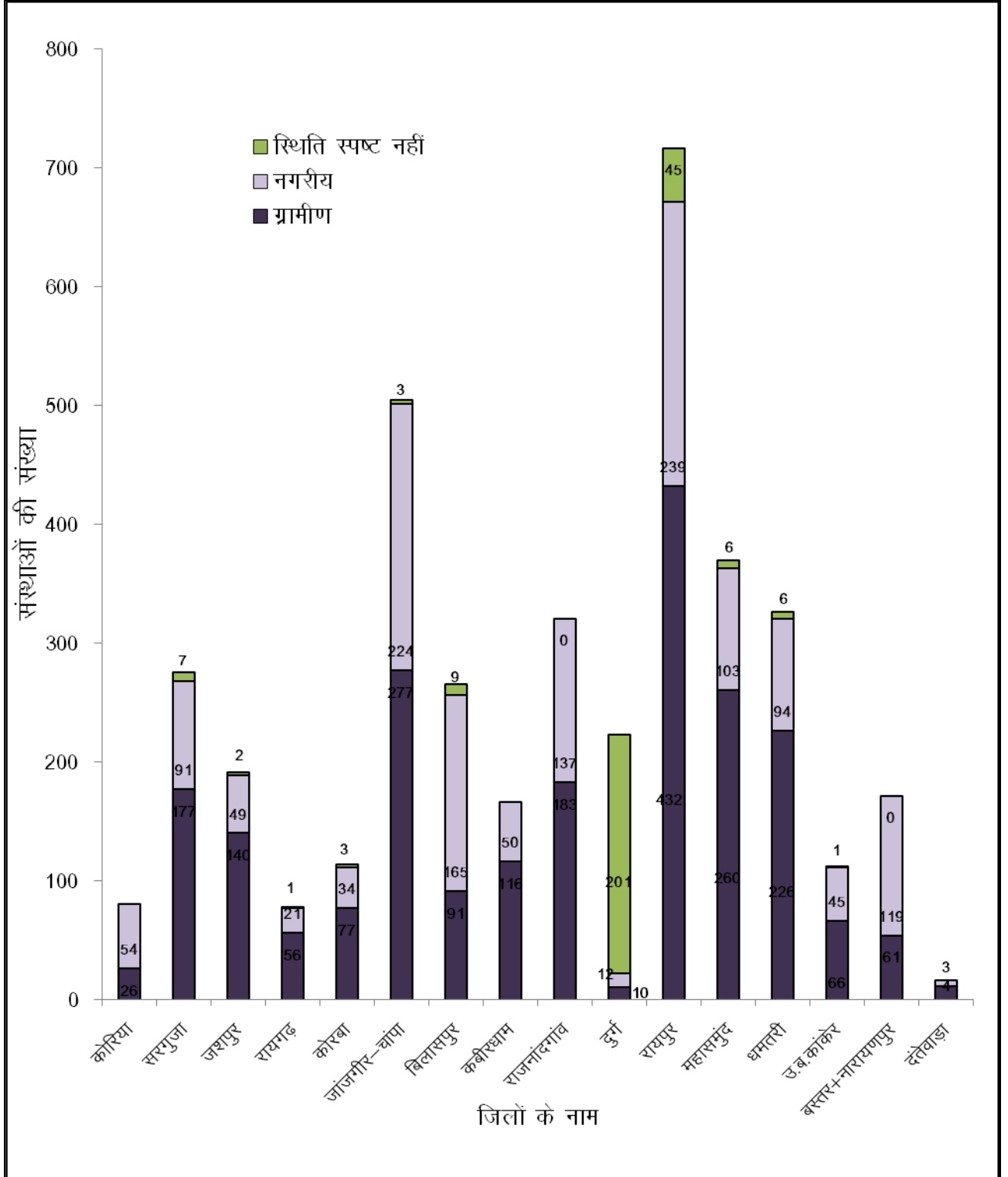
सत्यमेव जयते

**तालिका क्रमांक-3**  
**छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार भेंट दी गई अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं की क्षेत्रवार**  
**(ग्रामीण एवं शहरी) संख्या**

क्र.	जिलों के नाम	संस्था का स्थिति के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या					
		ग्रामीण		नगरीय		स्थिति स्पष्ट नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कोरिया	26	32%	54	67%	0	0
2	सरगुजा	177	64%	91	33%	7	2%
3	जशपुर	140	73%	49	25%	2	1%
4	रायगढ़	56	71%	21	26%	1	1%
5	कोरबा	77	67%	34	29%	3	2%
6	जांजगीर-चांपा	277	54%	224	44%	3	0.5%
7	बिलासपुर	91	34%	165	62%	9	3%
8	कबीरधाम	116	69%	50	30%	0	0
9	राजनांदगांव	183	57%	137	42%	0	0
10	दुर्ग	10	4%	12	5%	201	90%
11	रायपुर	432	60%	239	33%	45	6%
12	महासमुंद	260	70%	103	27%	6	1%
13	धमतरी	226	69%	94	28%	6	1%
14	उ.ब.कांकेर	66	58%	45	40%	1	0.8%
15	बस्तर+नारायणपुर	61	34%	119	66%	0	0
16	दंतेवाड़ा	4	57%	3	43%	0	0
	<b>योग</b>	<b>2202</b>	<b>56%</b>	<b>1440</b>	<b>37%</b>	<b>284</b>	<b>7%</b>



**चित्र क्रमांक -3**  
**छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की**  
**ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रवार संख्या**





## अध्याय-8

### छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का पंजीयन वर्षवार विवरण

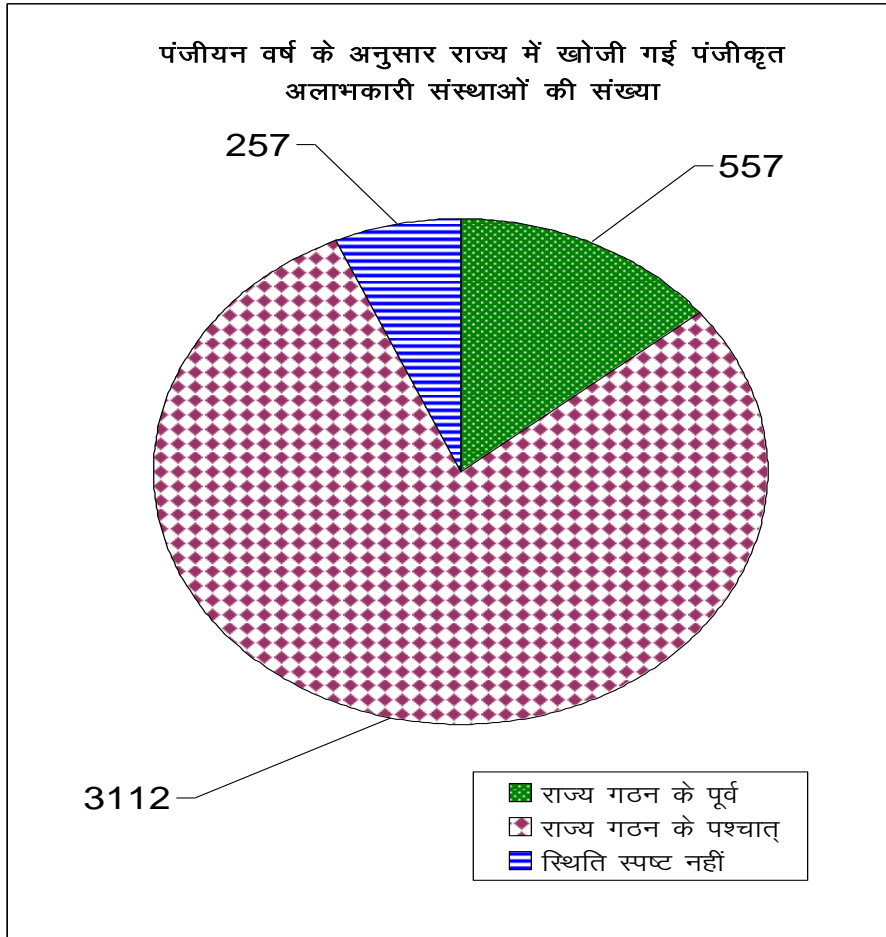
राज्य में खोजी गई अलाभकारी संस्थाएं विभिन्न वर्षों में पंजीकृत की गईं। इन संस्थाओं का पंजीयन के वर्षों के आधार पर वर्गीकरण करने पर पाया गया कि कुल 3926 खोजी गई अलाभकारी संस्थाओं में से 3112 अलाभकारी संस्थाएं राज्य गठन के पश्चात् अर्थात् वर्ष 2000 से 2012 के दौरान पंजीकृत की गईं, जो कुल संस्थाओं का 79.26% है। सन् 2000 से पहले राज्य में कुल 557 (14.18%) अलाभकारी संस्थाएं ही पंजीकृत थीं, 257 संस्थाओं (6.54%) के पंजीकरण वर्ष के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है।

#### तालिका क्रमांक-4

#### पंजीयन वर्ष के अनुसार राज्य में पंजीकृत खोजी गई पंजीकृत संस्थाओं की कुल संख्या

राज्य गठन के पूर्व		राज्य गठन के पश्चात्		स्थिति स्पष्ट नहीं		कुल संख्या
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
557	14.00	3112	79.00	257	6.98	3926

#### चित्र क्रमांक-4





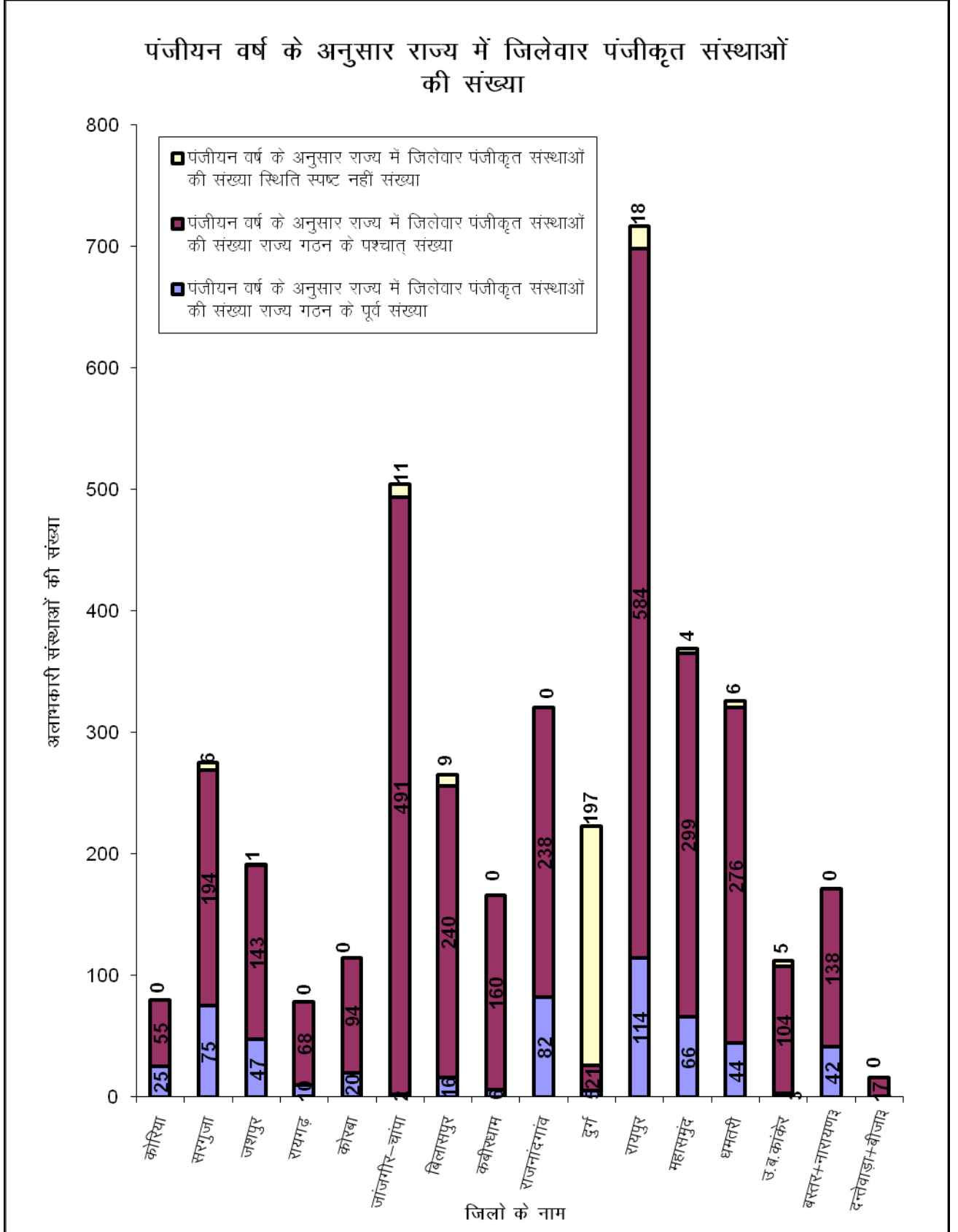
**तालिका क्रमांक-5**  
**पंजीयन वर्ष के अनुसार राज्य में जिलेवार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या**

क्र.	जिलों के नाम	राज्य गठन (वर्ष 2001) के पूर्व		राज्य गठन (वर्ष 2001) के पश्चात्		स्थिति स्पष्ट नहीं		अलाभकारी संस्थाओं की कुल संख्या
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	कोरिया	25	31	55	68	0	0	80
2	सरगुजा	75	27	194	70	6	2	275
3	जशपुर	47	24	143	74	1	0	191
4	रायगढ़	10	12	68	87	0	0	78
5	कोरबा	20	17	94	82	0	0	114
6	जांजगीर-चांपा	2	0	491	97	11	2	504
7	बिलासपुर	16	6	240	90	9	3	265
8	कबीरधाम	6	3	160	96	0	0	166
9	राजनांदगांव	82	25	238	74	0	0	320
10	दुर्ग	5	2	21	9	197	88	223
11	रायपुर	114	15	584	81	18	2.5	716
12	महासमुंद	66	17	299	81	4	1	369
13	धमतरी	44	13	276	84	6	1.8	326
14	उ.ब.कांकेर	3	2.6	104	92	5	4	112
15	बस्तर+नारायणपुर	42	23.9	138	77	0	0	180
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	0	0	7	100	0	0	7
<b>योग</b>		<b>557</b>	<b>14%</b>	<b>3112</b>	<b>79%</b>	<b>257</b>	<b>7%</b>	<b>3926</b>



### चित्र क्रमांक-5

पंजीयन वर्ष के अनुसार राज्य में जिलेवार पंजीकृत संस्थाओं की संख्या





## अध्याय 9

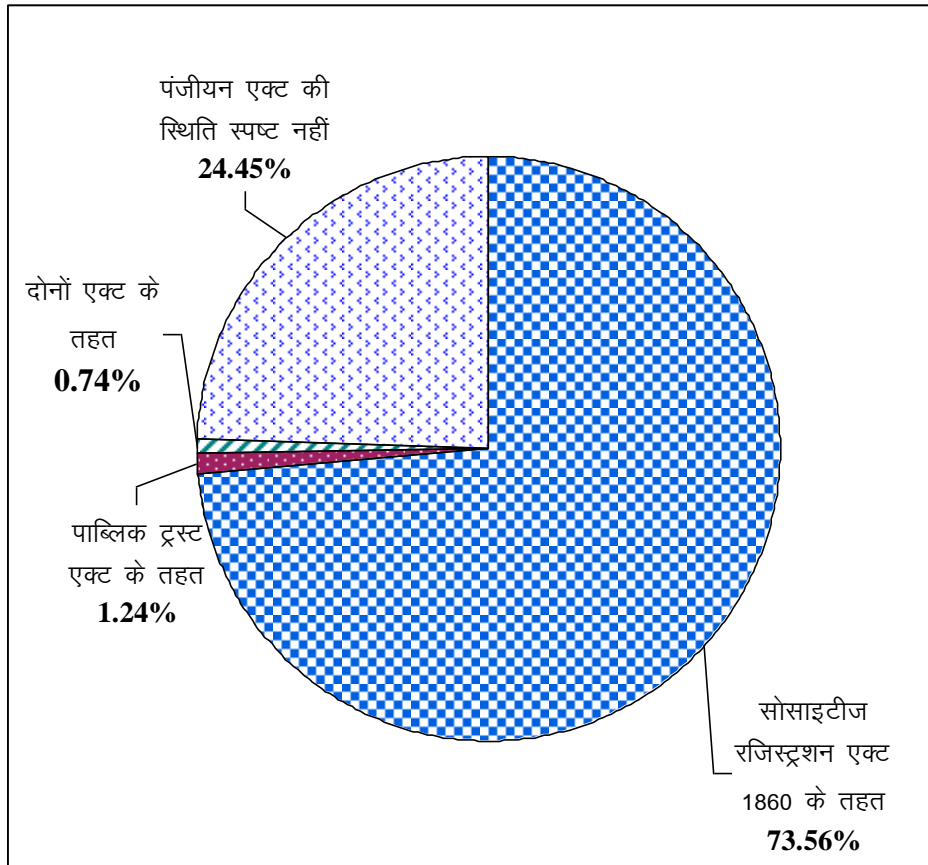
### सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का विवरण

भारत में हालांकि अलाभकारी संस्थाएं विभिन्न अधिनियमों के अधीन विविध विभागों अथवा प्राधिकरणों के द्वारा पंजीकृत किये जाते हैं। मुख्य पंजीकरण अधिनियम हैं :- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860, भारतीय न्यास अधिनियम -1882, पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950, धर्मार्थ न्यास अधिनियम 1920, धार्मिक अधिनियम 1954, प्रदेश में यह सर्वेक्षण केवल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 या दोनों के अधीन पंजीकृत संस्थाओं के लिए ही सम्पादित किया गया है, इसका मुख्य कारण सभी राज्यों में अलाभकारी संस्थाओं के लगभग 90 प्रतिशत संस्थाएं इस एक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। कुल 3926 संस्थाओं में 2888 (73.56%) अलाभकारी संस्थाएं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के तहत पंजीकृत हैं, जबकि मात्र 49 (1.25%) अलाभकारी संस्थाएं पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत हैं तथा 29 (0.74%) संस्थाओं दोनो अधिनियमों के तहत पंजीकृत पाई गई है।

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं में सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगांव जिले में 99.38% तथा न्यूनतम दुर्ग जिले में 6.28% है। पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत संस्थाओं में सर्वाधिक प्रतिशत कांकर जिले में 10.71% तथा न्यूनतम जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बीजापुर जिले में 0% है। उपरोक्त दोनो अधिनियमों के तहत 29 संस्थाएं पंजीकृत हैं, जबकि 960 संस्थाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

#### चित्र क्रमांक-6

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं का प्रतिशत





तालिका क्रमांक-6

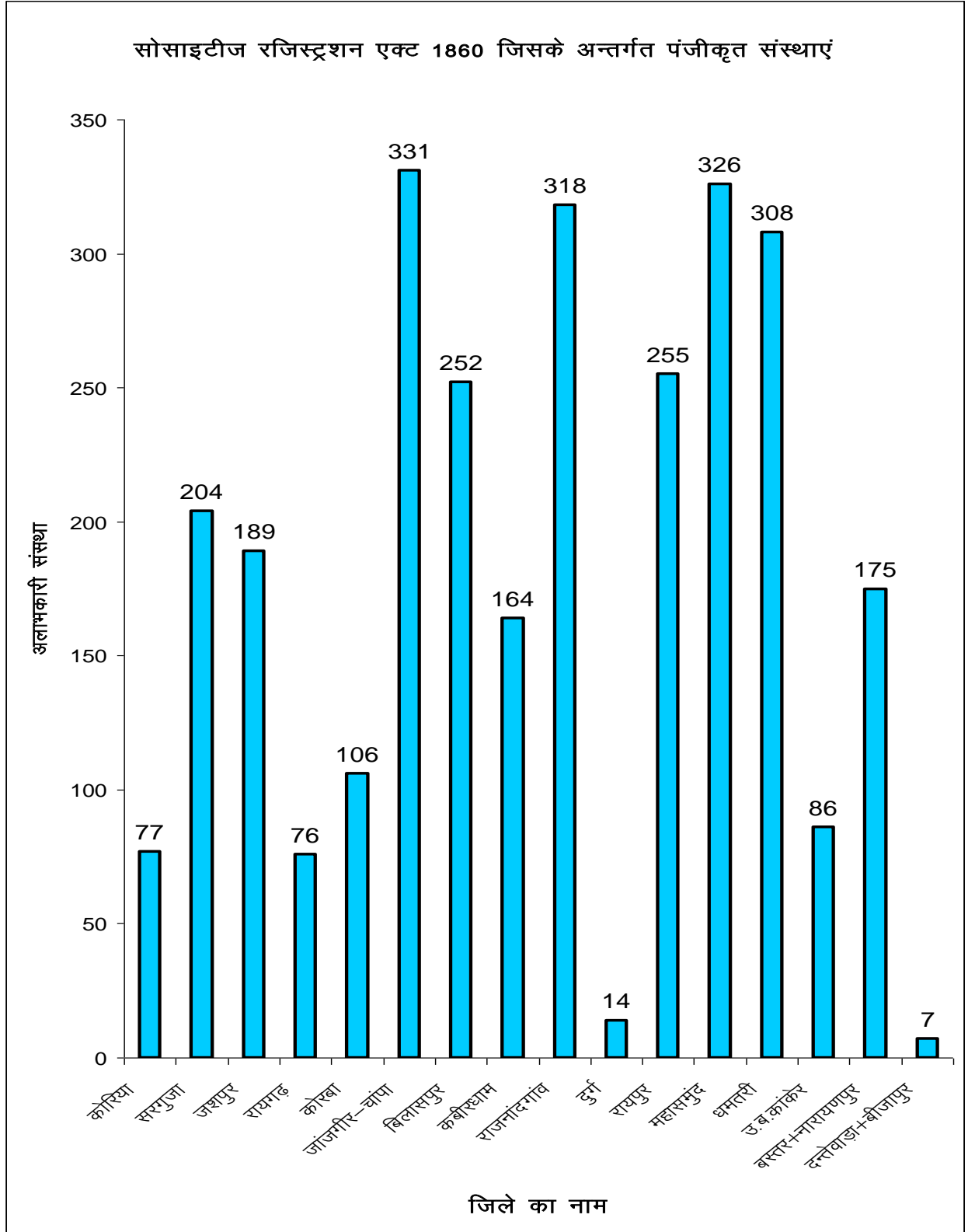
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, पाब्लिक ट्रस्ट एक्ट या दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की जिलेवार संख्या एवं प्रतिशत

क्रं	जिलों के नाम	अधिनियम जिसके अन्तर्गत संस्था का पंजीकरण हुआ है (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860/पाब्लिक ट्रस्ट एक्ट/ दोनों एक्ट्स के तहत)								
		सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860-1		पाब्लिक ट्रस्ट एक्ट -2		दोनों -3		स्थिति स्पष्ट नहीं		कुल अलाभकारी संस्थाओं की संख्या
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	कोरिया	77	96.25	1	1.25	2	2.50	0	0	80
2	सरगुजा	204	74.18	10	3.64	10	3.64	51	18.55	275
3	जशपुर	189	98.95	0	0.00	0	0.00	2	1.05	191
4	रायगढ़	76	97.44	0	0.00	0	0.00	2	2.56	78
5	कोरबा	106	92.98	0	0.00	1	0.88	7	6.14	114
6	जांजगीर-चांपा	331	65.67	3	0.60	3	0.60	167	33.13	504
7	बिलासपुर	252	95.09	0	0.00	3	1.13	10	3.77	265
8	कबीरधाम	164	98.8	1	0.60	0	0.00	1	0.6	166
9	राजनांदगांव	318	99.38	2	0.63	0	0.00	0	0.00	320
10	दुर्ग	14	6.28	4	1.79	1	0.45	204	91.48	223
11	रायपुर	255	35.61	1	0.14	3	0.42	457	63.83	716
12	महासमुंद	326	88.35	9	2.44	1	0.27	33	8.94	369
13	धमतरी	308	94.48	1	0.31	1	0.31	16	4.91	326
14	उ.ब.कांकेर	86	76.79	12	10.71	4	3.57	10	8.93	112
15	बस्तर+नारायणपुर	175	97.22	5	2.78	0	0.00	0	0.00	180
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7
	<b>योग</b>	<b>2888</b>	<b>73.56</b>	<b>49</b>	<b>1.25</b>	<b>29</b>	<b>0.74</b>	<b>960</b>	<b>24.45</b>	<b>3926</b>



चित्र क्रमांक- 7

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की  
जिलेवार संख्या







## अध्याय-10

### छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियाकलाप/प्रयोजनों के अनुसार पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं को उनके क्रियाकलापों के अनुसार वर्गीकृत करने के उद्देश्य से सर्वे किया गया एवं निम्नानुसार प्रमुख क्रियाकलापों में वर्गीकृत पाया गया :-

प्रमुख क्रियाकलाप विवरण	संख्या	प्रतिशत
संस्कृति एवं मनोरंजन	366	9.32
शिक्षा एवं शोध	617	15.72
स्वास्थ्य	297	7.56
सामाजिक सेवाएं	1214	30.92
पर्यावरण	27	0.69
आवास एवं विकास	116	2.95
विधि, वकालत एवं राजनीति	01	0.03
लोकोपकारी, मध्यवर्ती तथा स्वयंसेवी संस्थाएं	292	7.44
अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप	01	0.03
धार्मिक संस्थाएं	77	1.96
व्यावसायिक एवं पेशेवर संस्थाएं, संघ	224	5.71
अन्य	420	10.70
स्थिति स्पष्ट नहीं	274	6.98
<b>योग</b>	<b>3926</b>	<b>100</b>

कुल खोजी गयी अर्थात् मौजूद (TRACED) 3926 संस्थाओं में सर्वाधिक संस्थाएं 1214 (30.90%) सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, 617 (15.7%) संस्थाएं शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में, 366 (9.3%) संस्थाएं संस्कृति एवं मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, 297 (7.6%) स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, 292 (7.4%) लोकोपकारी, मध्यवर्ती तथा स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। जबकि 224 (5.7%) व्यावसायिक एवं पेशेवर संस्थाएं हैं तथा 116 (3%) आवास एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही 77 (2%) संस्थाएं धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं जबकि 27 (0.7%) संस्थाएं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। सबसे कम 1 (0.03%) संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप एवं विधि, वकालत के क्षेत्र में कार्यरत है तथा कुल 274 (7%) संस्थाओं के क्रियाकलापों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई।

कुल पंजीकृत 3926 संस्थाओं में 2881 (73.38%) संस्थाएं न्यूनतम एक क्रियाकलाप में संलग्न हैं, जिनमें से कुल 770 (19.61%) संस्थाएं दो प्रकार के क्रियाकलाप संचालित कर रहे हैं। जबकि 275 (7.01%) संस्थाएं तीन क्रियाकलापों में संलग्न हैं। प्रदेश के राजनांदगांव जिले में तीन क्रियाकलापों वाली सर्वाधिक 60 (18.8%) अलाभकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं, जबकि कबीरधाम जिले में तीन क्रियाकलाप संचालित कर रही संस्था एक भी नहीं है।



तालिका क्रमांक-7

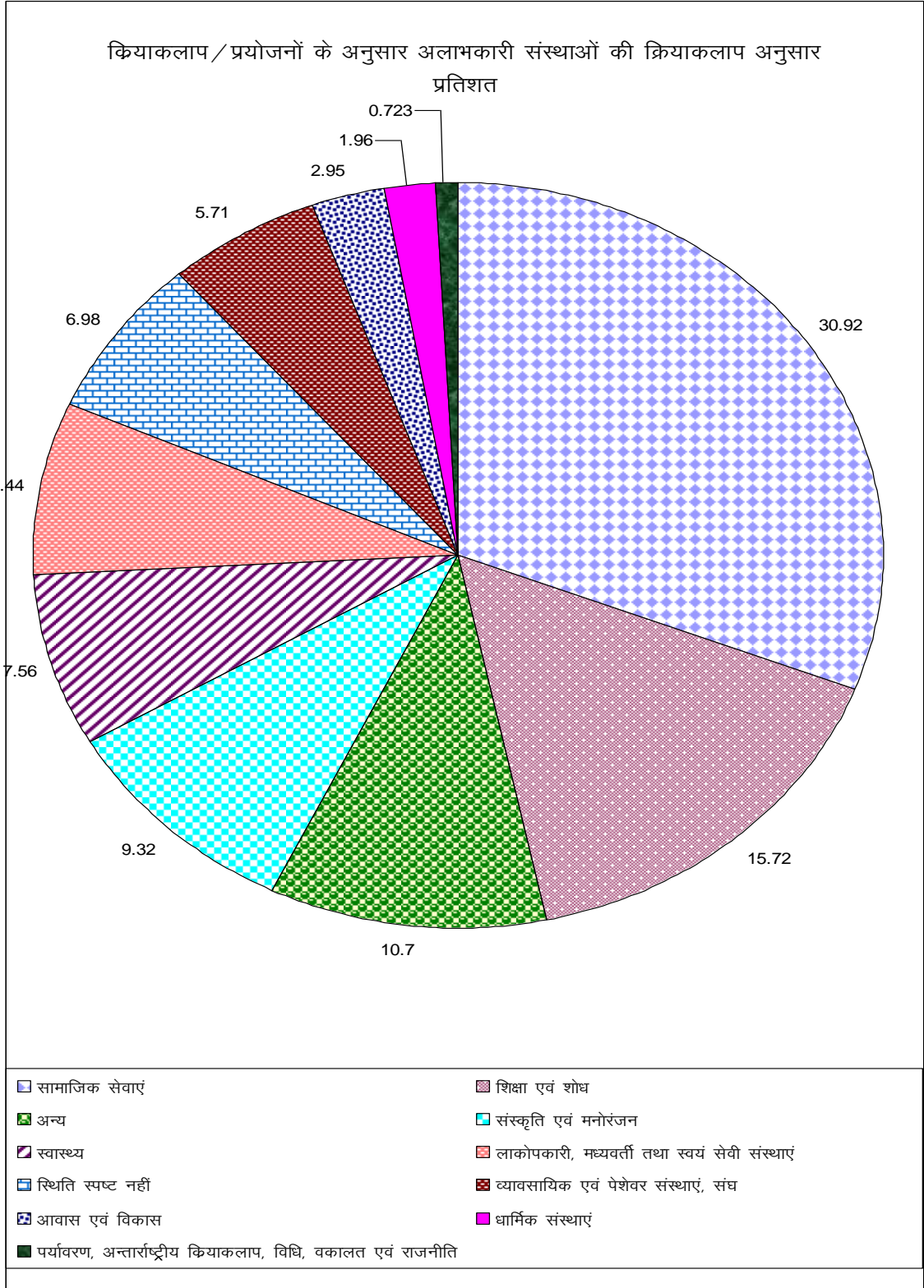
छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियाकलाप/प्रयोजनों के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं की जिलेवार संख्या तथा क्रियाकलाप अनुसार प्रतिशत वितरण

क्र.	जिलों के नाम	क्रियाकलाप/प्रयोजनों के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं की जिलेवार संख्या तथा क्रियाकलाप अनुसार प्रतिशत													
		संस्कृत एवं मनोरंजन	शिक्षा एवं शोध	स्वास्थ्य	सामाजिक सेवाएं	पर्यावरण	आवास एवं विकास	विधिवकालत एवं राजनीति	लाकोपकारी, मध्यवर्ती तथा स्वयंसेवी संस्थाएं	अन्ताराष्ट्रीय क्रियाकलाप	धार्मिक संस्थाएं	व्यावसायिक एवं पेशेवर संस्थाएं, संघ	अन्य	स्थिति स्पष्ट नहीं	योग
1	कोरिया	2	43	9	20	0	0	0	3	0	1	2	0	0	80
2	सरगुजा	2	133	56	66	0	0	0	2	0	2	1	3	10	275
3	जशपुर	5	86	30	45	5	4	0	1	0	8	0	4	3	191
4	रायगढ़	7	18	3	18	0	0	0	20	0	1	1	0	10	78
5	कोरबा	6	14	19	29	0	0	0	0	0	1	10	32	3	114
6	जांजगीर-चांपा	36	38	8	75	3	2	0	148	0	9	62	3	120	504
7	बिलासपुर	20	40	7	140	0	14	0	15	0	5	6	6	12	265
8	कबीरधाम	23	14	8	70	1	0	0	1	0	2	42	3	2	166
9	राजनांदगांव	33	42	10	190	4	2	0	2	0	7	27	3	0	320
10	दुर्ग	2	6	1	5	0	0	0	2	0	4	2	201	0	223
11	रायपुर	106	57	23	317	2	88	1	22	0	9	17	23	51	716
12	महासमुंद	52	42	21	72	5	3	0	35	1	11	23	68	36	369
13	धमतरी	38	41	19	125	2	2	0	25	0	7	22	36	9	326
14	उ.ब.कांकेर	15	15	37	20	1	0	0	0	0	0	0	7	17	112
15	बस्तर+नारायणपुर	19	28	39	22	4	1	0	16	0	10	9	31	1	180
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
<b>योग</b>		<b>366</b>	<b>617</b>	<b>297</b>	<b>1214</b>	<b>27</b>	<b>116</b>	<b>1</b>	<b>292</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>224</b>	<b>420</b>	<b>274</b>	<b>3926</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>9.32</b>	<b>15.72</b>	<b>7.56</b>	<b>30.92</b>	<b>0.69</b>	<b>2.95</b>	<b>0.003</b>	<b>7.44</b>	<b>0.03</b>	<b>1.96</b>	<b>5.71</b>	<b>10.7</b>	<b>6.98</b>	<b>100</b>



### चित्र क्रमांक-8

छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियाकलाप/प्रयोजनों के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं की संख्या का प्रतिशत वितरण





### तालिका क्रमांक-8

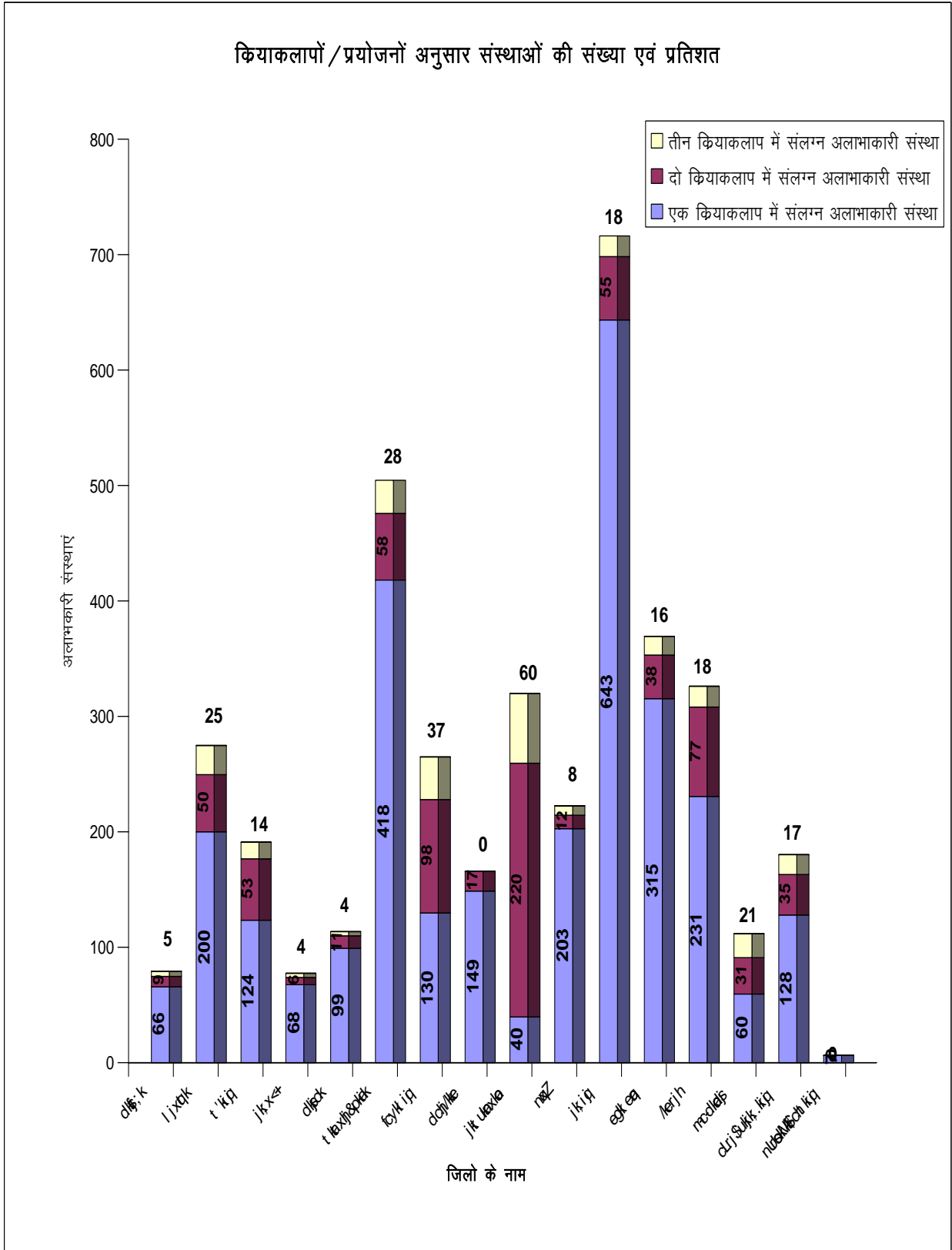
छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं की संचालित क्रियाकलापों के अनुसार जिलेवार संख्या एवं प्रतिशत

क्र.	जिलों के नाम	कुल खोजी गई पंजीकृत संस्थाएं	क्रियाकलापों/प्रयोजनों अनुसार संस्थाओं की संख्या एवं प्रतिशत					
			एक क्रियाकलाप में संलग्न अलाभकारी संस्था		दो क्रियाकलाप में संलग्न अलाभकारी संस्था		तीन क्रियाकलाप में संलग्न अलाभकारी संस्था	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	कोरिया	80	66	82.50	9	11.25	5	6.25
2	सरगुजा	275	200	72.73	50	18.18	25	9.09
3	जशपुर	191	124	64.92	53	27.75	14	7.33
4	रायगढ़	78	68	87.18	6	7.69	4	5.13
5	कोरबा	114	99	86.84	11	9.65	4	3.51
6	जांजगीर-चांपा	504	418	82.94	58	11.51	28	5.56
7	बिलासपुर	265	130	49.06	98	36.98	37	13.96
8	कबीरधाम	166	149	89.76	17	10.24	0	0.00
9	राजनांदगांव	320	40	12.50	220	68.75	60	18.75
10	दुर्ग	223	203	91.03	12	5.38	8	3.59
11	रायपुर	716	643	89.80	55	7.68	18	2.51
12	महासमुंद	369	315	85.37	38	10.30	16	4.34
13	धमतरी	326	231	70.86	77	23.62	18	5.52
14	उ.ब.कांकेर	112	60	53.57	31	27.68	21	18.75
15	बस्तर+नारायणपुर	180	128	71.11	35	19.44	17	9.44
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7	7	100.00	0	0.00	0	0.00
<b>योग</b>		<b>3926</b>	<b>2881</b>	<b>73.38</b>	<b>770</b>	<b>19.61</b>	<b>275</b>	<b>7.01</b>



### चित्र क्रमांक- 9

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार क्रियाकलाप/प्रयोजनों की संख्या के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं की संख्या







### अध्याय-11

### संस्थाओं का क्षेत्र जिसमें वे सेवारत है (शासकीय/उद्योग/गृहकार्य), के अनुसार वर्गीकरण

सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के दौरान पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं को उनके क्षेत्र अर्थात् शासकीय/उद्योग/गृहकार्य, जिसमें वे सेवारत हैं, के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। कुल 3926 संस्थाओं में से 2104 संस्थाएं घरेलू गृहकार्य क्षेत्र में कार्यरत पायी गईं, जो कि कुल संस्थाओं का 53.59% है, 459 (11.69%) संस्थाएं शासकीय क्षेत्र में तथा 551 (14.04%) संस्थाएं उद्योग क्षेत्र में कार्यरत पायी गईं। 812 (20.68%) संस्थाओं के क्षेत्र के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी।

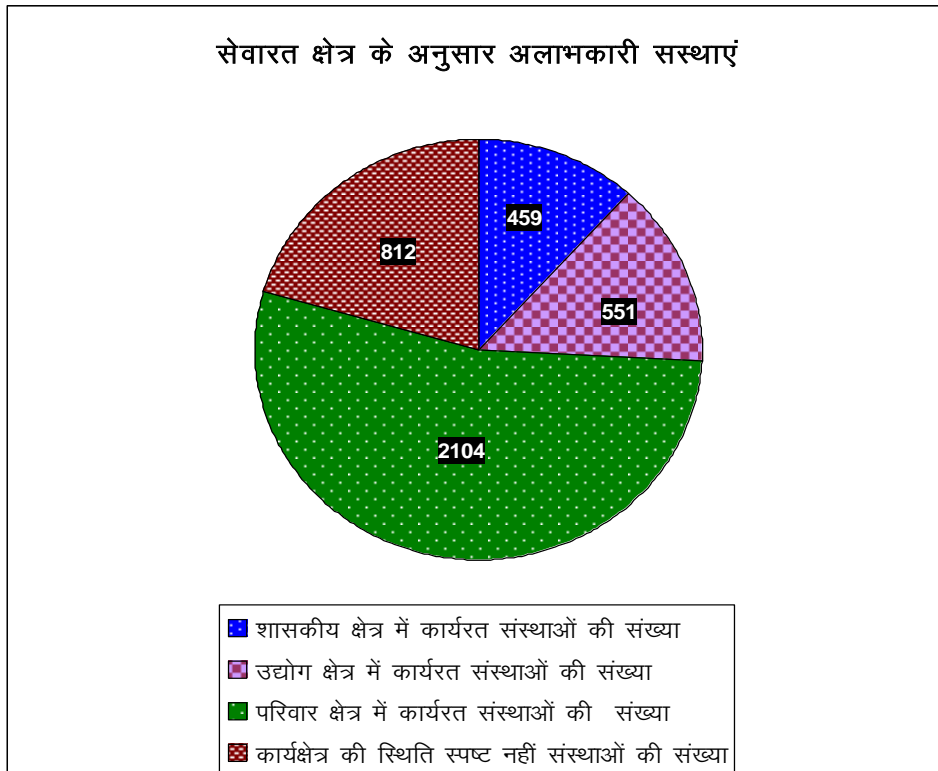
जिलेवार संस्थाओं के सर्वेक्षण में पाया गया कि अनुपातिक रूप से शासकीय क्षेत्र में कार्यरत सर्वाधिक संस्थाएं कोरबा जिले में 51.74% जबकि सबसे कम दुर्ग जिले में 0.45% में पायी गईं। उद्योग क्षेत्र में कार्यरत सर्वाधिक संस्थाएं कवर्धा जिले में 98.80% तथा सबसे कम राजनांदगांव जिले में 0.30% पायी गईं। घरेलू गृहकार्य क्षेत्र में कार्यरत सर्वाधिक संस्थाएं 91.88% राजनांदगांव जिले में तथा सबसे कम जशपुर जिले में 3.66% पायी गईं।

#### तालिका क्र.-9

#### संस्थाओं का क्षेत्र जिसमें वे सेवारत हैं, का प्रतिशत के अनुसार वितरण

शासकीय क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की संख्या	उद्योग क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की संख्या	परिवार क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की संख्या	कार्यक्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं संस्थाओं की संख्या
459	551	2104	812

#### चित्र क्र. -10





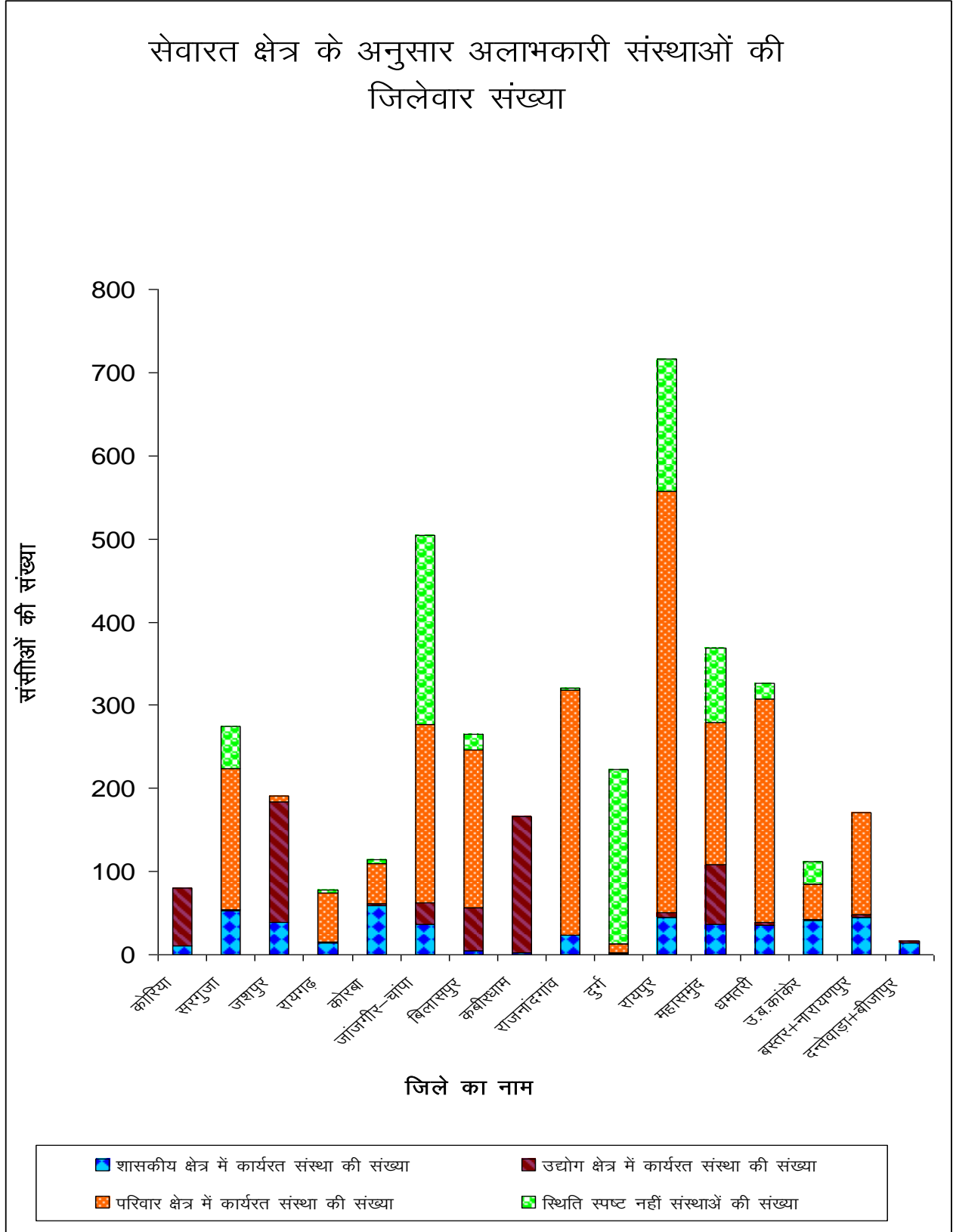
**तालिका क्रमांक-10**  
**कार्यक्षेत्र के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं की संख्या एवं प्रतिशत**

क्र.	जिलों के नाम	क्षेत्र जिसके सेवार्थ संस्था कार्यरत है								योग
		शासकीय क्षेत्र में कार्यरत संस्था		उद्योग क्षेत्र में कार्यरत संस्था		परिवार क्षेत्र में कार्यरत संस्था		स्थिति स्पष्ट नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	कोरिया	11	13.75	69	86.25	0	0	0	0	80
2	सरगुजा	53	19.27	1	0.36	170	61.82	51	18.55	275
3	जशपुर	39	20.42	145	75.92	7	3.66	0	0.00	191
4	रायगढ़	14	17.95	1	1.28	59	75.64	4	5.13	78
5	कोरबा	59	51.75	2	1.75	48	42.11	5	4.39	114
6	जांजगीर-चांपा	36	7.14	27	5.36	214	42.46	227	45.04	504
7	बिलासपुर	5	1.89	52	19.62	189	71.32	19	7.17	265
8	कबीरधाम	2	1.20	164	98.80	0	0.00	0	0.00	166
9	राजनांदगांव	23	7.19	1	0.31	294	91.88	2	0.63	320
10	दुर्ग	1	0.45	1	0.45	11	4.93	210	94.17	223
11	रायपुर	45	6.28	6	0.84	506	70.67	159	22.21	716
12	महासमुंद	36	9.76	72	19.51	171	46.34	90	24.39	369
13	धमतरी	35	10.74	4	1.23	269	82.52	18	5.52	326
14	उ.ब.कांकेर	41	36.61	1	0.89	43	38.39	27	24.11	112
15	बस्तर+नारायणपुर	52	28.88	5	2.77	123	68.35	0	0.00	180
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7
<b>योग</b>		<b>459</b>		<b>551</b>		<b>2104</b>		<b>812</b>		<b>3926</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>11.69</b>		<b>14.04</b>		<b>53.59</b>		<b>20.68</b>		<b>100</b>





चित्र क्रमांक- 11  
सेवारत क्षेत्र के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं की जिलेवार संख्या





## अध्याय-12

### छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में प्रबंधन समिति के सदस्यों का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में खोजी गई संस्था के प्रबंधन मंडल में सदस्यों की संख्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई । कुल संस्थाओं के प्रबंधन मंडल में पुरुषों की संख्या का प्रतिशत 52.97% तथा महिलाओं का प्रतिशत 47.03% पाया गया। सर्वाधिक 3001 पुरुष प्रबंधक रायपुर जिले में तथा सर्वाधिक 5090 महिला प्रबंधक भी रायपुर जिले में पाए गए। जिलों में अनुपातिक रूप से प्रबंधन समिति में सर्वाधिक पुरुष सदस्य 1420 (80.36%) जशपुर जिले में तथा प्रबंधन समिति में सर्वाधिक महिला सदस्य 2655 (64.22% ) जाजंगीर-चांपा जिले में पाए गए।

#### तालिका क्रमांक-11

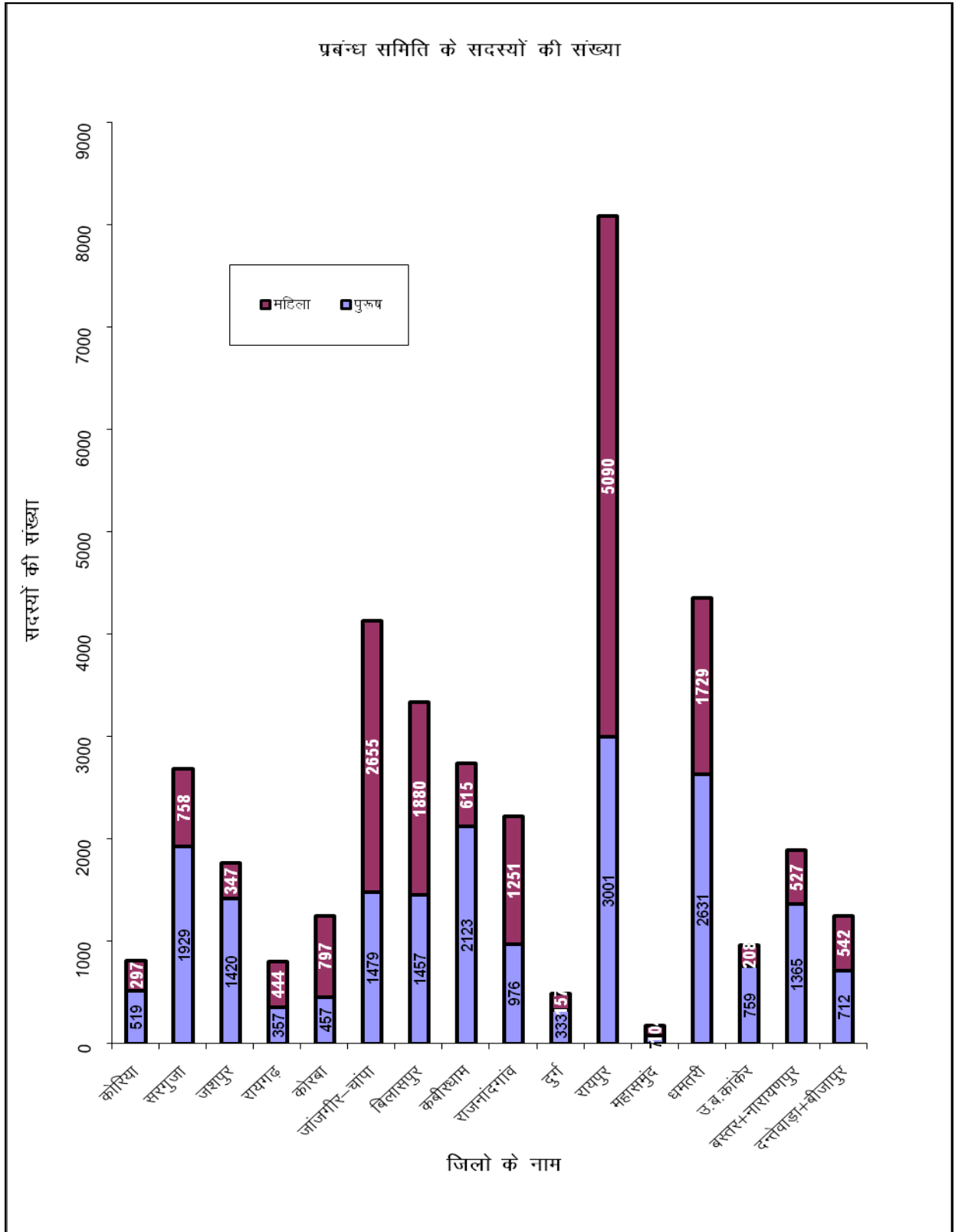
#### अलाभकारी संस्थाओं में प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या एवं प्रतिशत

क्र.	जिलों के नाम	प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या वर्गवार				कुल सदस्यों की संख्या
		पुरुषों की		महिलाओं की		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	कोरिया	519	63.6	297	36.39	816
2	सरगुजा	1929	71.79	758	28.2	2687
3	जशपुर	1420	80.36	347	19.63	1767
4	रायगढ़	357	44.56	444	55.43	801
5	कोरबा	457	36.44	797	63.55	1254
6	जाजंगीर-चांपा	1479	35.77	2655	64.22	4134
7	बिलासपुर	1457	43.66	1880	56.33	3337
8	कबीरधाम	2123	77.53	615	22.46	2738
9	राजनांदगांव	976	43.82	1251	56.17	2227
10	दुर्ग	333	67.95	157	32.04	490
11	रायपुर	3001	37.09	5090	62.9	8091
12	महासमुंद	78	42.85	104	57.14	182
13	धमतरी	2631	60.34	1729	39.65	4360
14	उ.ब.कांकेर	759	78.49	208	21.5	967
15	बस्तर+नारायणपुर	1365	72.14	527	27.85	1892
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	712	56.77	542	43.22	1254
<b>योग</b>		<b>19596</b>	<b>52.97</b>	<b>17401</b>	<b>47.03</b>	<b>36997</b>



सत्यमेव जयते

चित्र क्रमांक- 12  
अलाभकारी संस्थाओं में प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या एवं प्रतिशत





### अध्याय-13

## छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं का लेखा विवरण

प्रदेश सर्वेक्षित, कुल 3926 पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के लेखा संबंधी जानकारी में पाया गया कि कुल 765 (19.5%) संस्थाओं का लेखा तैयार एवं उपलब्ध है, जबकि कुल 675 (17%) संस्थाओं के लेखे तैयार किन्तु उपलब्ध नहीं पाये गये। साथ ही 2197 (56%) संस्थाओं के लेखे तैयार नहीं हैं तथा 289 (7.4%) संस्थाओं के लेखों के विषय में जानकारी ही प्राप्त नहीं हो पाई। लेखा उपलब्धता का सर्वाधिक प्रतिशत जशपुर जिले में 71.73% एवं सबसे कम 2.98% जांजगीर-चांपा जिले में पाया गया।

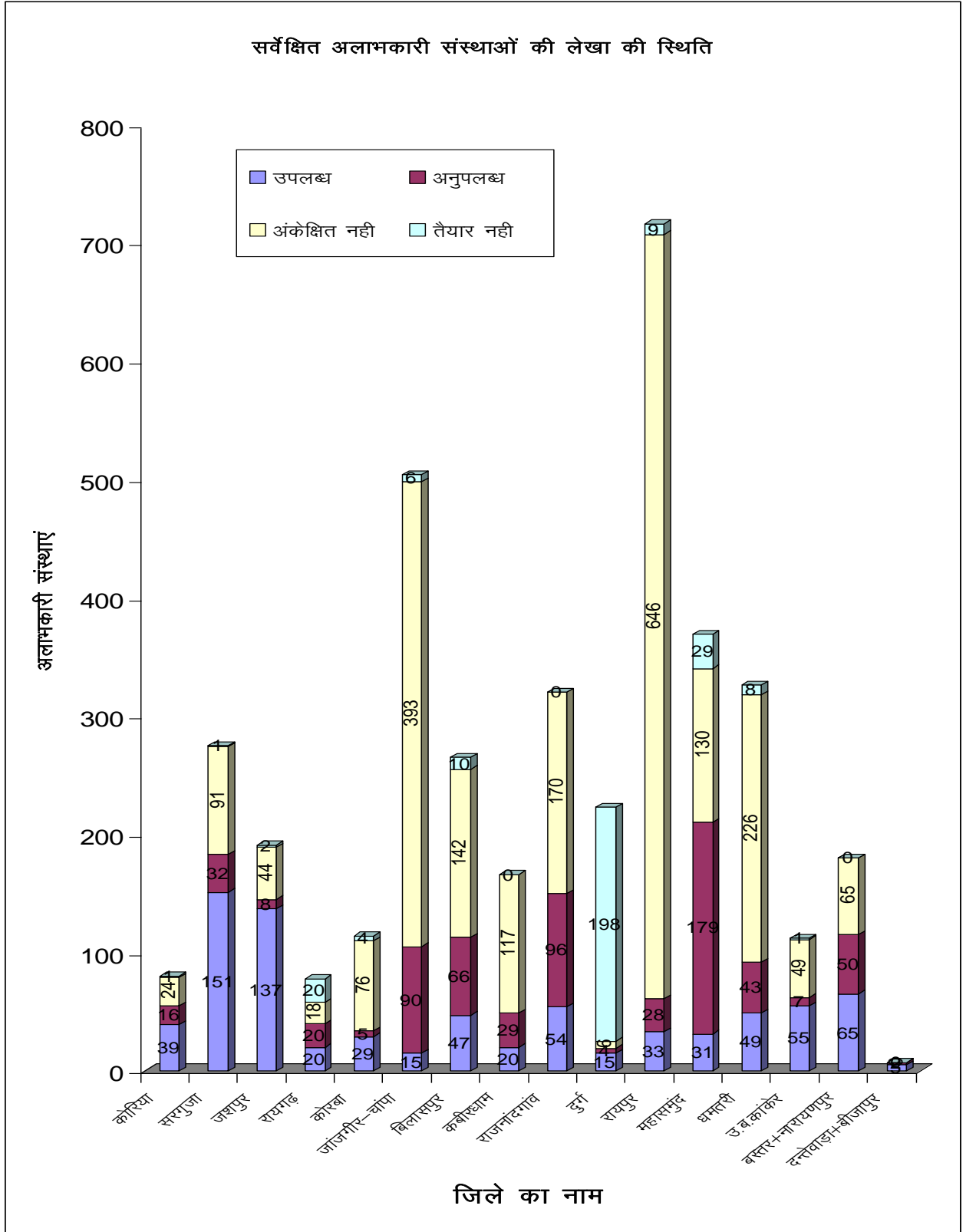
### तालिका क्रमांक-12

#### सर्वेक्षित अलाभकारी संस्थाओं की लेखा की स्थिति

क्र.	जिलों के नाम	लेखा तैयार एवं उपलब्ध		लेखा तैयार एवं अनुपलब्ध		लेखा उपलब्ध किन्तु अंकेक्षित नहीं		लेखा तैयार नहीं		योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	कोरिया	39	48.75	16	20	24	30	1	1.25	80
2	सरगुजा	151	54.91	32	11.64	91	33.09	1	0.36	275
3	जशपुर	137	71.73	8	4.19	44	23.04	2	1.05	191
4	रायगढ़	20	25.64	20	25.64	18	23.08	20	25.64	78
5	कोरबा	29	25.44	5	4.39	76	66.67	4	3.51	114
6	जांजगीर-चांपा	15	2.98	90	17.86	393	77.98	6	1.19	504
7	बिलासपुर	47	17.74	66	24.91	142	53.58	10	3.77	265
8	कबीरधाम	20	12.05	29	17.47	117	70.48	0	0.00	166
9	राजनांदगांव	54	16.88	96	30.00	170	53.13	0	0.00	320
10	दुर्ग	15	6.73	4	1.79	6	2.69	198	88.79	223
11	रायपुर	33	4.61	28	3.91	646	90.22	9	1.26	716
12	महासमुंद	31	8.40	179	48.51	130	35.23	29	7.86	369
13	धमतरी	49	15.03	43	13.19	226	69.33	8	2.45	326
14	उ.ब.कांकेर	55	49.11	7	6.25	49	43.75	1	0.89	112
15	बस्तर+नारायणपुर	65	36.12	50	27.76	65	36.12	0	0.00	180
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	5	71.42	2	28.58	0	0.00	0	0.00	7
<b>योग</b>		<b>765</b>	<b>19.49</b>	<b>675</b>	<b>17.19</b>	<b>2197</b>	<b>55.96</b>	<b>289</b>	<b>7.36</b>	<b>3926</b>



चित्र क्रमांक- 13  
सर्वेक्षित अलाभकारी संस्थाओं की लेखा की स्थिति







#### अध्याय-14

### छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं में स्वयं सेवकों की संख्या (प्रबन्ध समिति के सदस्यों सहित)

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में संस्था के स्वयं सेवकों की संख्या, प्रबन्ध समिति के सदस्यों सहित विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई। दो प्रकार के सदस्यों का उल्लेख है, मानदेय सहित एवं मानदेय रहित। कुल संस्थाओं में संलग्न स्वयं सेवकों की संख्या 14622 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 9754 (66.71%) एवं महिलाओं की संख्या 4868 (33.29%) है। मानदेय सहित स्वयं सेवकों की संख्या 2173 (14.86%) है जिसमें पुरुषों की संख्या 1344 (9.19%) एवं महिलाओं की संख्या 829 (5.67%) है। मानदेय रहित स्वयं सेवकों की संख्या 12449 (85.14%) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 8410 (57.52%) एवं महिलाओं की संख्या 4039 (27.62%) है। सर्वाधिक पुरुष स्वयं सेवक 3919 बस्तर+ नारायणपुर जिले में तथा सर्वाधिक 1468 महिला स्वयं सेवक भी बस्तर+नारायणपुर जिले में पाए गए।

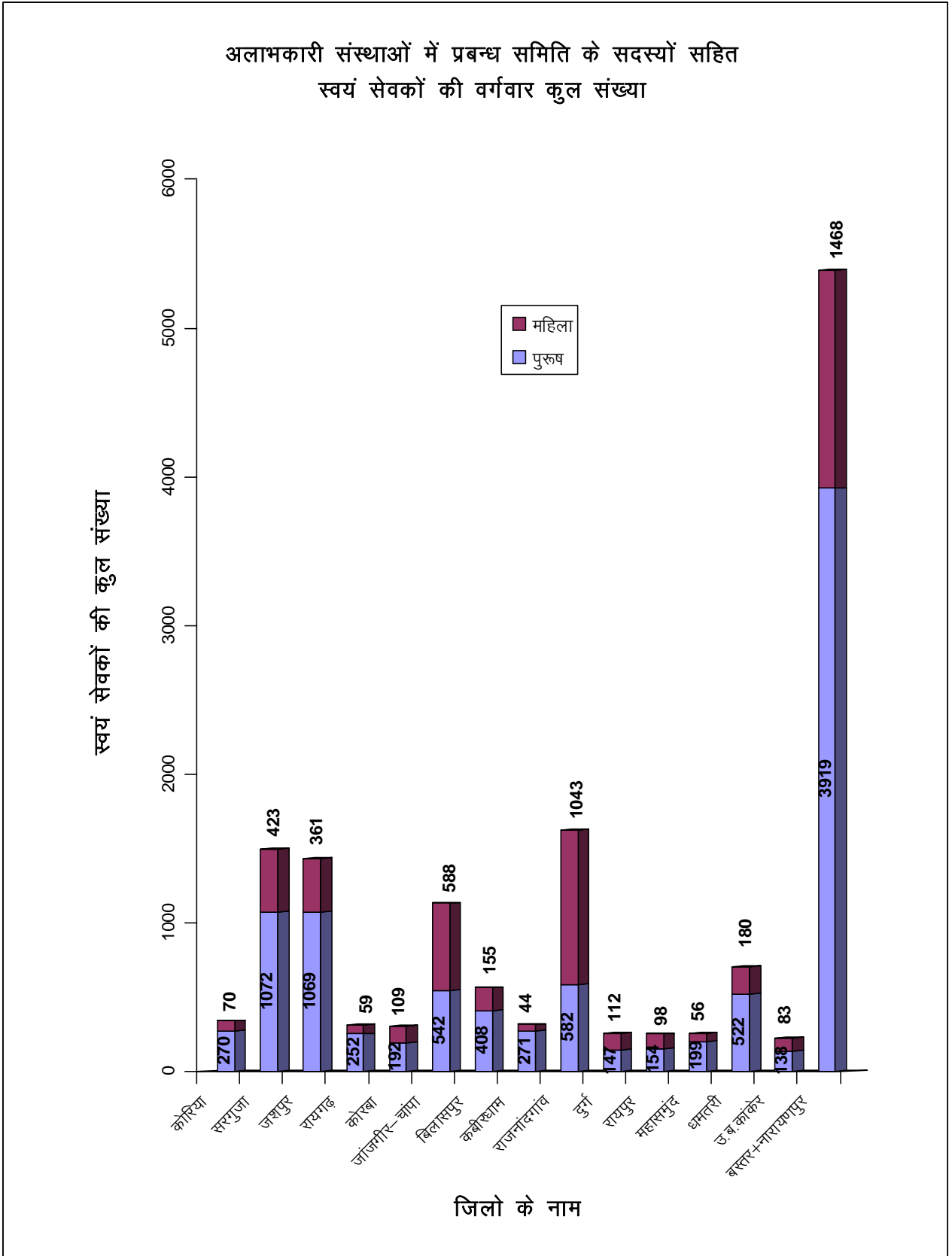
#### तालिका क्रमांक-13

### छत्तीसगढ़ राज्य में खोजी गई अलाभकारी संस्थाओं में स्वयं सेवकों की जिलेवार संख्या (प्रबन्ध समिति के सदस्यों सहित)

क्र.	जिलों के नाम	स्वयं सेवकों की संख्या (प्रबन्ध समिति के सदस्यों सहित)								
		मानदेय सहित			मानदेय रहित			योग		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	कोरिया	27	14	41	243	56	299	270	70	340
2	सरगुजा	236	115	351	836	308	1144	1072	423	1495
3	जशपुर	241	147	388	828	214	1042	1069	361	1430
4	रायगढ़	79	16	95	173	43	216	252	59	311
5	कोरबा	42	28	70	150	81	231	192	109	301
6	जांजगीर-चांपा	30	52	82	512	536	1048	542	588	1130
7	बिलासपुर	57	32	89	351	123	474	408	155	563
8	कबीरधाम	195	32	227	76	12	88	271	44	315
9	राजनांदगांव	75	63	138	524	999	1523	599	1062	1661
10	दुर्ग	8	61	69	139	51	190	147	112	259
11	रायपुर	39	28	67	115	70	185	154	98	252
12	महासमुंद	16	9	25	183	47	230	199	56	255
13	धमतरी	163	104	267	359	76	435	522	180	702
14	उ.ब.कांकेर	30	53	83	108	30	138	138	83	221
15	बस्तर+नारायणपुर	106	75	181	3813	1393	5206	3919	1468	5387
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर					N.A.				
	<b>योग</b>	<b>1344</b>	<b>829</b>	<b>2173</b>	<b>8410</b>	<b>4039</b>	<b>12449</b>	<b>9754</b>	<b>4868</b>	<b>14622</b>
	<b>प्रतिशत</b>	<b>9.19</b>	<b>5.67</b>	<b>14.86</b>	<b>57.52</b>	<b>27.62</b>	<b>85.14</b>	<b>66.71</b>	<b>33.29</b>	<b>100.00</b>



चित्र क्रमांक- 14  
जिलेवार स्वयं सेवकों की कुल संख्या

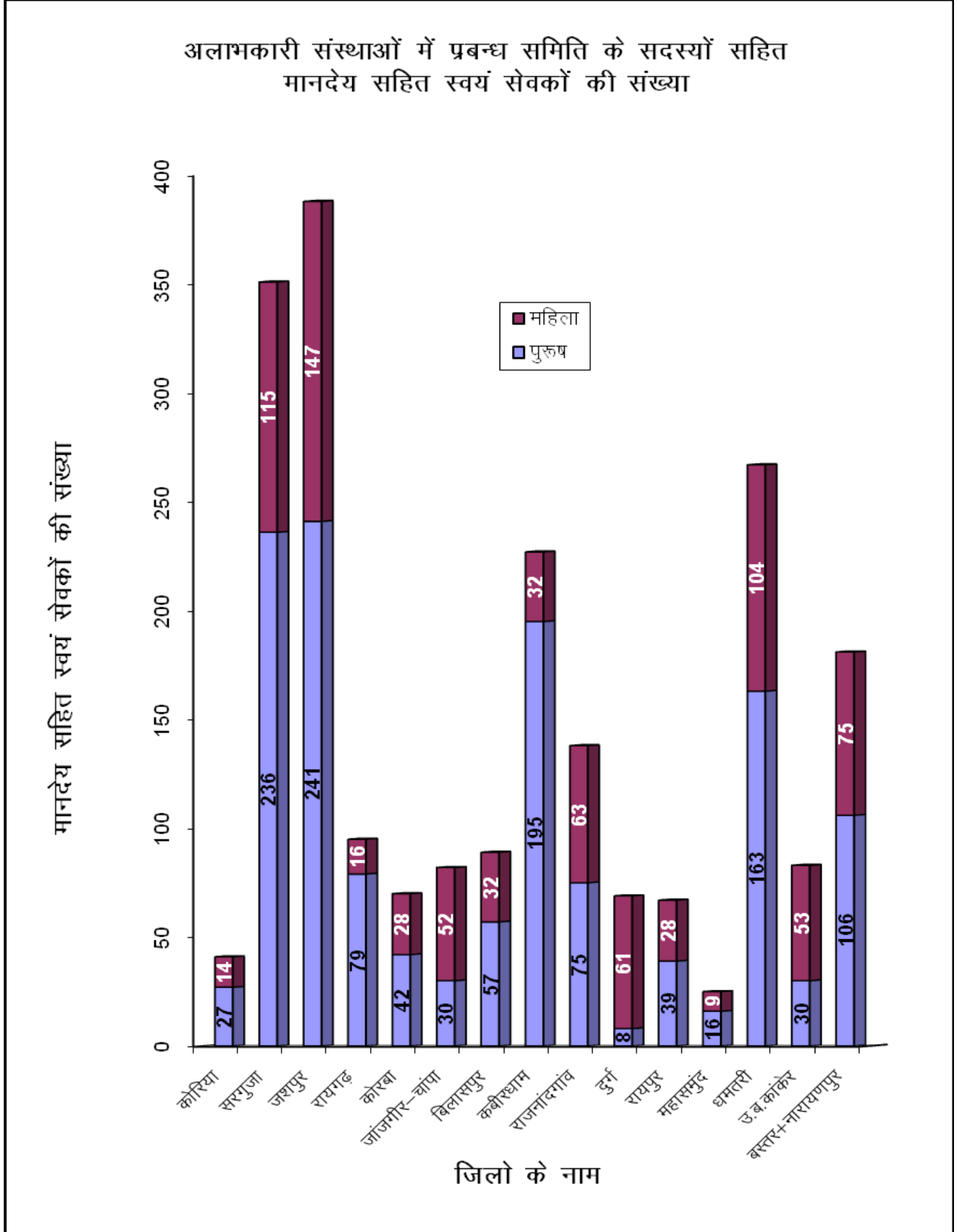






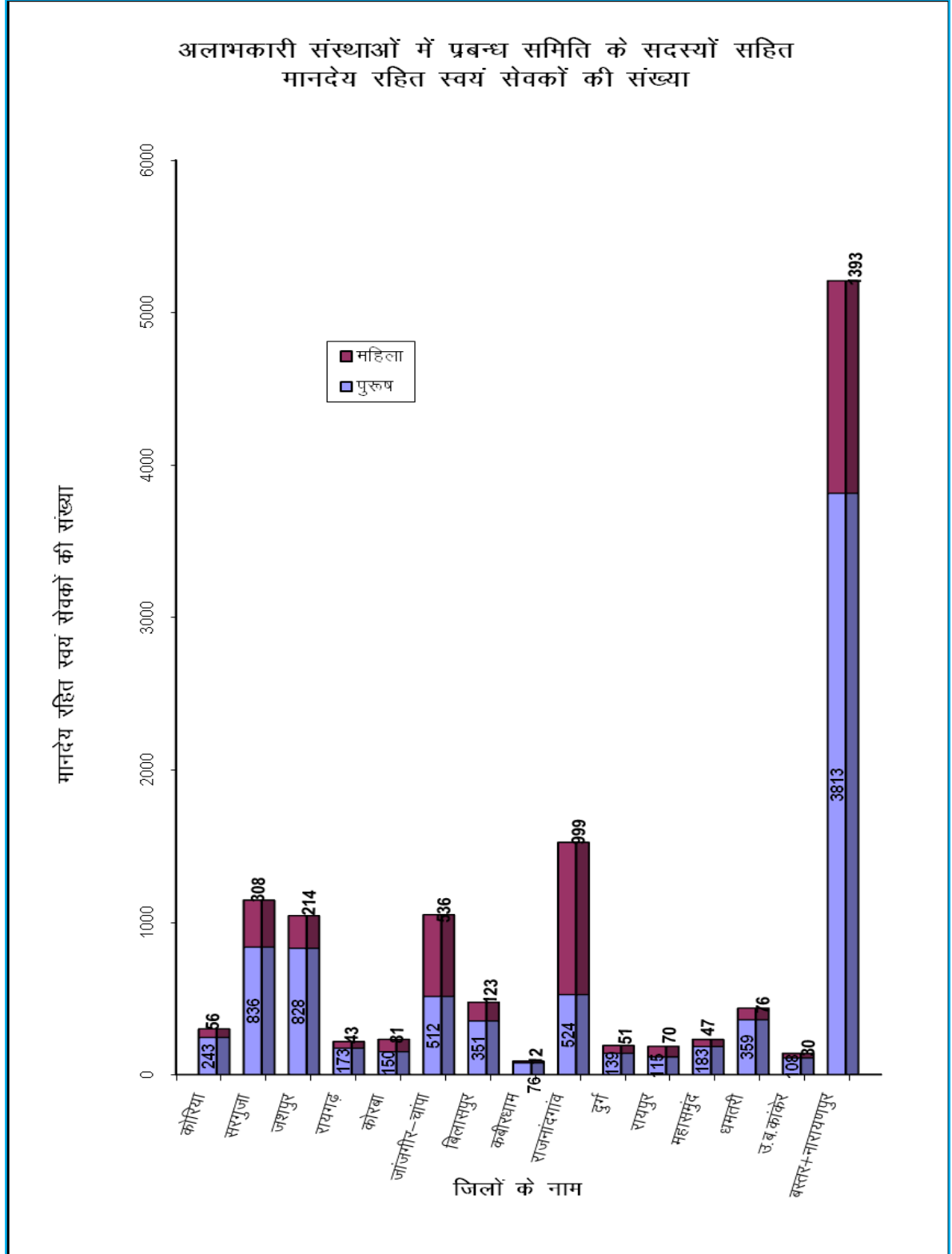


चित्र क्रमांक-15  
जिलेवार मानदेय सहित स्वयं सेवकों की संख्या





चित्र क्रमांक-16  
जिलेवार मानदेय रहित स्वयं सेवकों की संख्या







## अध्याय 15

### छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण अनुसार मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों (पूर्णकालिक/अल्पकालिक) का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में संस्था के मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई। दो प्रकार के सदस्यों का उल्लेख है, पूर्णकालिक एवं अल्पकालिक कर्मचारी। कुल संस्थाओं में संलग्न मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 8968 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4419 (49.27%) एवं महिलाओं की संख्या 4549 (50.73%) पाई गई है। पूर्णकालिक कर्मचारी की संख्या 5524 (61.59%) है जिसमें पुरुषों की संख्या 3068 (34.21%) एवं महिलाओं की संख्या 2456 (27.38%) पाई गई है। अल्पकालिक कर्मचारी की संख्या 3444 (38.40%) है जिसमें पुरुषों की संख्या 1351 (15.07%) एवं महिलाओं की संख्या 2093 (23.33%) पाई गई है। सर्वाधिक पुरुष कर्मचारी 1418 नारायणपुर सहित बस्तर जिले में तथा सर्वाधिक महिला कर्मचारी 1096 भी बस्तर +नारायणपुर जिले में पाए गए।

#### तालिका क्रमांक-14

#### मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या का विवरण

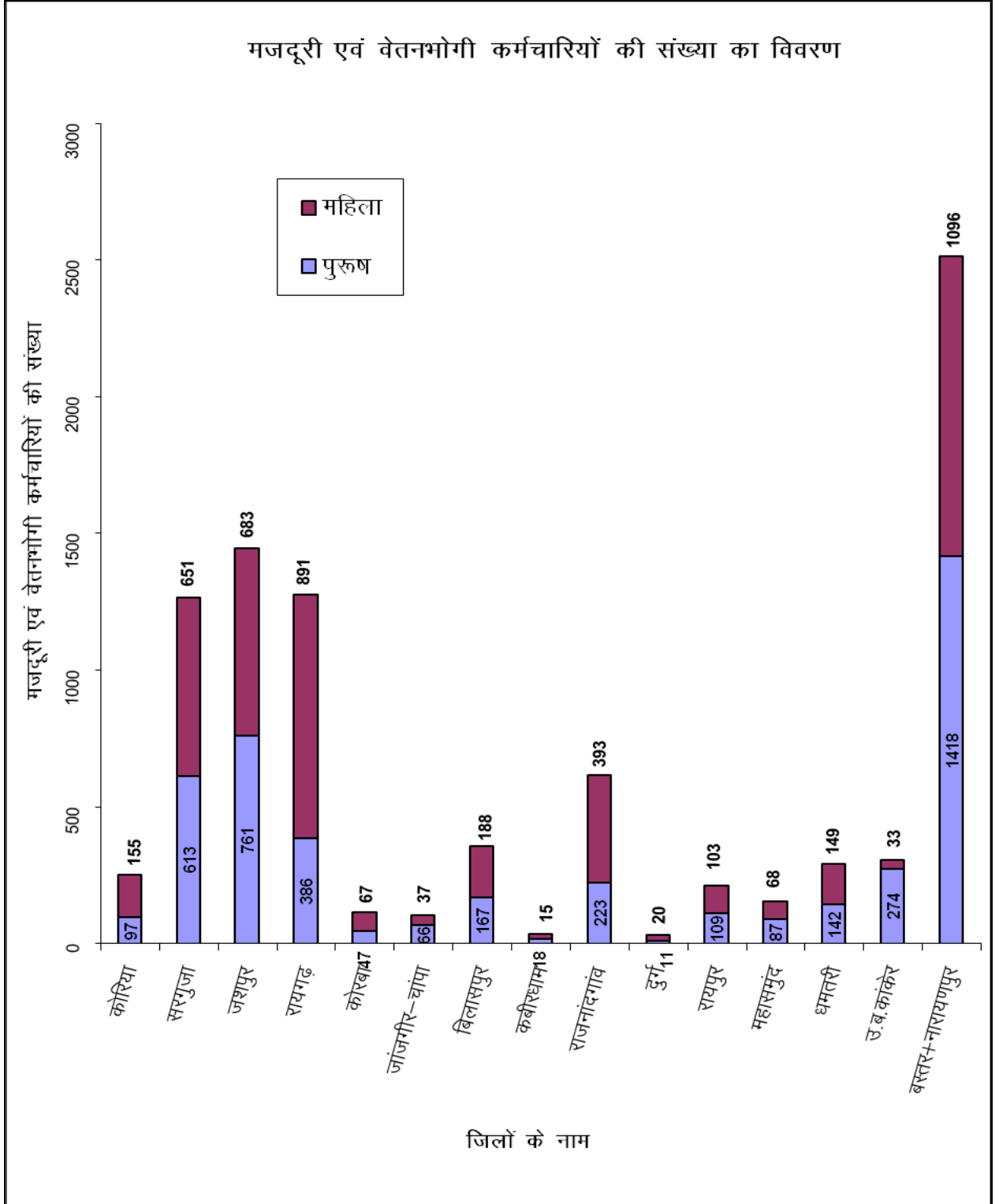
क्र.	जिलों के नाम	मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या का विवरण								
		पूर्णकालिक			अल्पकालिक			योग		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	कोरिया	67	128	195	30	27	57	97	155	252
2	सरगुजा	323	306	629	290	345	635	613	651	1264
3	जशपुर	619	537	1156	142	146	288	761	683	1444
4	रायगढ़	100	68	168	286	823	1109	386	891	1277
5	कोरबा	30	55	85	17	12	29	47	67	114
6	जांजगीर-चांपा	22	7	29	44	30	74	66	37	103
7	बिलासपुर	27	26	53	140	162	302	167	188	355
8	कबीरधाम	13	4	17	5	11	16	18	15	33
9	राजनांदगांव	71	90	161	152	303	455	223	393	616
10	दुर्ग	6	15	21	5	5	10	11	20	31
11	रायपुर	105	94	199	4	9	13	109	103	212
12	महासमुंद	50	32	82	37	36	73	87	68	155
13	धमतरी	45	20	65	97	129	226	142	149	291
14	उ.ब.कांकेर	266	28	294	8	5	13	274	33	307
15	बस्तर+नारायणपुर	1324	1046	2370	94	50	144	1418	1096	2514
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर				N.A.					
	<b>योग</b>	<b>3068</b>	<b>2456</b>	<b>5524</b>	<b>1351</b>	<b>2093</b>	<b>3444</b>	<b>4419</b>	<b>4549</b>	<b>8968</b>





### चित्र क्रमांक-17

सभी पूर्णकालिक एवं अल्पकालिक मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की जिलेवार कुल संख्या का विवरण

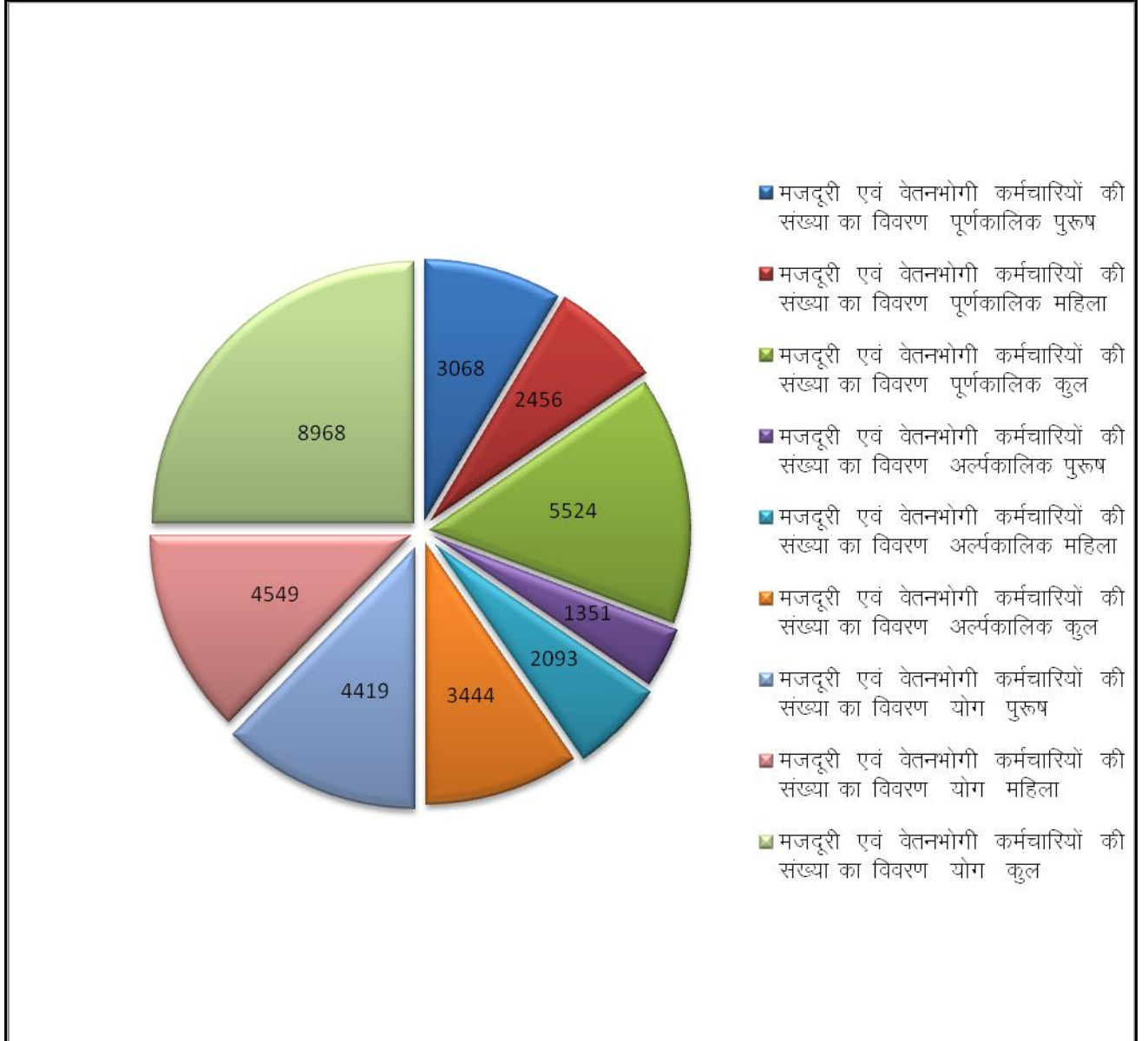








**चित्र क्रमांक-18**  
**सभी मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या**



**तालिका क्र.-15**  
**मजदूरी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या का विवरण**

पूर्णकालिक			अल्पकालिक			योग		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
3068	2456	5524	1351	2093	3444	4419	4549	8968
34.21	27.38	61.60	15.06	23.33	38.40	49.28	50.72	100



## अध्याय-16

### छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण अनुसार संलग्न कुल सदस्यों की संख्या का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में संस्था के कुल सदस्यों की संख्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई । संस्था में कुल सदस्यों की संख्या 23582 है, जिसमें कई प्रकार के सदस्यों का उल्लेख है, यथा पूर्णकालिक एवं अल्पकालिक कर्मचारी, मजदूर, वेतनभोगी, प्रबंध समिति के सदस्य, मानदेय सहित, मानदेय रहित इत्यादी। संस्थाओं में संलग्न कुल सदस्यों की संख्या 23582 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 14173 (60.91%) एवं महिलाओं की संख्या 9409 (39.89%) है। प्रबंध समिति में मानदेय सहित स्वयं सेवकों का प्रतिशत 9.21 तथा मानदेय रहित स्वयं सेवकों का प्रतिशत 52.79 पाया गया । सर्वाधिक पुरुष कर्मचारी 5337 बस्तर+नारायणपुर जिले में तथा सर्वाधिक महिला कर्मचारी 2564 बस्तर+नारायणपुर जिले में पाये गये । जबकि दुर्ग जिले में सबसे कम 158 कर्मचारी पुरुष तथा कबीरधाम जिले में सबसे कम 59 महिला कर्मचारी प्रबंध समिति में पाये गये ।

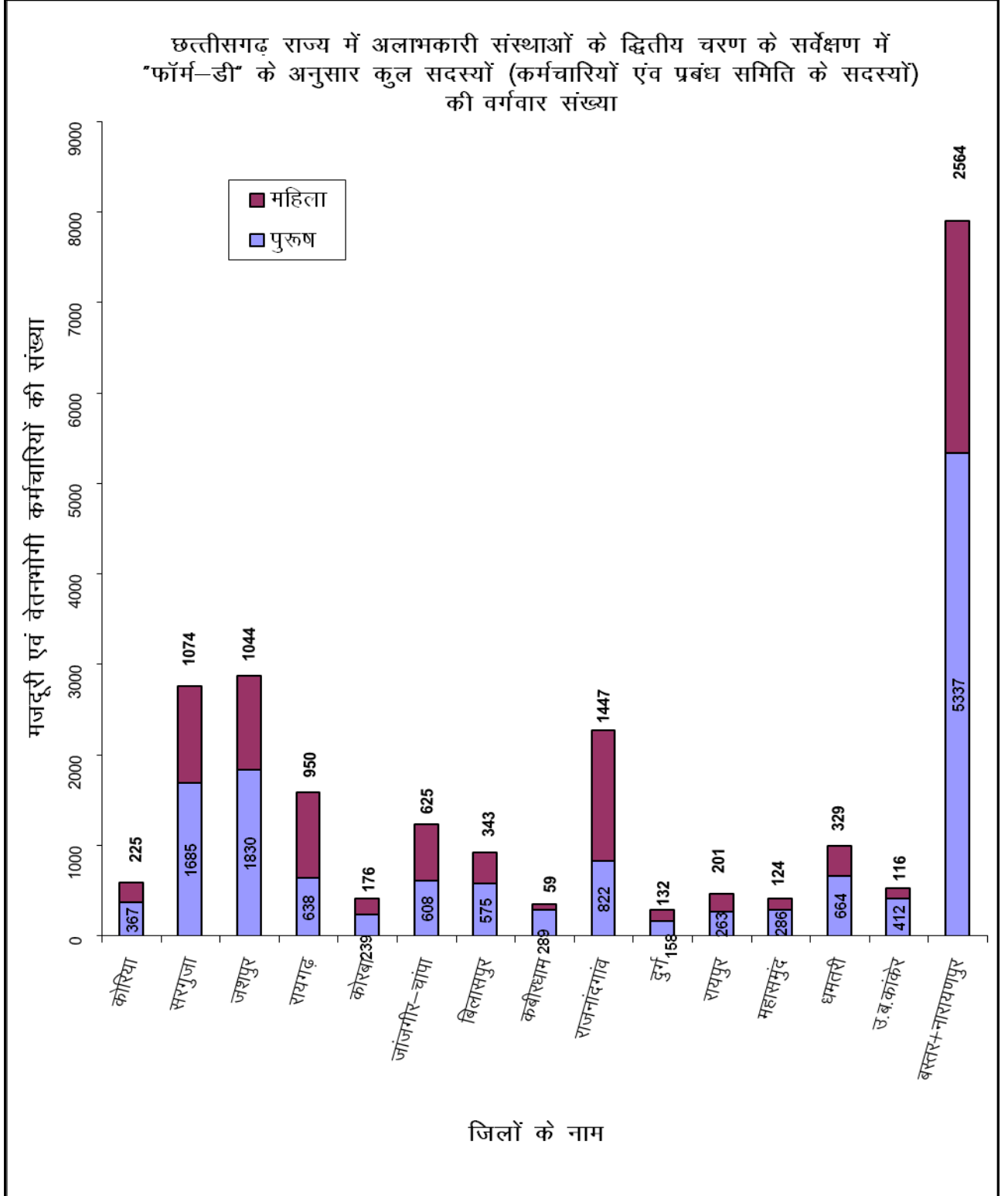
### तालिका क्रमांक-16

#### छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में कुल सदस्यों की वर्गवार संख्या

क्र.	जिलों के नाम	पुरुष	महिला	कुल
1	कोरिया	367	225	592
2	सरगुजा	1685	1074	2759
3	जशपुर	1830	1044	2874
4	रायगढ़	638	950	1588
5	कोरबा	239	176	415
6	जांजगीर-चांपा	608	625	1233
7	बिलासपुर	575	343	918
8	कबीरधाम	289	59	348
9	राजनांदगांव	822	1447	2269
10	दुर्ग	158	132	290
11	रायपुर	263	201	464
12	महासमुंद	286	124	410
13	धमतरी	664	329	993
14	उ.ब.कांकेर	412	116	528
15	बस्तर+नारायणपुर	5337	2564	7901
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	NA		
<b>योग</b>		<b>14173</b>	<b>9409</b>	<b>23582</b>



चित्र क्रमांक-19  
छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में  
कुल सदस्यों की जिलेवार (महिला/पुरुष) संख्या





## अध्याय-17

### छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण अनुसार संलग्न कुल सदस्यों की संख्या में विशेषज्ञों की संख्या

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में संस्था के कुल सदस्यों की संख्या में विशेषज्ञ जैसे डाक्टर, वकील, शिक्षक के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई। संस्था में कुल सदस्यों की संख्या 23582 है, जिसमें चिकित्सकों की संख्या 494 है जिसमें पुरुष चिकित्सकों की संख्या 399 एवं महिला चिकित्सकों की संख्या 95 पाई गई। वकीलों की संख्या 108 (0.50%) है जिसमें पुरुषों की संख्या 92 एवं महिलाओं की संख्या 16 है। शिक्षकों की संख्या 3729 है जिसमें पुरुषों की संख्या 1779 एवं महिलाएं 1950 है। इस तरह कुल विशेषज्ञों की संख्या 4331 है, जो कुल सदस्यों की संख्या 23582 की 18.4% है। सर्वाधिक चिकित्सकों की संख्या 209 सरगुजा जिले में, सर्वाधिक शिक्षकों की संख्या 679 बस्तर+नारायणपुर जिले में तथा सर्वाधिक अधिवक्ताओं की संख्या 18 कोरबा जिले में पाई गई हैं। नीचे दी गई तालिका में जिलेवार सर्वेक्षित अलाभकारी संस्थाओं में संलग्न विशेषज्ञों की संख्या का विवरण दर्शाया गया है।

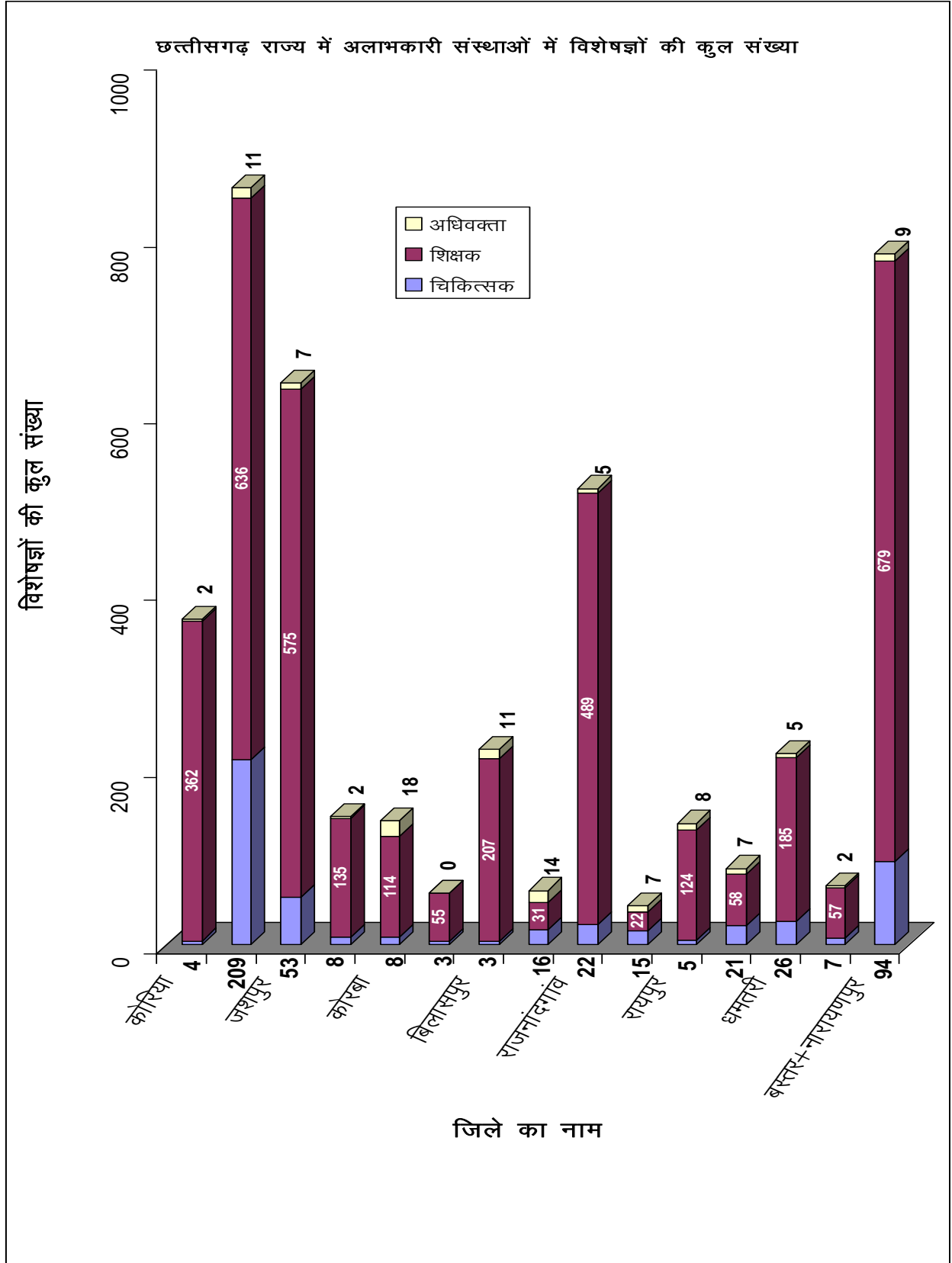
#### तालिका क्रमांक-17

### छत्तीसगढ़ राज्य में अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में कुल विशेषज्ञों की संख्या

क्र.	जिले का नाम	चिकित्सक			शिक्षक			अधिवक्ता		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	कोरिया	4	0	4	154	208	362	2	0	2
2	सरगुजा	168	41	209	270	366	636	10	1	11
3	जशपुर	48	5	53	355	220	575	7	0	7
4	रायगढ़	7	1	8	99	36	135	2	0	2
5	कोरबा	6	2	8	52	62	114	14	4	18
6	जांजगीर-चांपा	2	1	3	37	18	55	0	0	0
7	बिलासपुर	3	0	3	86	121	207	9	2	11
8	कबीरधाम	15	1	16	24	7	31	14	0	14
9	राजनांदगांव	13	9	22	150	339	489	5	0	5
10	दुर्ग	10	5	15	6	16	22	6	1	7
11	रायपुर	3	2	5	43	81	124	1	7	8
12	महासमुंद	15	6	21	34	24	58	7	0	7
13	धमतरी	22	4	26	95	90	185	4	1	5
14	उ.ब.कांकेर	6	1	7	30	27	57	2	0	2
15	बस्तर+नारायणपुर	77	17	94	344	335	679	9	0	9
योग		399	95	494	1779	1950	3729	92	16	108



चित्र क्रमांक-20  
अलाभकारी संस्थाओं में वर्गवार विशेषज्ञों की संख्या





## अध्याय 18

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के आय के स्रोत का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में संस्थाओं के आय संबंधी जानकारी भी प्राप्त की गई। सर्वे में पाया गया कि संस्थाओं के संचालन के लिए प्राप्त मुख्यतः दो प्रकार के अनुदानों का उल्लेख है :- चालू अनुदान एवं पूंजीगत अनुदान। पूंजीगत अनुदान में पुनः तीन प्रकार हैं, जैसे सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान, विदेशी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं अन्य से प्राप्त अनुदान। एकत्रित रूप में कुल 184130601 रु. का अनुदान प्राप्ति की जानकारी परिलक्षित हुई। सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान की धन राशि रु. 119037368 (64.64%), विदेशी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान की धन राशि रु. 19410470 (10.54%) तथा अन्य से प्राप्त अनुदान की धन राशि रु. 45682763 (24.80%) के प्राप्ति जानकारी एकत्र की गई। सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों में सर्वाधिक धन राशि बस्तर जिले की संस्थाओं को रु. 89317413 एवं न्यूनतम जांजगीर-चांपा जिले को रु. 11285 प्राप्त हुई है। विदेशी संस्थाओं से केवल चार जिलों अलाभकारी संस्थाओं को ही अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें सर्वाधिक बस्तर जिले की अलाभकारी संस्थाओं को प्राप्त राशि रु. 19149160 एवं न्यूनतम कांकेर जिले को 4680 प्राप्त हुआ है। अन्य अनुदानों में सर्वाधिक जशपुर जिले को प्राप्त अनुदान राशि रु. 28569820 एवं न्यूनतम कोरिया जिले की संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि रु. 29500 की जानकारी प्राप्त हुई है। नीचे दी गई तालिका में अलाभकारी संस्थाओं को प्राप्त अनुदानों का विस्तृत विवरण है।

#### तालिका क्रमांक -18

#### अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण, अनुसूची का संकलित प्रतिवेदन पूंजीगत अनुदान

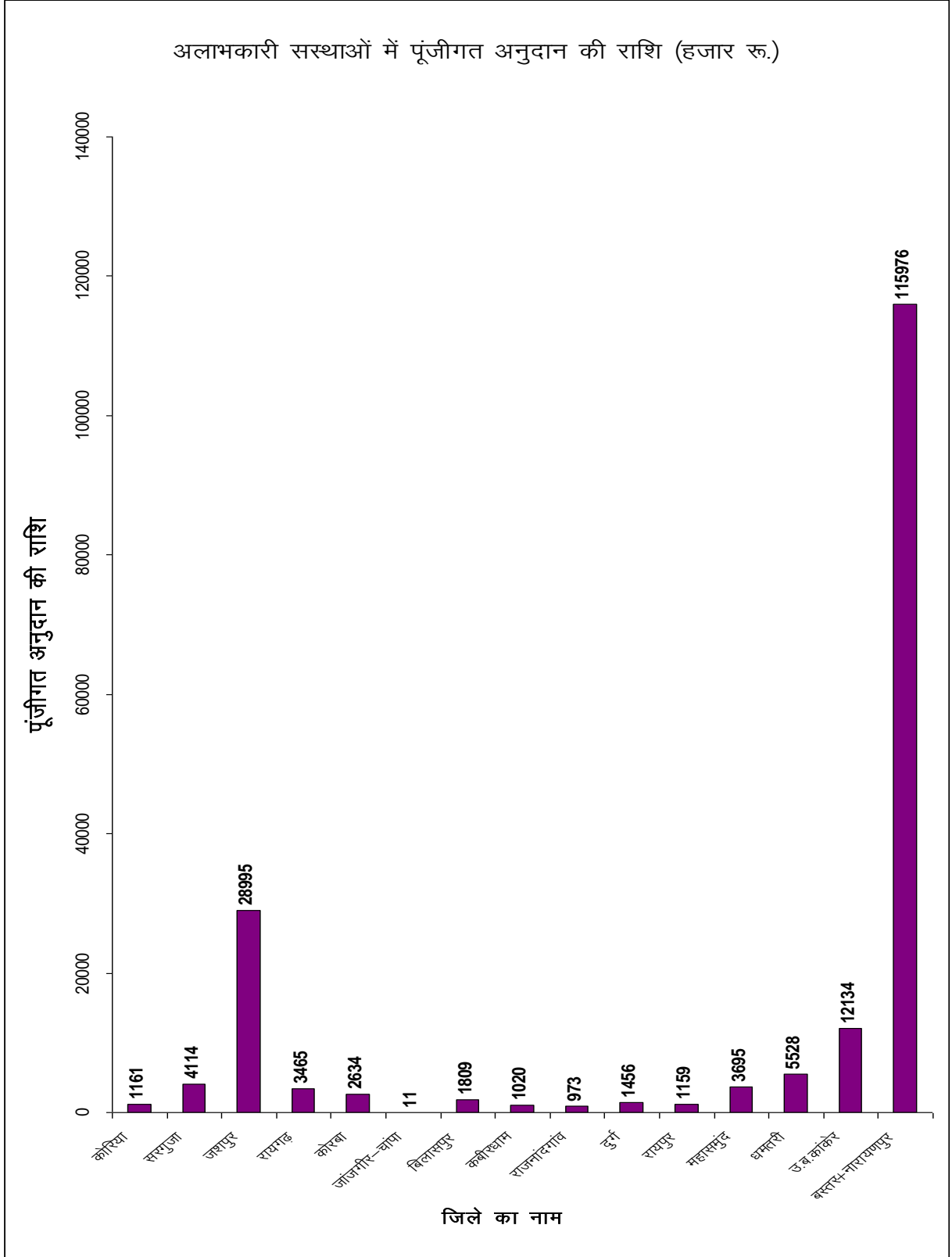
क्र.	जिलों के नाम	कुल खोजी गई पंजीकृत संस्थाएं	सरकारी संस्थाओं से	विदेशी संस्थाओं से	अन्य से	कुल पूंजीगत अनुदान (रु. में)	कुल पूंजीगत अनुदान (रु. हजार में)	प्रति संस्था औसत पूंजीगत अनुदान
1	कोरिया	80	1131175	0	29500	1160675	1161	14508.44
2	सरगुजा	275	3817118	228280	68495	4113893	4114	14959.61
3	जशपुर	191	425000	0	28569820	28994820	28995	151805.34
4	रायगढ़	78	3399892	0	64757	3464649	3465	44418.58
5	कोरबा	114	95000	0	2539067	2634067	2634	23105.85
6	जांजगीर-चांपा	504	11285	0	0	11285	11	22.29
7	बिलासपुर	265	668629	0	1140742	1809371	1809	6827.82
8	कबीरधाम	166	165256	0	854986	1020242	1020	6146.04
9	राजनांदगांव	320	823000	0	150000	973000	973	3040.63
10	दुर्ग	223	1456045	0	0	1456045	1456	6529.35
11	रायपुर	716	1095032	0	64250	1159282	1159	1619.11
12	महासमुंद्र	369	1045296	0	2649239	3694535	3695	10012.29
13	धमतरी	326	5000000	28350	500000	5528350	5528	16958.13
14	उ.ब.कांकेर	112	10587227	4680	1542065	12133972	12134	108339.04
15	बस्तर+नारायणपुर	180	89317413	19149160	7509842	115976415	115976	644313.42
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7			N.A.			0.00



योग	3926	119037368	19410470	45682763	184130601	184131	46900.31
-----	------	-----------	----------	----------	-----------	--------	----------



चित्र क्रमांक-21  
अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल पूजीगत अनुदान (रु.हजार में)







**तालिका क्रमांक-19**  
**अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल चालू अनुदान**

अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल चालू अनुदान (रु. हजार में)

क्र.	जिलों के नाम	कुल खोजी गई पंजीकृत संस्थाएं	सरकारी संस्थाओं से	विदेशी संस्थाओं से	अन्य से	कुल चालू अनुदान (रु. में)	कुल चालू अनुदान (रु. हजार में)	प्रति संस्था औसत चालू अनुदान (रु. में)
1	कोरिया	80	694252	0	648483	1342735	1343	16784.19
2	सरगुजा	275	4871344	251137	19193185	24315666	24316	88420.60
3	जशपुर	191	127455062	4609879	8972997	141037938	141038	738418.52
4	रायगढ़	78	261273	50000	25000	336273	336	4311.19
5	कोरबा	114	2281694	0	2120037	4401731	4402	38611.68
6	जांजगीर-चांपा	504	300000	0	0	300000	300	595.24
7	बिलासपुर	265	72000	0	1957544	2029544	2030	7658.66
8	कबीरधाम	166	130000	0	631000	761000	761	4584.34
9	राजनांदगांव	320	34499346	75000	703553	35277899	35278	110243.43
10	दुर्ग	223	172050	0	0	172050	172	771.52
11	रायपुर	716	13869944	0	147230	14017174	14017	19577.06
12	महासमुंद	369	4386902	0	2418244	6805146	6805	18442.13
13	धमतरी	326	60225327	0	39660	60264987	60265	184861.92
14	उ.ब.कांकेर	112	4675603	12000	274773	4962376	4962	44306.93
15	बस्तर+नारायणपुर	180	3263495	1495765	5769513	10528773	10529	58493.18
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7	N.A	N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A
<b>कुल</b>		<b>3926</b>	<b>257158292</b>	<b>6493781</b>	<b>42901219</b>	<b>306553292</b>	<b>306553</b>	<b>78082.86</b>

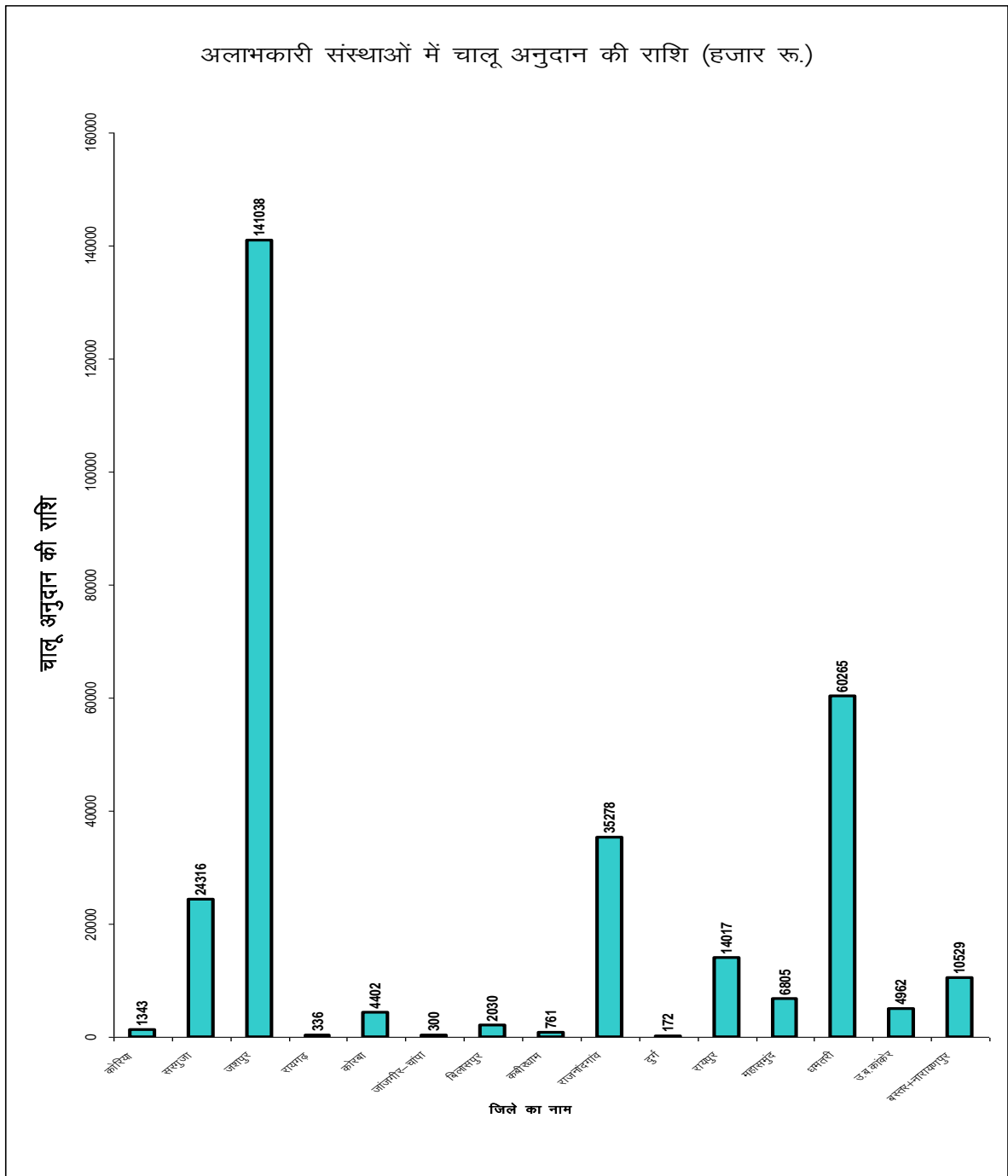
उपरोक्त तालिका अनुसार चालू अनुदान के भी तीन स्रोत से उपलब्ध होता है:- सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान, विदेशी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान एवं अन्य से प्राप्त अनुदान। प्रदेश में एकत्रित रूप में सभी अलाभकारी संस्थाओं को कुल 306553292 रु. का अनुदान प्राप्त होने की जानकारी उपलब्ध हुई। सरकारी



संस्थाओं से प्राप्त अनुदान धन राशि रु. 257158292 (83.88%), विदेशी संस्थाओं से प्राप्त अनुदान धन राशि रु. 6493781 (2.11%) तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान धन राशि के रु. 42901219 (13.99%) की जानकारी एकत्रित की गई है। सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों में सर्वाधिक जशपुर जिले की संस्थाओं को राशि रु. 127455062 एवं न्यूनतम बिलासपुर जिले की संस्थाओं को अनुदान राशि रु. 72000 प्राप्त हुए हैं। विदेशी संस्थाओं से केवल छः जिले की संस्थाओं को ही अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें सर्वाधिक जशपुर जिले को राशि रु. 4609879 एवं न्यूनतम कांकेर जिले को रु. 12000 प्राप्त हुआ है। अन्य स्त्रातों से प्राप्त अनुदानों में सर्वाधिक सरगुजा जिले को रु. 19193185 एवं न्यूनतम रायगढ जिले को रु 25000 प्राप्त हुआ है। उपरोक्त तालिका में अलाभकारी संस्थाओं को प्राप्त अनुदानों का विस्तृत विवरण है।

### चित्र क्रमांक-22

#### अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार चालू अनुदान के तहत कुल प्राप्त धनराशि का विवरण







## अध्याय-19

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं को प्राप्त विविध अनुदानों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में संस्थाओं के आय संबंधी जानकारी भी प्राप्त की गई। सर्वे में पाया गया कि संस्थाओं की आय में अनुदान के अलावा भी कई प्रकार की प्राप्ति हैं, जैसे आर्थिक सहायता (सबसिडी सदस्यता शुल्क दान एवं उपहार आदि) वस्तु रूप में प्राप्ति का मूल्य, सामग्री के स्टॉक का मूल्य, परिचालन से प्राप्त आय/प्राप्तियां (संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय), निवेश/किराये से आय, ब्याज लाभांश आदि, भूमि, भवन, पार्क आदि का किराया एवं अन्य आय एवं प्राप्ति— जिनका जिलेवार विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका क्र. 19, 20 एवं 21 में प्रदर्शित है।

#### तालिका क्र.- 20

#### अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल अन्य आय/प्राप्तियां (रु. लाख में)

क्र.	जिलों के नाम	कुल खोजी गई पंजीकृत संस्थाएं	आर्थिक सहायता (सबसिडी)	सदस्यता शुल्क	दान एवं उपहार आदि	वस्तु रूप में प्राप्ति का मूल्य
1	कोरिया	80	0.00	8.68	5.01	0.10
2	सरगुजा	275	6.00	19.75	39.93	0.00
3	जशपुर	191	21.76	48.29	783.81	0.08
4	रायगढ़	78	0.40	0.87	7.13	0.15
5	कोरबा	114	1.75	1.10	1.74	11.15
6	जांजगीर-चांपा	504	0.00	2.14	0.83	0.10
7	बिलासपुर	265	0.00	7.36	21.73	0.12
8	कबीरधाम	166	5.73	0.26	0.29	0.20
9	राजनांदगांव	320	0.40	4.05	23.09	0.31
10	दुर्ग	223	0.63	0.58	21.15	6.90
11	रायपुर	716	0.36	2.42	6.12	0.00
12	महासमुंद	369	1.99	1.27	17.22	0.02
13	धमतरी	326	0.00	1.15	21.61	0.00
14	उ.ब.कांकेर	112	7.77	5.66	4.09	1.90
15	बस्तर+नारायणपुर	180	1.96	5.46	5.09	0.84
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



योग	3926	48.74	109.03	958.87	21.89
-----	------	-------	--------	--------	-------



**तालिका क्रमांक- 21**  
**अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल अन्य आय/प्राप्तियां (रू. लाख में)**

क्र.	जिलों के नाम	कुल खोजी गई पंजीकृत संस्थाएं	सामग्री के स्टॉक का मूल्य		परिचालन से प्राप्त आय/प्राप्तियां (संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय)
			अन्तिम स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	
1	कोरिया	80	9.18	7.86	28.76
2	सरगुजा	275	21.81	8.85	28.80
3	जशपुर	191	0.32	0.00	389.63
4	रायगढ़	78	3.16	11.68	26.73
5	कोरबा	114	2.60	0.62	17.40
6	जांजगीर-चांपा	504	0.03	0.01	50.28
7	बिलासपुर	265	0.53	0.51	52.92
8	कबीरधाम	166	0.20	0.00	1.54
9	राजनांदगांव	320	130.57	137.28	192.44
10	दुर्ग	223	0.62	0.00	0.22
11	रायपुर	716	0.00	0.00	54.51
12	महासमुंद	369	140.14	869.05	49.33
13	धमतरी	326	0.00	0.00	103.28
14	उ.ब.कांकेर	112	15.28	0.14	2.80
15	बस्तर+नारायणपुर	180	139.70	4.18	3777.93
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	7	0	0	0
<b>योग</b>		<b>3926</b>	<b>464.13</b>	<b>1040.18</b>	<b>4776.57</b>



**तालिका क्र. -22**  
**अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल अन्य आय/प्राप्तियां (रु. लाख में)**

क्र.	जिलों के नाम	निवेश/किराये से आय			योग आय/प्राप्तियां
		ब्याज लाभांश आदि	भूमि, भवन, पार्क आदि का किराया	अन्य आय एवं प्राप्तियां	
1	कोरिया	0.55	0.06	35.75	105.27
2	सरगुजा	6.49	0.11	123.35	521.68
3	जशपुर	73.86	0.00	217.06	3235.14
4	रायगढ़	0.23	2.68	1.27	68.94
5	कोरबा	1.34	0.00	37.92	144.73
6	जांजगीर-चांपा	0.11	0.02	0.64	57.27
7	बिलासपुर	5.63	0.00	2.36	128.53
8	कबीरधाम	0.55	0.53	69.43	96.54
9	राजनांदगांव	42.35	0.22	109.56	728.21
10	दुर्ग	0.04	0.00	2.09	48.52
11	रायपुर	6.26	1.03	16.90	239.35
12	महासमुंद	8.81	1.79	11.32	-532.14
13	धमतरी	11.18	2.81	17.38	815.35
14	उ.ब.कांकेर	1.60	1.23	13.21	224.37
15	बस्तर+नारायणपुर	28.60	2.57	393.74	5616.77
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>187.59</b>	<b>13.06</b>	<b>1051.98</b>	<b>11498.52</b>

उपरोक्त तालिका अनुसार अनुदानों के अलावा अन्य प्राप्तियों में सर्वाधिक आय संस्था के परिचालन से प्राप्त हुई है, संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय से कुल 477656622 रु. आय हुई है। संस्था के परिचालन से प्राप्त आय में जिलेवार सर्वाधिक आय बस्तर+नारायणपुर जिले को 377792538 रु. एवं न्यूनतम दुर्ग जिले को 22299 रु. की है। संस्था के कुल आय में न्यूनतम योगदान भूमि, भवन, पार्क आदि का किराया क्षेत्र का है, जिसमें कुल आय रु.1306331 की हुई है। उपरोक्त तालिका में अलाभकारी संस्थाओं को प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त विविध स्रोतों से प्राप्त आय का विस्तृत विवरण प्रदर्शित है।



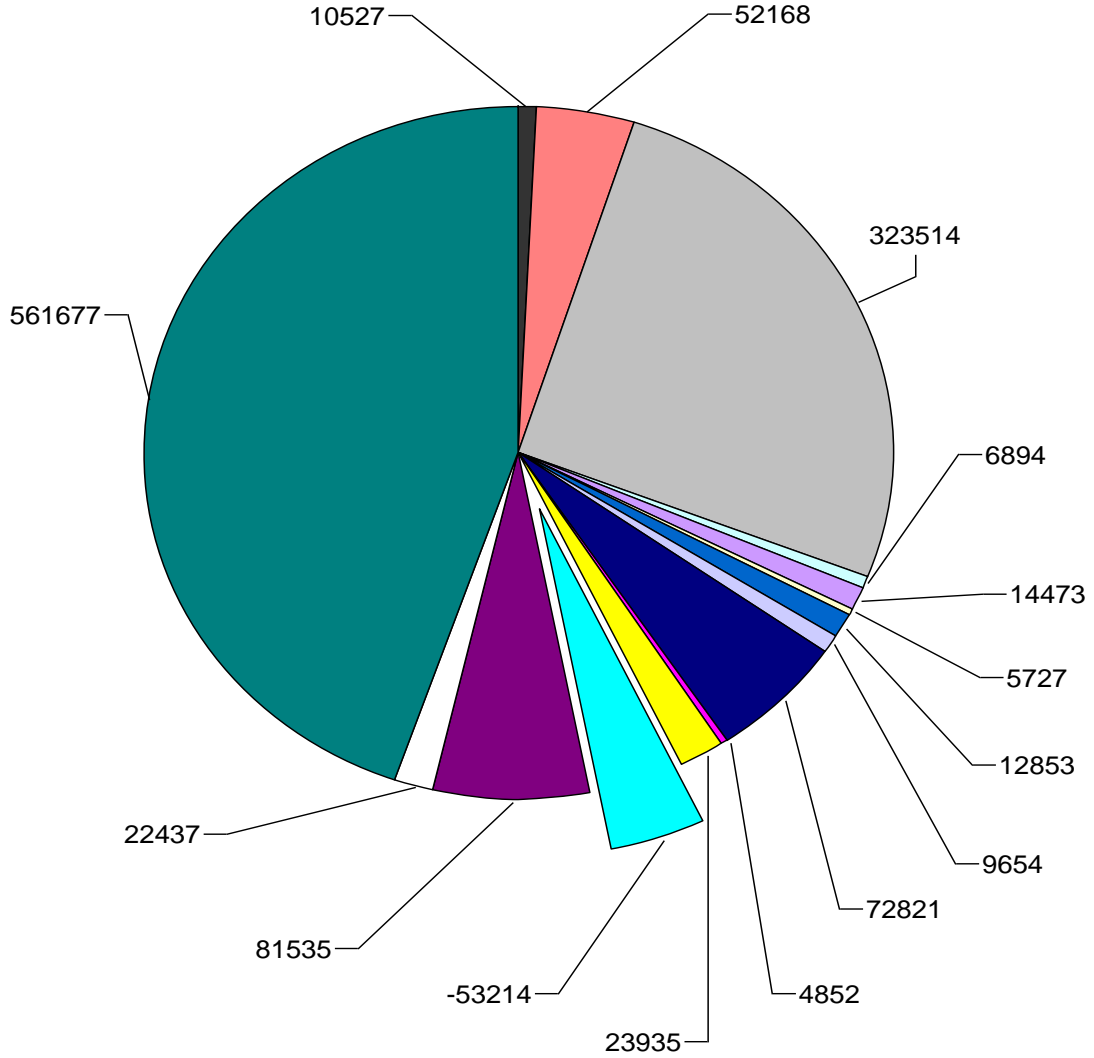




चित्र क्रमांक-23  
अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल अन्य आय/प्राप्तियां



### अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल आय/प्राप्तियां



कोरिया	सरगुजा	जशपुर	रायगढ़	कोरबा
जांजगीर-चांपा	बिलासपुर	कबीरधाम	राजनांदगांव	दुर्ग
रायपुर	महासमुंद	धमतरी	उ.ब.कांकेर	बस्तर+नारायणपुर



## अध्याय-20

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के व्ययों का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में संस्थाओं के व्यय संबंधी जानकारी भी प्राप्त की गई। सर्वेक्षण हेतु निर्धारित अनुसूची 2.0:डी के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं में मुख्यतः वेतन, भत्ते एवं मजदूरी, मानदेय, ब्याज, किराया, संस्थाओं के परिचालन व्यय, अन्य संस्थाओं को दिया गया अनुदान, निःशुल्क दी गयी वस्तुओं का मूल्य, ह्रास, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का भुगतान इत्यादी मदों पर ही व्यय किये जाने की जानकारी एकत्रित की गई। प्रदेश में सर्वेक्षित अलाभकारी संस्थाओं के संचालन में कुल रु. 1036819658 के व्यय का आकड़ा संकलित किया गया, जिसमें सवार्धिक व्यय वेतन, भत्ते एवं मजदूरी के लिए रु. 493019611.00 (47.55%) तथा संस्थाओं के परिचालन व्यय में रु. 428592498.40 (41.33%), किया गया है, न्यूनतम व्यय अप्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिए राशि रु. 189431.00 (0.018%) व्यय किया गया। संस्थाओं के संचालन में सवार्धिक व्यय बस्तर जिले द्वारा रु. 461362790.00 किया गया जो कुल व्यय का 44.49% है एवं न्यूनतम व्यय दुर्ग जिले द्वारा रु. 3051593.00 किया गया जो कुल व्यय का मात्र 0.29% है, इसका जिलेवार एवं मदवार व्यय विवरण निम्न तालिकाओं से सुस्पष्ट है:-

#### तालिका क्रमांक-23

अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण, अनुसूची का संकलित प्रतिवेदन में संस्थाओं के कोष के व्ययों का विवरण (विस्तृत आंकड़ा अनुसूची 2.0:D)

क्र.	जिलों के नाम	वेतन, भत्ते एवं मजदूरी	दिया गया मानदेय	दिया गया ब्याज	दिया गया किराया	अन्य परिचालन व्यय
1	कोरिया	3879300	830821	0	209653	3003525
2	सरगुजा	12251767.1	934380	3794	826506	7703215
3	जशपुर	51083605	915805	15265.05	493622	179610784
4	रायगढ़	1683673	508925	2000	88700	997098
5	कोरबा	1522385	1036571	1711	185000	4375968
6	जांजगीर-चांपा	1210345	206835	290000	1312000	1802601
7	बिलासपुर	5513268	221299.82	92310	954592	3013461.7
8	कबीरधाम	6065291	827174	10665	55786	317900
9	राजनांदगांव	20778405	2579226	1096257	642417	25442317
10	दुर्ग	1727682	429459	76750	58145	750558
11	रायपुर	4377126	48000	12148.25	217690	3843777.7
12	महासमुंद	5772618	463766	43905	182200	38993772
13	धमतरी	2354526	16534	213756	378638	74797380
14	उ.ब.कांकेर	493096	2563650	18000	15000	527380
15	बस्तर+नारायणपुर	374306524	1384182	417329	676632	83412761
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	<b>योग</b>	<b>493019611.1</b>	<b>12966627.82</b>	<b>2293890.3</b>	<b>6296581</b>	<b>428592498.4</b>
	<b>प्रतिशत</b>	<b>47.55</b>	<b>1.25</b>	<b>0.22</b>	<b>0.60</b>	<b>41.33</b>



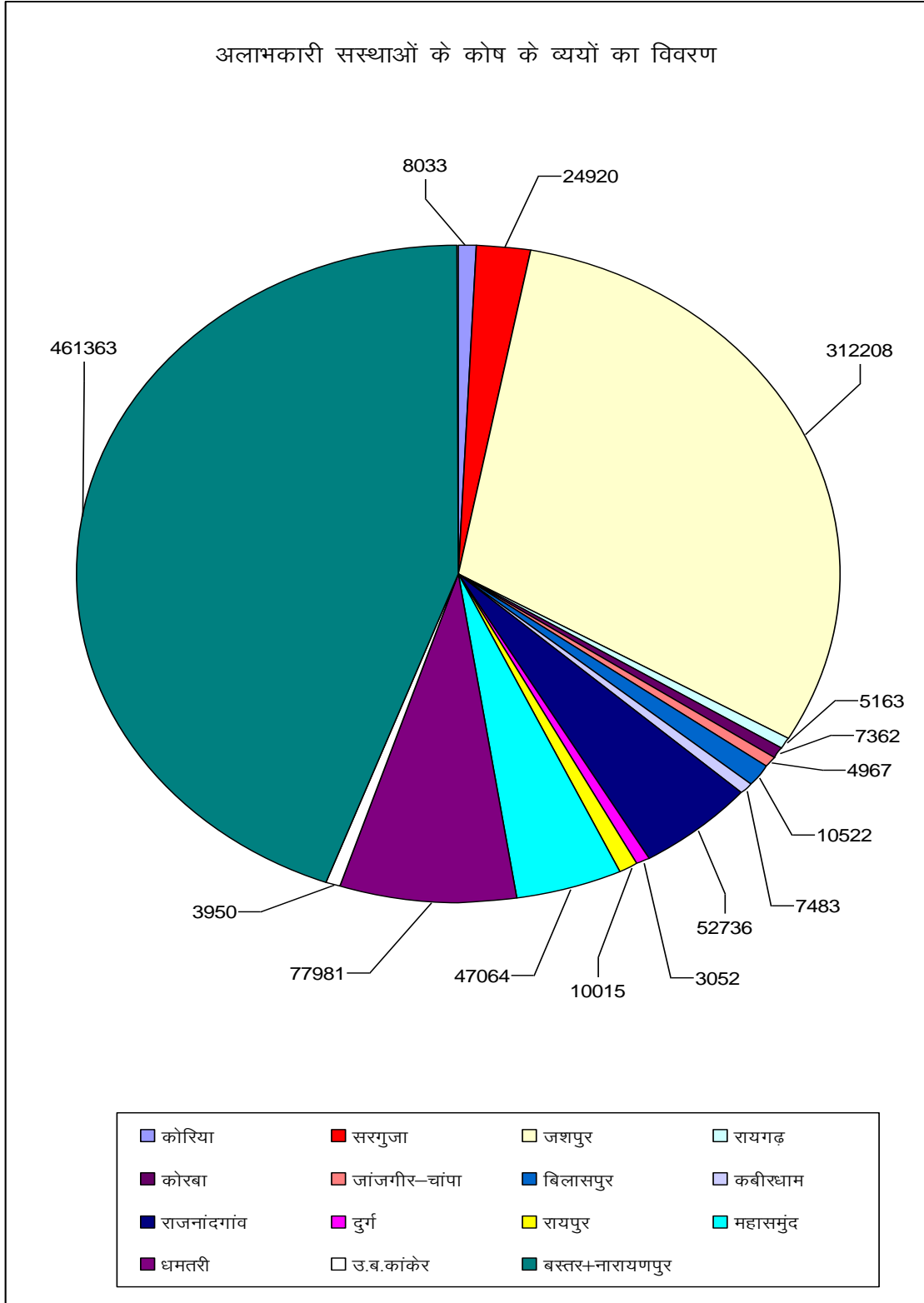
## तालिका क्रमांक-24

अलाभकारी सस्थाओं के द्वितीय चरण, अनुसूची का संकलित प्रतिवेदन में संस्थाओं के कोष के व्ययों का विवरण (विस्तृत आंकड़ा अनुसूची 2.0:D)

क्र.	जिलों के नाम	अन्य संस्थाओं को दिया गया अनुदान	निःशुल्क दी गयी वस्तुओं का मूल्य	ह्यास के लिए प्रावधान	करों का भुगतान		योग (कुल चालू व्यय)
					अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	
1	कोरिया	500	93120	16290	0	0	8033209
2	सरगुजा	113105	2368397	135	142	718841	24920282
3	जशपुर	72647651	1603055	5835181	3303	0	312208271
4	रायगढ़	1859000	0	13000	5000	6000	5163396
5	कोरबा	0	24155	163672	52707	0	7362169
6	जांजगीर-चांपा	0	0	93192	51603	0	4966576
7	बिलासपुर	223361	21120	482090	625	0	10522128
8	कबीरधाम	30410	104200	5103	5900	60640	7483069
9	राजनांदगांव	179600	271506	1738943	0	7378	52736049
10	दुर्ग	0	0	8999	0	0	3051593
11	रायपुर	1257274	0	259390	0	0	10015406
12	महासमुंद	1253672	209708	117150	0	27350	47064141
13	धमतरी	34290	3603	177877	0	4259	77980863
14	उ.ब.कांकेर	280863	51727	0	0	0	3949716
15	बस्तर+नारायणपुर	6000	137512	951699	70151	0	461362790
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
योग		77885726	4888103	9862721	189431	824468	1036819658
प्रतिशत		7.51	0.47	0.95	0.018	0.07	100



चित्र क्रमांक-24  
अलाभकारी संस्थाओं में जिलेवार कुल व्यय







## अध्याय— 21

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के भौतिक परिसम्पतियों का विवरण

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में संस्थाओं के भौतिक परिसम्पतियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। सर्वे में पाया गया कि निम्नलिखित भौतिक परिसम्पतियों की मुख्य मदें हैं :- भूमि, भवन, अन्य निर्माण, भूमि-पौधरोपण तथा बागवानी विकास, मशीनरी एवं संयंत्र, परिवहन एवं उपकरण, अन्य कार्यालय उपकरण, बहुमूल्य वस्तुएं तथा अन्य भौतिक परिसम्पत्तियां। प्रदेश की समस्त अलाभकारी संस्थाओं के पास कुल रु. 342797958.00 की भौतिक परिसम्पत्तियां हैं जिसमें वर्ष के दौरान रु. 94683785.60 (27.62%) की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक संपत्ति कोरबा जिले के पास रु. 13719823.80 की है एवं न्यूनतम रायगढ़ जिले के पास रु. 219810.00 है। मदों के अनुसार सर्वाधिक मूल्य की भौतिक परिसम्पत्तियां भवन हैं जिनका मूल्य रु. 209157266.00 (कुल मूल्य का 61.01%) है, एवं न्यूनतम मूल्य की भौतिक परिसम्पत्तियां भूमि पौधरोपण तथा बागवानी विकास हैं जिनका मूल्य रु. 118735.00 (कुल मूल्य का 0.03%)।

अलाभकारी संस्थाओं के जिलेवार एवं वर्गवार कुल भौतिक परिसम्पत्तियों के मूल्यों में वर्ष के दौरान हुई वृद्धि के साथ-साथ पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के पास अंतिम धनराशि का जिलेवार विस्तृत विवरण आगामी पृष्ठ में, तालिका क्रमांक 25 में प्रदर्शित है ।



**तालिका क्र.-25**  
**पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं द्वारा भौतिक परिसम्पत्तियों का विवरण**  
**(धन राशि रु. में)**

क	जिलों के नाम	भूमि		भवन		अन्य निर्माण एवं भूमि		पौधरोपण तथा बागवानी विकास		मनगिरी एवं संवर्धन		परिचरन एवं उपकरण		अन्य कार्यालय उपकरण		अन्य भौतिक परिसम्पत्तियां		बहुमूल्य वस्तुएं		भौतिक परिसम्पत्तियों में कुल निवेश राशि		
		वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष	
1	काठिया	0	443300	36094	194958	0	0	0	175	0	36258	1550	196600	0	137308	427609	8735	1205274	0	7419	415170	2280110
2	सरगुजा	600878	535211	0	314875	0	0	0	0	400111	743204	0	8350	100000	421834.3	15325	326156	0	246949	1116314	2596579	
3	रायपुर	151537	1823971	4621334	54234273	394900	1083192	0	0	5009810	8620825	847022	2519578	648749	2128652	6474410	41428748	0	0	18147782	111839239	
4	रामगढ़	0	52000	876887	49000	28023	8500	0	2000	0	30000	889	10310	9100	51000	0	12000	0	5000	914899	219810	
5	कोरबा	0	0	446773	5287141	50000	511501	0	1650	0	4381928	0	1089986	0	1868906	0	57812	0	0	496773	13719824	
6	राजगीर-राय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528086	25700	117017	0	10225	0	0	25700	655328	
7	बिलासपुर	9719894	1698510	0	11449740	0	0	0	0	0	0	0	1308592	1183420	1500	1182093	0	0	11029986	15513763		
8	कबीरधाम	300000	0	833089	0	67540	0	53000	0	92800	0	319500	0	269420	0	32800	0	1200	0	1969349	1969349	
9	राजनांदगाव	0	6242726	1598954	27294727	0	0	11478	38150	361020	1874356	475595	493816	718800	13725841	555961	17659372	0	4425	3721808	67333413	
10	दुर्ग	0	287532	33888	1497191	0	0	0	0	29650	0	0	0	3400	0	33883	0	57482	63538	1879488		
11	सयपुर	165	0	816598	1058597	250140	0	0	0	57752	89460	27833	27833	169367	53690	548838	420412	0	0	1870693	1649992	
12	महासुंद	5149	58149	6896066	7722211	134786	1457596	0	71935	2410467	3516210	0	0	346525	1428600	59977	515735	0	0	9852970	14770456	
13	भदवरी	17447	979905.6	0	6126983	0	0	0	0	0	567112	0	710706	0	483482	0	1074430	0	0	17447	9942619	
14	रा.ब.कांठ	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	106781	23250	0	0	0	0	0	106781	423250	
15	सतस-सावणपुर	1014915	369050	36271935	93527570	1688047	0	1461167	5000	364730	1230729	2310211	581279	953835	2321773	2434261	0	0	44934575	99974107		
16	सतनाडम-बीजापुर																		N.A.			
	योग	11810005	12490354	52431619	209157266	2613436	3060789	1525820	118735	8762598	20198825	3098168	7698876	4421621	22870536	10019319	66881301	1200	321275	94683785	342797958	
	प्रतिशत		3.64		61.01		0.89		0.03		5.8		2.24		6.67		19.51		0.09		27.62	100



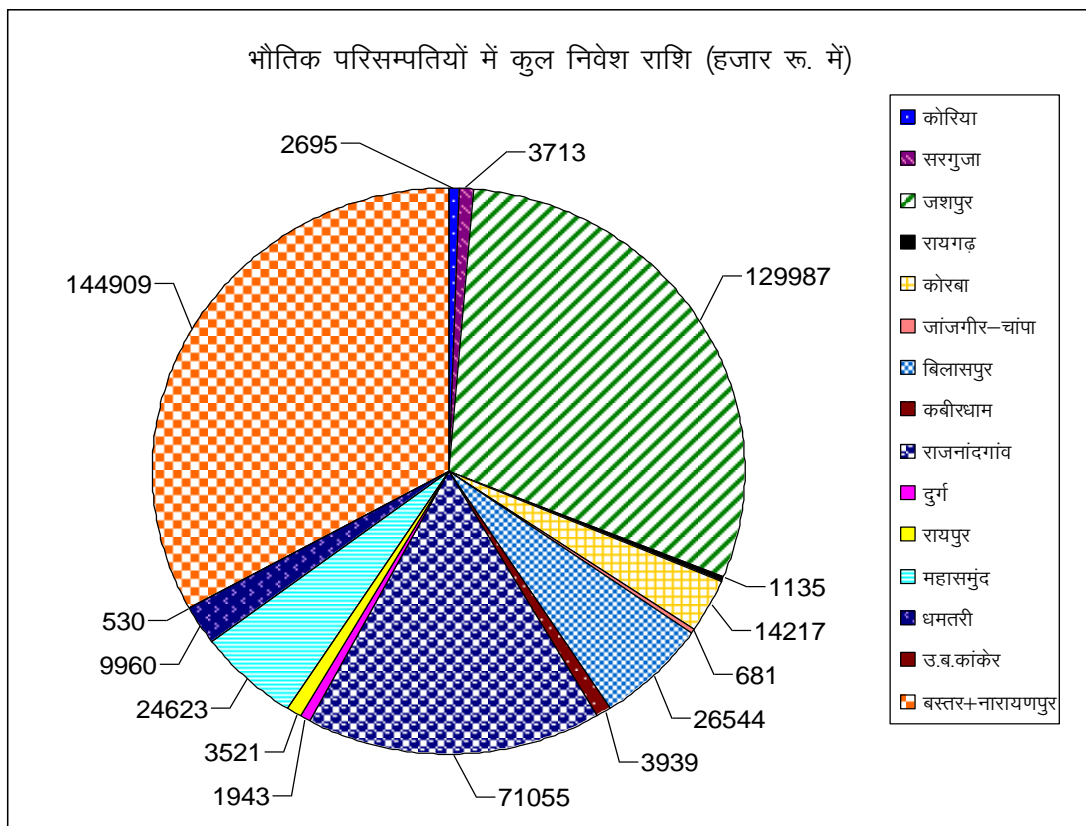




**तालिका क्र.-26**  
**अलाभकारी सस्थाओं में भौतिक परिसम्पतियों में निवेश राशि**

क्र.	जिलों के नाम	भौतिक परिसम्पतियों में कुल निवेश राशि		भौतिक परिसम्पतियों में कुल निवेश राशि (रु. में)	भौतिक परिसम्पतियों में कुल निवेश राशि (हजार रु. में)
		वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष		
1	कोरिया	415170	2280110	2695280	2695
2	सरगुजा	1116314	2596579.35	3712893	3713
3	जशपुर	18147782	111839239	129987021	129987
4	रायगढ़	914899	219810	1134709	1135
5	कोरबा	496773	13719823.8	14216597	14217
6	जांजगीर-चांपा	25700	655328	681028	681
7	बिलासपुर	11029986	15513763.3	26543749	26544
8	कबीरधाम	1969349	1969349	3938698	3939
9	राजनांदगांव	3721808	67333413	71055221	71055
10	दुर्ग	63538	1879488.5	1943027	1943
11	रायपुर	1870694	1649991.59	3520685	3521
12	महासमुंद	9852970	14770436	24623406	24623
13	धमतरी	17447	9942618.6	9960066	9960
14	उ.ब.कांकेर	106781	423250	530031	530
15	बस्तर+नारायणपुर	44934575	99974107	144908682	144909
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	<b>योग</b>	<b>94683786</b>	<b>344767307</b>	<b>439451093</b>	<b>439451</b>

**चित्र क्रमांक-25**





## अध्याय 22

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के फण्ड का वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण में संस्थाओं द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश की जानकारी प्राप्त की गई। जिसके अनुसार पाया गया कि निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश की मुख्य मर्दे हैं :- सरकारी प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियां, निजी क्षेत्र के अंश एवं ऋण, बैंक सावधि खाते में निवेश, एवं अन्य निवेश। प्रदेश की समस्त अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा कुल रु. 142486419.00 राशि का निवेश किया गया। जिसमें से सर्वाधिक रु. 64552435.00 (45.30%) बैंक सावधि खाते में निवेश, रु. 24828685.00 (17.43%) सरकारी प्रतिभूतियों में, रु. 7405596.00 (5.20%) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियों में, न्यूनतम रु. 1201841.00 (0.84%) निजी क्षेत्र के अंश एवं ऋण में, तथा रु. 44497862.00 (31.23%) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश किया गया है। जिलेवार सर्वाधिक निवेश बस्तर जिले के द्वारा रु. 53219078.00 का किया गया है जो कुल निवेश का 37.35% है, एवं दुर्ग जिले के द्वारा रु. 2600.00 का न्यूनतम निवेश किया गया है।

नीचे दी तालिका में अलाभकारी संस्थाओं के जिलेवार एवं वर्गवार कुल वित्तीय परिसम्पत्तियों के मूल्य और उनके प्रतिशत का विस्तृत विवरण है।

#### तालिका क्र.-27

#### अलाभकारी संस्थाओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों में कुल निवेश राशि

क.	जिलों के नाम	सरकारी प्रतिभूतियां	सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियां	निजी क्षेत्र के अंश एवं ऋण	बैंक सावधि खाते में निवेश	अन्य निवेश धन राशि	वित्तीय परिसम्पत्तियों में कुल निवेश
1	कोरिया	33000	0	30978	578000	653260	1295238
2	सरगुजा	1320535	0	0	560557	374430	2255522
3	जशपुर	0	5654000	0	7878192	7587129	21119321
4	रायगढ़	0	0	0	62969	20000	82969
5	कोरबा	22050000	0	0	700000	0	22750000
6	जांजगीर-चांपा	0	0	0	105300	2543	107843
7	बिलासपुर	20000	0	0	221258	7453	248711
8	कबीरधाम	0	0	0	420000	14750	434750
9	राजनांदगांव	0	0	368341	7184650	27689758	35242749
10	दुर्ग	0	0	0	0	2600	2600
11	रायपुर	17949	0	0	110975	25700	154624
12	महासमुंद	90000	0	62000	1168506	0	1320506
13	धमतरी	0	0	30000	2315730	1848778	4194508
14	उ.ब.कांकेर	0	0	8000	50000	0	58000
15	बस्तर+नारायणपुर	1297201	1751596	702522	43196298	6271461	53219078
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर			N.A.			
	योग	24828685	7405596	1201841	64552435	44497862	142486419

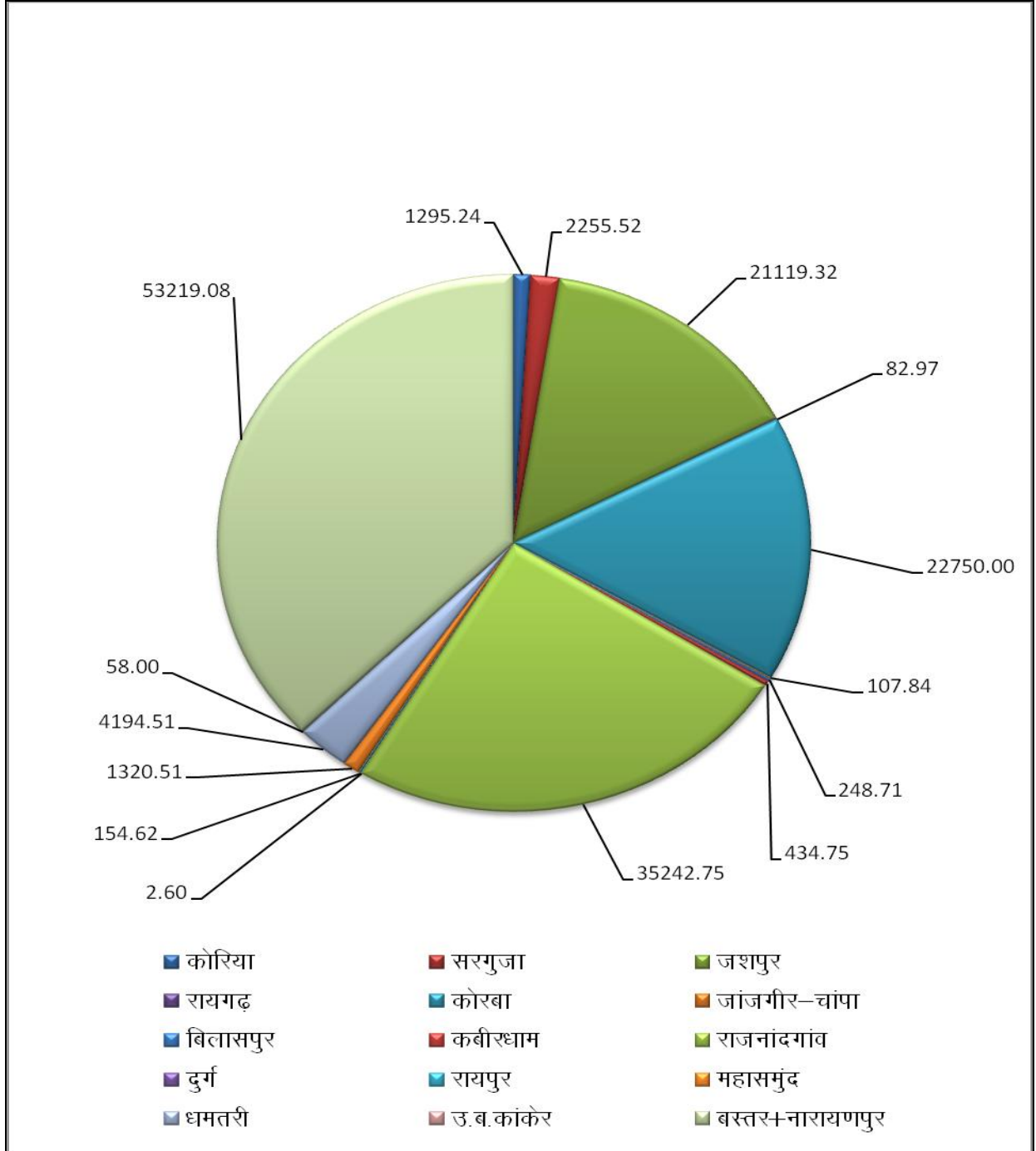


प्रतिशत	17.43	5.20	0.84	45.30	31.23	100.00
---------	-------	------	------	-------	-------	--------



### चित्र क्रमांक-26

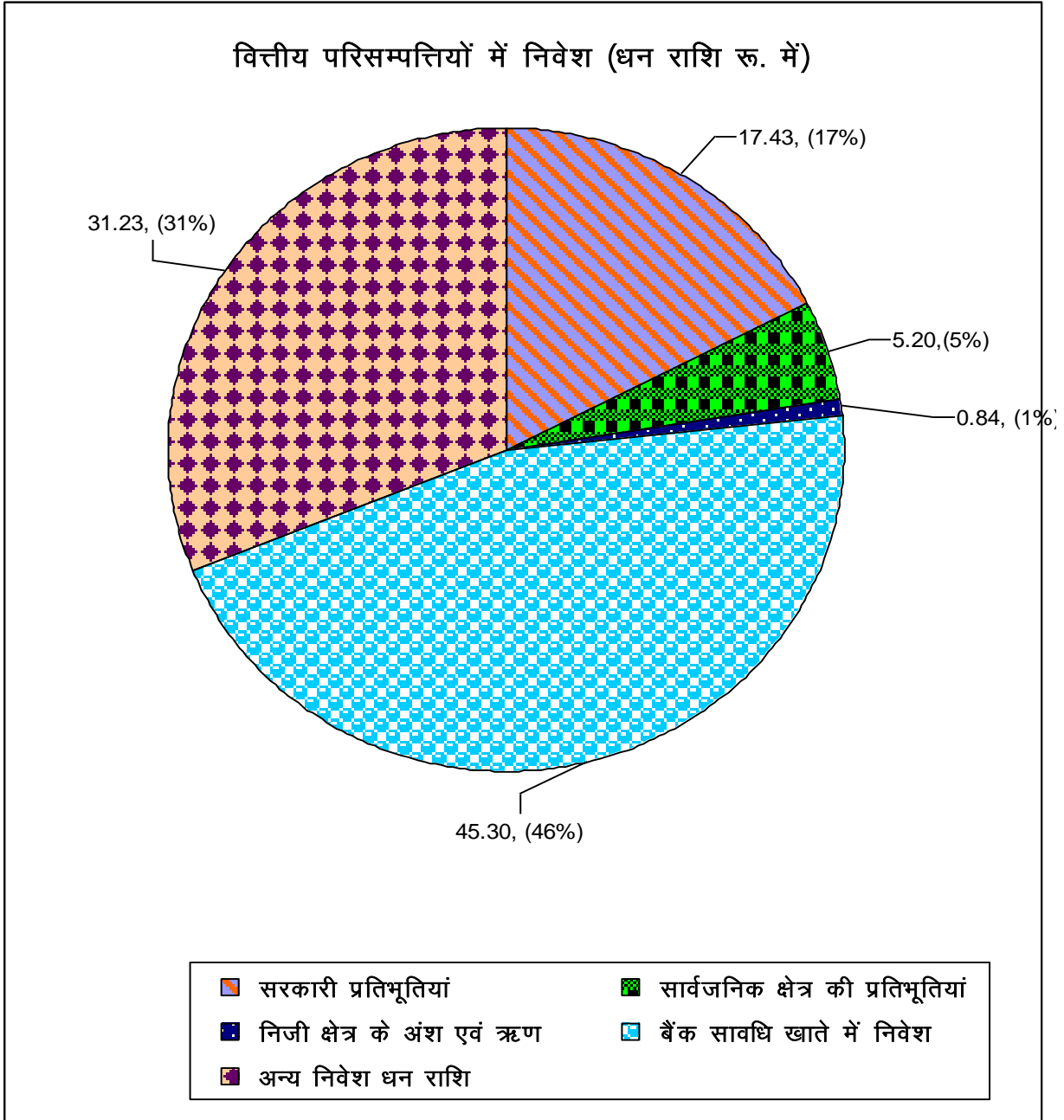
अलाभकारी संस्थाओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों में कुल निवेश राशि  
जिलेवार कुल निवेश धन राशि (हजार रु. में)





### चित्र क्रमांक-27

अलाभकारी संस्थाओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों में कुल निवेश राशि का मदवार विवरण



सरकारी प्रतिभूतियां	सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियां	निजी क्षेत्र के अंश एवं ऋण	बैंक सावधि खाते में निवेश	अन्य निवेश धन राशि
17.43	5.20	0.84	45.30	31.23



## अध्याय— 23

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि का विवरण निम्न है। प्रदेश की समस्त अलाभकारी संस्थाओं के पास कुल रु. 206525522.00 राशि है, जिसमें रु. 8973213.71 (4.34%) नकद जमा राशि एवं रु.197552307.90 (95.66%) बैंक जमा राशि के रूप में है। जिलेवार सर्वाधिक जमा राशि बस्तर जिले के पास रु. 68465.83 का है जो कुल जमा राशि का 33.15% है, एवं न्यूनतम दुर्ग जिले के पास रु. 118.53 का है जो कुल जमा राशि का 0.05% है।

नीचे दी तालिका में अलाभकारी संस्थाओं के जिलेवार एवं वर्गवार कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि और उनके प्रतिशत का विस्तृत विवरण प्रदर्शित है ।

### तालिका क्र.-28

### संस्थाओं के कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि का विवरण

क्रं	अलाभकारी संस्थाओं के अनुसूची के संकलित प्रतिवेदन (विस्तृत आंकड़ा अनुसूची 2.0:D) के अनुसार कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि (हजार रु. में)				
	जिलों के नाम	नकद जमा धन राशि (हजार रु. में)	बैंक जमा धन राशि (हजार रु. में)	कुल जमा धन राशि (हजार रु. में)	प्रतिशत
1	कोरिया	123.01	1404.54	1527.55	0.74
2	सरगुजा	719.97	5416.62	6136.6	2.97
3	जशपुर	716.82	40046.23	40763.05	19.73
4	रायगढ़	263.73	522.76	786.49	0.38
5	कोरबा	119.26	6644.71	6763.97	3.27
6	जांजगीर-चांपा	95.48	529.87	625.36	0.3
7	बिलासपुर	544.78	4499.64	5044.42	2.44
8	कबीरधाम	532.82	530.89	1063.7	0.51
9	राजनांदगांव	391.93	32903.89	33295.81	16.12
10	दुर्ग	53.28	65.25	118.53	0.05
11	रायपुर	1825.33	13528.07	15353.4	7.43
12	महासमुंद	231.88	3231.9	3463.78	1.67
13	धमतरी	369.86	21589.09	21958.94	10.63
14	उ.ब.कांकेर	4.9	1153.2	1158.1	0.56
15	बस्तर+नारायणपुर	2980.18	65485.65	68465.83	33.15
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर		N.A.		
	<b>योग</b>	<b>8973.21</b>	<b>197552.31</b>	<b>206525.52</b>	<b>100</b>
	<b>प्रतिशत</b>	<b>4.34</b>	<b>95.66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



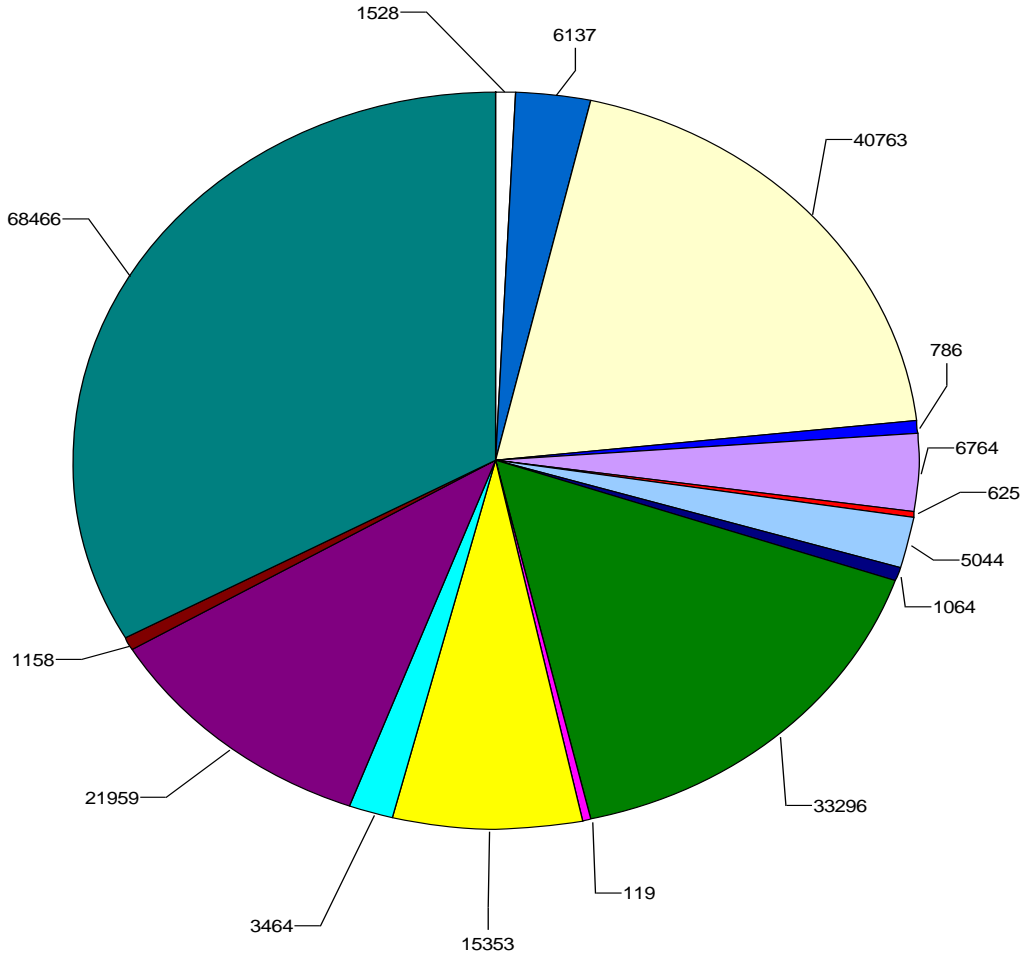
## चित्र क्रमांक-28

अलाभकारी सस्थाओं के अनुसूची के संकलित प्रतिवेदन (विस्तृत आंकड़ा अनुसूची 2.0:D) के अनुसार कुल नकद एवं बैंक में जमा धन राशि





अलाभकारी सस्थाओं के अनुसूची के संकलित प्रतिवेदन (विस्तृत  
आंकड़ा अनुसूची 2.0:D) के अनुसार कुल जमा धन राशि  
(हजार रु. में)



कोरिया	सरगुजा	जशपुर	रायगढ़	कोरबा
जांजगीर-चांपा	बिलासपुर	कबीरधाम	राजनांदगांव	दुर्ग
रायपुर	महासमुंद	धमतरी	उ.ब.कांकेर	बस्तर+नारायणपुर



## अध्याय 24

### पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कुल निधि, (अन्तिम अवशेष)

पंजीकृत अलाभकारी संस्थाओं के कुल निधि (अन्तिम अवशेष) राशि का विवरण निम्न है। प्रदेश की समस्त अलाभकारी संस्थाओं के पास कुल रू. 449074180.00 राशि है। जिलेवार सर्वाधिक जमा राशि जशपुर जिले के पास रू. 270707098.70 का है, जो कुल जमा राशि का 60.28% है, एवं न्यूनतम कांकेर जिले के पास रू. 71025.00 का है जो कुल जमा राशि का 0.016% है। नीचे तालिका में अलाभकारी संस्थाओं के जिलेवार एवं वर्गवार कुल निधि (अन्तिम अवशेष) राशि और उनके प्रतिशत का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया गया है।

#### तालिका क्र.-29

#### अलाभकारी संस्थाओं के कुल निधि (अन्तिम अवशेष) धन राशि का विवरण

क्रं	जिलों के नाम	कुल अन्तिम अवशेष (रू. में)	कुल अन्तिम अवशेष (हजार रू. में)	प्रतिशत
1	कोरिया	533576	534	0.119
2	सरगुजा	5009514	5010	1.116
3	जशपुर	270707099	270707	60.281
4	रायगढ़	450592	451	0.100
5	कोरबा	2203752	2204	0.491
6	जांजगीर-चांपा	2842298	2842	0.633
7	बिलासपुर	2438061	2438	0.543
8	कबीरधाम	262403	262	0.058
9	राजनांदगांव	85393197	85393	19.015
10	दुर्ग	2000617	2001	0.446
11	रायपुर	2663913	2664	0.593
12	महासमुंद	16424287	16424	3.657
13	धमतरी	7817291	7817	1.741
14	उ.ब.कांकेर	71025	71	0.016
15	बस्तर+नारायणपुर	50256555	50257	11.191
16	दन्तेवाड़ा+बीजापुर	0	N.A.	
योग		449074180	449074	100

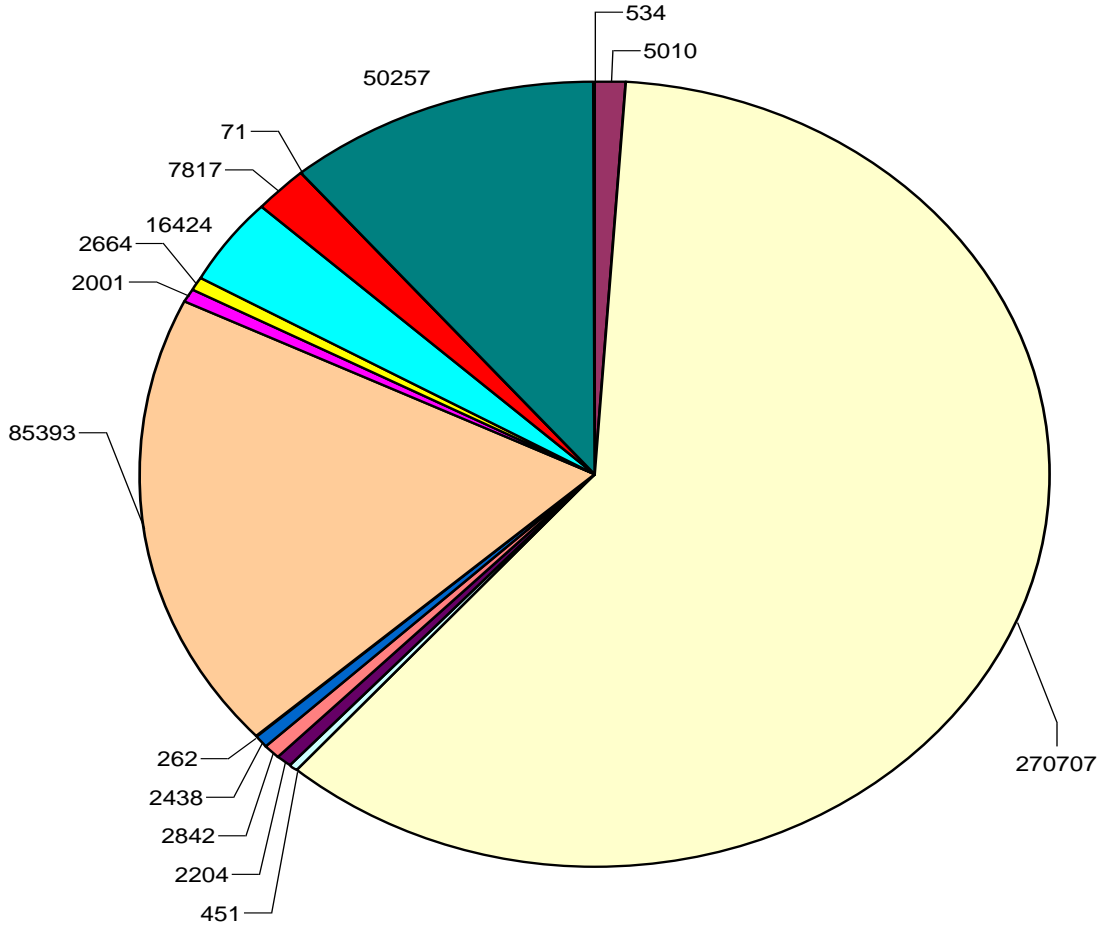


## चित्र क्रमांक— 29

अलाभकारी सस्थाओं के अनुसूची के संकलित प्रतिवेदन (विस्तृत आंकड़ा अनुसूची 2.0:D) के अनुसार कुल निधि (अन्तिम अवशेष) (हजार रु.में)



अलाभकारी संस्थाओं में कुल निधि (हजार रु. में)  
(अन्तिम अवशेष- विस्तृत आंकड़ा अनुसूची 2.0:डी)



कोरिया	सरगुजा	जशपुर	रायगढ़
कोरबा	जांजगीर-चांपा	बिलासपुर	कबीरधाम
राजनांदगांव	दुर्ग	रायपुर	महासमुंद
धमतरी	उ.ब.कांकेर	बस्तर+नारायणपुर	



## Annexure- I

### OVERVIEW

#### Background<sup>1</sup>

- 1.1 Voluntary Organisations play a vital role in the shaping and implementation of participatory democracy. Their credibility lies in the responsible and constructive role they play in society. They have been contributing immensely for quite sometime towards various development programmes. They work at grassroots level even in remote areas and, therefore, their reach is much wider. They are closer to ground realities and know the needs of the communities. Their approach with target group is direct, emphatic and therefore they are able to draw more contextualized plans of action. They also manage to develop intimate contacts with the people and develop confidence among them.
- 1.2 During the nineties, VOs/NGOs have emerged as important players in the development arena. On the one hand, voluntary sector is making significant contributions at the UN sponsored meetings at global level, and on the other, VOs are also working for the empowerment of the poor at the grassroots level and are providing quick help in the management of disasters. Role of VOs was particularly recognised at the United Nations Conference on Environment and Development held at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. Thereafter active presence of VOs continued at all important global international fora, such as the Cairo Population Conference 1994, the Copenhagen World Summit on Social Development 1995, the Beijing Conference on Women 1995, and so on. In the coming years, it is expected that voluntary sector would be playing significant role not only in social sectors but also in other sectors. Keeping in view the respect for the independence of VOs and their significant role, the emerging voluntary sector is also known as independent sector, third sector, civil-society sector or social economy sector.

#### Depth of Voluntarism in India

- 1.3 India has a rich tradition of voluntary action. Before Independence, VOs imbued with the Gandhian philosophy were playing significant role mainly in social welfare activities and now, the range of spheres covered by voluntary sector has expanded considerably covering almost all development related activities. Some of the reasons put forward for increase in the number and activities of VOs are the decline of socialism and an increased national and international funding for voluntary sector. In a number of developmental activities, VOs are working as supplements or complements to the governmental efforts.
- 1.4 The origin and development of the voluntary sector in India has been shaped by two major influences: one rooted in indigenous traditions and value systems, and the other a product of the interface between the Indian society and the western world. The Indian traditions and value-systems are in turn rooted in religion that prescribes a code of ethics for the individual and the principles governing social life. A noteworthy feature of all major religions has been the emphasis they place on charity and sharing wealth with others, especially the poor. In Hinduism serving the poor is considered equivalent to serving God. Philanthropy and

---

<sup>1</sup> Extracts from Report of the Steering Committee on Voluntary Sector for the Tenth Five Year Plan (2002-07), Planning Commission, Government of India (January 2002); TFYP - STEERING COMMITTEE Sr. No. 7/ 2001 are reproduced here.



individual acts of social service have, historically, been the main forms of voluntary activity in India. Institutionalised social service activities existed largely within the domain of religious institutions: Ashramas and Maths among Hindus, Waqfs and Khanqahs among Muslims and Gurudwaras and Deras among Sikhs. Throughout the ancient and medieval periods, voluntary activity – whether individual inspired or state supported – found its natural expression through religious institutions. The concept of secular voluntary activity accelerated with the advent of western, mainly British, influence in India. The work of Christian missionaries in the field of education and health care, especially in remote tribal areas, stood out as examples of dedicated service to the poor, even though the motivation may have been to win over these people to Christianity. The example of Christian missionary work exerted a great influence on the new English educated elite that emerged in the eighteenth and nineteenth centuries. The organized form of charity and service to the poor practiced by the Christian missionaries impressed many who tried to emulate them. The activities of the Brahma Samaj in Bengal, Arya Samaj in north India and the Ramakrishna Mission in different parts of the country are noteworthy. Mahatma Gandhi further developed the tradition set by these early voluntary religious organizations. Though religious in form, the content of Gandhi's programme was secular: spinning, promotion of cottage industries, decentralization of power and an economy based on the satisfaction of need rather than greed. 1.5 After the Independence, there was awareness that development to be meaningful requires mobilisation of resources, public cooperation and creation of social capital. Gradually, professionals from various disciplines joined the voluntary sector to undertake multi-sectoral development work. It has been recognised that no development strategy can be successful unless a shared vision of public sector, private sector and voluntary sector is created and the civil society, having VOs as the key actors, can play a vital role in this strategy for development. The process of social mobilisation and development of people's initiatives cannot be achieved without the active support and involvement of VOs.

#### Diversity of the Voluntary Sector

1.6 In India, societies, associations, organisations, trusts or companies registered under the Societies Registration Act, 1860; the Indian Trusts Act, 1882; the Charitable & Religious Trusts Act, 1920 or as a charitable company under Section 25 of the Companies Act, 1956 are considered as VOs / NGOs. In addition, there are informal groups working at grassroots level without being registered under any legislation but may also be considered as part of voluntary sector. VOs may be working in the field of welfare of disabled; development of other disadvantaged sections like SCs/STs, children & women in education; environment; human rights; and on issues like resettlement & rehabilitation of oustees by big projects, right to information and so on. VOs may take up issues concerning a particular village or a community to the global issues like impact of WTO or global warming. The range of associations or societies may vary from a resident welfare association to an advocacy organisation. The substantive areas of work of VOs have changed considerably over time. The following typology of civil society associations is available from a study by Rajesh Tandon (2001<sup>2</sup>):

##### **(i) Traditional Associations**

Such associations exist around a social unit either defined by a tribe, ethnicity or caste. Associations

---

<sup>2</sup> Tandon, Rajesh (2001) Civil Society in India: An Exercise in Mapping. *Innovations in Civil Society* 1(1): 2-9.



of this variety undertake a wide range of functions in the lives of those citizens. Several important struggles to protect and advance customary rights of tribals over natural resources in different parts of the country have been led by such associations.

### **(ii) Religious Associations**

Over the centuries, new sects and religions were born and incorporated into Indian life. Charity, help to the needy, service to the poor and daan (giving) have been uniformly recommended by all these religions and sects in India. Activities are carried out in the areas of education, health care, drinking water, afforestation, social welfare, etc.

### **(iii) Social Movements**

In the contemporary Indian context, a number of social movements, spearheaded by social movement organisations (SMOs) have emerged as major manifestations of civil society. These movements are of several types such as focusing on the interest and aspirations of particular groups - SCs, STs and women; protests against social evils like liquor, dowry, inheritance rights etc.; protests against displacement due to big development projects; campaigns against environmental degradation, corruption and for rights to information, education and livelihood.

### **(iv) Membership Associations**

Membership organisations may be representational – set up to represent the opinions and interest of a particular category of citizens e.g. unions of rural labour, farm workers, women workers, consumer associations etc., professional – formed around a particular occupation or profession e.g. association of lawyers, teachers, engineers, managers, journalists etc., social-cultural – organised around a social or cultural purposes e.g. Nehru Yuvak Kendras, clubs for sports, Natak Mandalis etc. and self-help groups – a growing category of membership organisations e.g. savings and credit groups etc.

### **(v) Intermediary Associations**

These associations function between individual citizens and macro state institutions like the bureaucracy, judiciary and police etc. These could be of several types, e.g. service delivery, mobilizational, support, philanthropic, advocacy and network.

1.7 Traditionally, NGOs are known as Voluntary Organisations (VOs) & Voluntary Agencies (VAs) and recently as Voluntary Development Organisations (VDOs) or Non-Governmental Development Organisations (NGDOs) or Non-Profit Institutions (NPIs). There are equivalent names for NGOs available in different Indian languages; like in Hindi NGOs are called Swayamsevi Sanstha or Swayamsevi Sangathan.

### **Definition of NPIs in the System of National Accounts**

1.8 The SNA distinguishes two broad types of economic entities: establishments, which are enterprises, or parts of enterprises, that perform a single production activity, generally at a single site; and institutional units, which are “capable, in their own right, of owning goods and assets, incurring liabilities, and engaging in economic activities and transactions with other units.”

“they Satellite Accounts: Satellite accounts provide a framework linked to the central accounts and which enables attention to be focused on a certain field or aspect of economic and social life in the context of national accounts; common examples are satellite accounts for the environment, or tourism, or unpaid household work, or Non-profit Institutions”

Institutional units may have one or a number of establishments.

1.9 Within that structure, NPIs form a class of institutional units. The SNA distinguishes NPIs from



other institutional units principally in terms of what happens to any profit that they might generate. In particular:

- 1.10 “Non-profit institutions are legal or social entities created for the purpose of producing goods and services whose status does not permit them to be a source of income, profit, or other financial gain for the units that establish, control or finance them. In practice their productive activities are bound to generate either surpluses or deficits but any surpluses they happen to make cannot be appropriated by other institutional units.” That basis for defining NPIs, which focuses on the common characteristic that they do not distribute their profits, is a central feature of most definitions of “the non-profit sector” in law and social science literature.
- 1.11 The SNA also distinguishes NPIs in terms of the kinds of services that they produce. The SNA notes that the reasons for establishing NPIs are varied. For example, “NPIs may be created to provide services for the benefits of the persons or corporations who control or finance them; or they may be created for charitable, philanthropic or welfare reasons to provide goods or services to other persons in need; or they may be intended to provide health or education services for a fee, but not for profit, ... etc.” While acknowledging that they may provide services to groups of persons or institutional units,” the SNA definition of NPIs stipulates that “by convention” NPIs “are deemed to produce only individual services and not collective services”.
- 1.12 Non-profit institutions, so defined, thus differ from the other three major types of institutional units defined within SNA, namely, corporations (financial and non-financial), government agencies and households, in the following:
- (a) Corporations differ from NPIs in that they are “set up for purposes of engaging in market production” and “are capable of generating a profit or other financial gain for their owners”;
  - (b) Government units differ from NPIs in that they are “unique kinds of legal entities established by political processes which have legislative, judicial or executive authority over other institutional units within a given area,” including “the authority to raise funds by collecting taxes or compulsory transfers from other institutional units.”
  - (c) A household differs from an NPI in that it is “a small group of persons who share the same living accommodations, who pool some or all of their income and wealth, and who consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food...”

### **Need for a satellite account on NPIs**

- 1.13 Although, the sector assignment of NPIs (namely NPISHs) makes sense for many analytical purposes, it makes it difficult to gain a comprehensive view of the entire universe of NPIs. As envisaged in the Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts<sup>3</sup>, gaining such a view is increasingly important, however, for a number of reasons. The main reasons are:
- (a) NPIs constitute a significant and growing economic presence in countries throughout the world, accounting for 7 to 10 per cent of non-agricultural employment in many developed countries and considerable shares of the employed labour force in developing countries as

---

<sup>3</sup> Extracts from the Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts, Department of Economic & Social Statistics Division, United Nations, 2003 are reproduced in Annexure I.





- well;
- (b) NPIs have distinct features that give them production functions and other characteristics that differ significantly from those of the other entities included in the corporate and government sectors to which they are assigned under current usage. Those features include:
    - (i) The prohibition on the distribution of profits from their operations, which gives them an objective function quite different from that of for-profit corporations;
    - (ii) Their involvement in the production of public goods in addition to whatever private goods they may produce;
    - (iii) A revenue structure that generally includes substantial voluntary contributions of time and money;
    - (iv) The use of volunteer as well as paid staff;
    - (v) Limited access to equity capital because of the prohibition on their distribution of profits;
    - (vi) Eligibility for special tax advantages in many countries.
    - (vii) Special legal provisions pertaining to governance, reporting requirements, political participation and related matters;
    - (viii) The lack of sovereign governmental powers despite their involvement in public goods provision;
  - (c) NPIs are increasingly a focus of policy attention as Governments seek to divert social functions to provide groups, which has increased the need for better information on NPIs;
  - (d) Existing treatment, by folding NPIs into other sectors, reduces the incentives to make the special efforts needed to capture NPIs fully in current data;
  - (e) Existing sectoring rules are hard to apply given the increasing complexity of the NPI universe. Considerable variation in treatment may consequently occur among countries.

1.14 The NPI satellite account departs from SNA conventions, where necessary, in order to add information that is important for depicting other key facets of the scope and operations of non-profit institutions.

#### **“Structural-Operational” definition of NPI**

1.15 As a first step in addressing the need for better information on NPIs, it is important to identify an appropriate definition of an NPI and of the NPI sector. Such a definition must be able to accommodate all entities currently embraced within the existing SNA definition of an NPI, while clarifying the differences between NPIs and both government and pure market producers. In addition, it must be neutral enough to accommodate the array of legal systems, patterns of financing, and types of purposes associated with NPI-type institutions in different national settings.

1.16 Within SNA, non-profit institutions (NPIs) form a class of institutional units. SNA distinguishes NPIs from other institutional units principally in terms of what happens to any profit that NPIs might generate. In particular:

“Non-profit institutions are legal or social entities created for the purpose of producing goods and services whose status does not permit them to be a source of income, profit or other financial gain for the units that establish, control or finance them. In practice, their productive activities are bound to generate either surpluses or deficits, but any surpluses they happen to make cannot be appropriated by other institutional units.”

1.17 That basis for defining NPIs, which focuses on the common characteristic that they do not distribute their profits, is a central feature of most definitions of the non-profit sector in law



and social science literature.

1.18 The NPI satellite account utilizes a mid-range concept of the non-profit institutions sector that uses components of the “structural-operational” definition used in the Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project to clarify the SNA definition, particularly with respect to the borders between NPIs and both corporations and governments. Three of the components of the structural-operational definition can provide the needed clarification:

- (i) In the first place, the “institutionally separate from government” criterion places additional emphasis on the non-governmental nature of NPIs, a crucial feature in most understandings of that set of institutions;
- (ii) In the second place, the “self-governing” criterion usefully distinguishes NPIs from organizations that are essentially controlled by other entities, whether government or corporations;
- (iii) Finally, the “non-compulsory” element of the “voluntary” criterion distinguishes NPIs from entities that people belong to by birth or legal necessity. That distinguishes NPIs from families, tribes and other similar entities, and represents another central feature of the common understanding of those organizations.

1.19 Thus, for the purpose of the NPI satellite account, the non-profit sector has been defined as consisting of: (a) Organizations that, (b) not-for-profit and, by law or custom, do not distribute any surplus they may generate to those who own or control them, (c) are institutionally separate from government, (d) are self-governing and (e) are non-compulsory. The details are as follows:

**(a) Organization** means that the entity has some institutional reality. Institutional reality can be signified by “some degree of internal organizational structure; persistence of goals, structure, and activities; meaningful organizational boundaries; or a legal charter of incorporations. Excluded are purely ad hoc and temporary gatherings of people with no real structure or organizational identity”. Specifically included, however, would be informal organizations that lack explicit legal standing but otherwise meet the criteria of being organizations with a meaningful degree of internal structure and permanence. This is consistent with the SNA definition of NPIs: “Most NPIs are legal entities created by process of law whose existence is recognized independently of the persons, corporations, or government units that establish, finance, control or manage them.” Those entities can take the legal form of associations foundations or corporations. “The purpose of the NPI is usually stated in the articles of association or similar document drawn up at the time of establishment.” In addition, however, an “NPI may be an informal entity whose existence is recognized by the society but which does not have any formal legal status”.

**(b) Not-for profit** means that NPIs are organizations that do not exist primarily to generate profits, either directly or indirectly, and that are not primarily guided by commercial goals and considerations. NPIs may accumulate surplus in a given year, but any such surplus must be plowed back into the basic mission of the agency and not distributed to the organizations; owners, members, founders or governing board. This is consistent with the SNA definition of an NPI, which acknowledges that, in practice, NPIs’ “productive activities are bound to generate either surpluses or deficits but any surpluses they happen to make cannot be appropriated by other institutional units”. The SNA goes on to note that “The term ‘non-profit institution; derives from the fact that the member....are not permitted to gain financially from its operations and cannot appropriate any surplus which it may make. It does not imply than an NPI cannot make an operating surplus on its



production”. In that sense, NPIs may be profit-making but they are non-profit distributing, which differentiates NPIs from for-profit businesses. Where excessive salaries or perquisites make it appear that organizations are evading the “nondistribution constraint”, grounds exist for treating the organization as a for-profit corporations. National laws usually make provision for disqualification from non-profit status on those grounds, although the implementation of such laws is frequently imperfect. The laws and regulations of some countries add restrictions to the use of the organization’s income in addition to surplus.

**(c) Institutionally separate** from government means that the organization is not part of the apparatus of government and does not exercise governmental authority in its own right. The organization may receive significant financial support from government and it may have public officials on its board; however, it has significant discretion with regard to the management of both its production and its use of funds that its operating and financing activities cannot be fully integrated with government finances in practice. “What is important from the point of view of this criterion is that the organization has an institutional identity separate from that of the state, that it is not an instrumentality of any unit of government, whether national or local, and that it therefore does not exercise governmental authority:. That means that an organization may exercise the authority that has been delegated to it by the state or administer a set of rules determined by the state, but it has no sovereign authority on its own. Thus, for example, a trade association might be given authority to set and even to enforce industry standards, but that authority could be withdrawn if misused or no longer necessary. Along different lines, an NPI might be empowered to distribute government subsidies, grants or contracts to individuals or other organizations, but within a given set of regulations determined by government. In those cases, the institution is still considered an NPI.

**(d) Self-governing** means that the organization is able to control its own activities and is not under the effective control of any other entity. To be sure, no organization is wholly independent. To be considered self-governing, however, the organization must control its management and operations to a significant extent, have its own internal governance procedures and enjoy a meaningful degree of autonomy. The emphasis here is not on the origins of the organization, i.e., what institution “created” it; or on the degree of government regulation of its activities or on the dominant source of its income. The emphasis is instead place on the organization’s governance capacity and structure. In particular:

- Is the organization generally in charge of its own “destiny” ie., can it dissolve itself, set and change its by-laws and alter its mission or internal structure without having to secure permission from any other authority than the normal registration officials? If yes, then the organization is an NPI.
- If government or corporate representatives sit on the governing body of the organization, do they exercise veto power, and if so do they serve in their official capacities or as private citizens? If the representatives serve in an official capacity and have veto power, the organization is not considered self-governing. The presence of government or corporate representatives on the board of a nonprofit organization does not, therefore, disqualify the organization. The question is the degree of authority they wield and the degree of autonomy the organization retains. That means that a corporate foundation tightly controlled by its parent corporation should be excluded. However, a corporate foundation that controls its own



activities and is not subject to the day-to-day control of its affiliated corporation could be included;

- Do governments or corporate entities select the executive director of the organization or is the executive director a government or corporate official? If either is true, the organization is probably not an NPI.

Of course, the self-governing criterion should be applied with care and should not disqualify NPIs in countries with less-democratic governance structures in which the state may close down organizations that oppose it.

**(e) Non-compulsory** means that membership and contributions of time and money are not required or enforced by law or otherwise made a condition of citizenship. As noted above, non-profit organizations can perform regulatory functions that make membership in them necessary in order to practice a profession (e.g., bar associations that license lawyers to practice law), but as long as membership- is not a condition of citizenship, as opposed to a condition of practicing a chosen profession, the organization can still be considered noncompulsory. By contrast, organizations in which membership, participation or support is required or otherwise stipulated by law or determined by birth (i.e., tribes or clans) would be excluded from the non-profit sector.

1.20 The “non-profit sector” as defined above includes NPIs that meet those five basic criteria, regardless of the sector to which the SNA assigns them. Included, therefore, are NPIs that may be market producers and that sell any part of their products or services at an economically significant price; they would be found in either the non-financial corporations sector or the financial corporations sector of the SNA, depending on their principal activity. Also included are entities within the general government sector of the SNA, should also be included.

1.21 The non-profit sector so defined includes NPIs that meet those five basic criteria regardless of the sector to which SNA assigns them. Included, therefore, are NPIs that may be market producers and that sell any part of their products or services at an economically significant prices; they would be found in either the non-financial corporations sector or the financial corporations sector of SNA, depending on their principal activity. Also included are entities within the general government sector of the SNA that are selfgoverning and institutionally separate from government, even if they are mainly financed by government and may have public appointees on their boards. Finally, NPIs that receive the bulk of their income from households, which would be found in either the households of NPISH sectors of SNA should also be included. Within the satellite account, therefore, we can show both the NPI and non-NPI components of the SNA sectors as well as a separate nonprofit sector.

**Table 2.1: Treatment of NPI in the NPI satellite account**

Type of institutional unit	SNA sectors					
	Non-financial corporations sector S.11	Financial corporations sector S.12	Central government sector S.13	Households sector S.14	NPISH sector S.15	Nonprofit sector



<b>Corporation Government Units Households</b>	C1	C2	G	H		
<b>Non-profit institution</b>	N1	N2	N3	N4	N5	N= N1to5



1.22 Thus, by applying the SNA sectoring rules to the institutional units identified as NPIs by the working definition, it is possible to define sub sectors for the NPI and non-NPI components of the SNA sectors other than NPISH non-financial corporations, financial corporations, general government and households.

### **Classifications**

1.23 SNA identified two basis for classifying NPIs-one according to the economic activity in which they engage and the other in terms of their function or purpose:

- The economic activity classification is the more general one. NPIs are essentially classified into industries on the basis of the chief or characteristic product that they produce using the same classification scheme that is applied to economic activities generally in SNA-i.e., the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 3 (ISIC, Rev.3). ISIC is designed to be a classification for production statistics. The unit to which it is applied the establishment, is intended to be the smallest unit from which it is possible to collect information on outputs, inputs and the processes by which inputs are transformed into the outputs.
- The purpose classification is more specific and relates to the “objectives that institutional units aim to achieve through various kinds of outlays” (United Nation, 2000). A particular economic activity can serve any of a number of objectives. A special classification system-the Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI), has been designed for nonprofit institutions, at least for those serving households.

1.24 Neither of those classification schemes alone can serve as the primary classification for the broad non-profit sector defined above. ISIC, Rev. 3, has very limited detail on the service industries-particularly the services that NPIs typically provide. In addition, there are potentially some problems with the SNA purpose classification used for non-profits. That classification, the Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI) is applicable only to NPISH and may be inappropriate for classifying the purpose of NPI activity outside that sector.

1.25 To address those problems, the present Handbook uses a classification system built fundamentally on ISIC as the primary classification scheme to detail the NPI sector in the satellite account when the focus of the analysis or data presentation is chiefly or exclusively the NPI sector. That elaborated classification, the International Classification of Non-Profit Organizations (ICNPO), was originally developed through a collaborative process involving the team of scholars working on the Johns Hopkins Comparative Non-Profit Sector Project'. ICNPO has been used successfully to collect and structure data in a broad cross-section of countries that vary by level of economic development; by political, cultural and legal system; and by size, scope and role of their nonprofit sector. In the process, refinements have been made in the basic scheme. The revised version was further tested by 11 countries that participated in a field test of the present Handbook and was found to work. Based on those experiences, it is possible to conclude that ICNPO effectively accommodates the major differences among non-profit group in a wide assortment of countries. By and large, ICNPO neither excludes nor misrepresents crucial subdivisions of the non-profit sector in various countries. ICNPO is presented at annexure II.



## **Extension of the Production boundary**

- 1.26 Although the NPI satellite account presents data on NPIs that are fully comparable with SNA, it also takes advantage of the flexibility of satellite accounting to extend the production boundary to include the non-market output of market NPIs and the output attribute to inputs of volunteer labour. The presentation of measures incorporating those boundaries is discussed below in the sector on the tables and their entries.
- 1.27 **Non-market output of market NPIs:** In the SNA, the source of financing matters considerably in the valuation of output, which creates a problem in valuing the output of which the SNA considers market NPIs, i.e., those that cover the preponderance of their operating expenses from market sales. Although the market output of such NPIs is counted, any non-market output they produce is not counted under SNA conventions. Yet such nonmarket output can be significant because such NPIs also produce output supported by charitable contributions or other transfers that do not show up in sales revenue.
- 1.28 **Volunteer labour:** As noted above, SNA does not count most volunteer effort. However, volunteer labour constitutes a significant input to many, if not most, non-profit organizations. In many such organizations, the voluntary contribution of time exceeds in value the voluntary contribution of money. Although people volunteer for other organizations, such as government agencies and even business, most voluntary work takes place in non-profit organizations.
- 1.29 Because volunteer labour is so critical to the output of the NPIs that employ it and to their ability, to produce the level and quality of services that they provide, it is important to capture that activity in the NPI satellite account. Doing so will give a more complete picture of service actually produced and consumed in the economy and in particular fields. The inclusion of volunteer labour input also permits more accurate comparisons of input structure and cost structure between NPI producers and those in other sectors.

## **Volunteerism through NPIs in India**

- 1.30 Volunteerism is an integral part of all communities. Its expression, definition and understanding vary according to history, politics, religion and culture. What may be seen as volunteering in one country may be treated as low paid or labor intensive work in another. However, despite the wide variety of volunteerism expressions, it is possible to identify some core characteristics.
- 1.31 The most obvious question raised is “Why does volunteerism matter?”Volunteering is a means for social inclusion and integration, and a powerful resource for reconciliation in divided communities. It can contribute to a cohesive society by creating bonds of trust and solidarity and, thus, social capital. Volunteerism can create opportunities for different people to contribute to positive change regardless of their nationalities, religions, socioeconomic backgrounds or age.
- 1.32 Through volunteering, people can gain and exercise skills such as leadership, communication and organization skills, and extend their social networks. It can provide informal learning opportunities and can be therefore a crucial instrument for continuous personal development.
- 1.33 On the other hand, the economic value and share of volunteering as “economic” activity in the Gross Domestic Product is significant and needs to be clearly identified in National Statistical



Accounts<sup>4</sup>. Moreover, corporate social responsibility (CSR) is a powerful tool for promoting local development and better access to services and service delivery.

### **The legal framework for registering Non-profit institutions in India**

- 1.34 Prior to the enactment of the Societies Registration Act of 1860, voluntary action was guided mainly by religious and cultural ethos. Subsequently, a series of legislations addressing the non-profit sector were adopted. The starting point in this respect was Article 19 of the Indian Constitution which recognized a number of civic rights including the right “...to form associations or unions”. It constitutes the legal basis of relevant legal provisions applicable to the non-profit sector. There are also non mandatory provisions that allow any group with the intention of starting a non-profit, voluntary or charitable work to organize itself into a legally registered entity. However, given the optional nature of these provisions, there is a large group of voluntary bodies which are not registered.
- 1.35 The non profit institutions in India can be registered as **societies, Trusts, Religious Endowments and Waqfs**, or a **private limited non profit companies** under section-25 companies of Indian Companies Act, 1956<sup>5</sup>. The brief description of the laws for registering these are given below.

#### **Societies**

##### **Societies Registration Act, 1860**

- 1.36 The following societies can be registered under Societies Registration Act 1860, namely, Charitable societies; Military orphan funds or societies; Societies established for promotion of science, literature, or for fine arts; Societies established for instruction and diffusion of useful knowledge; diffusion of political education; Societies established for maintenance of libraries or reading rooms for general public; Societies established for Public museums and galleries for paintings or other works of art; and collections of natural history, mechanical & philosophical inventions, instruments or designs [section 20]. Any seven or more persons associated for literary, scientific or charitable purpose can register a society by subscribing their names to memorandum of association.
- 1.37 Purpose of the Act is to provide for registration of literary, scientific and charitable societies. Societies Registration Act is a Federal Act. However, ‘unincorporated literary, scientific, religious and other societies and associations’ is a State Subject (Entry 32 of List II of Seventh Schedule to Constitution, i.e. State List). Thus, normally, there should have been only State Laws on this subject. However, Societies Registration Act was passed in 1860, i.e. much before bifurcation of power between State and Centre was specified. Though the Act is still in force, it has been specifically repealed in many States and those States have their own Acts. In certain states, which have a charity commissioner, the society must not only be registered under the Societies Registration Act, but also, additionally, under the Bombay Public Trusts Act.

#### **Trusts, Religious Endowments and Wakfs**

- 1.38 Trust is a special form of organisation which emerges out of a will. The will maker exclusively transfers the ownership of a property to be used for a particular purpose. If the purpose is to

---

<sup>4</sup> The UNV/John Hopkins University initiative for profiling volunteerism in the system of national accounts in India with the framework of the UN Handbook on Non-profit institutions.

<sup>5</sup> “Social Capital”, 9th Report, Second Administrative Reforms Commission, Government of India, August 2008





- benefit particular individuals, it becomes a Private Trust and if it concerns some purpose of the common public or the community at large, it is called a Public Trust. Religious Endowments and Wakfs are variants of Trusts which are formed for specific religious purposes e.g. for providing support functions relating to the deity, charity and religion amongst Hindus and Muslims respectively. Unlike Public Trusts, they may not necessarily originate from formal registration, nor do they specifically emphasize on a triangular relationship among the donor, Trustee and the beneficiary. Religious endowments arise from dedication of property for religious purposes. The corresponding action among the Muslim community leads to the creation of Wakfs. The Indian Trusts Act, 1882
- 1.39 This is the first law on Trusts which came into force in India in 1882 known as the Indian Trusts Act, 1882; it was basically for management of Private Trusts. Trust and trustees is a concurrent subject [Entry 10 of List III of Seventh Schedule to Constitution]. Different states in India have different Trusts Acts in force, which govern the trusts in the state; in the absence of a Trusts Act in any particular state or territory the general principles of the Indian Trusts Act 1882 are applied. Public Trust Act, 1950
- 1.40 Public Trust means an express or constructive trust for either public or charitable purpose or both and includes a temple, a math, a wakf, church, synagogue, agiary or any other religious or charitable endowment and a society formed either for religious or charitable purpose or both and registered under the Societies Registration Act, 1860.
- 1.41 In order to be a public trust, it is not essential that the trust should benefit the whole of mankind or all the persons living in a particular state or city. It is said to be a public trust if it benefits a sufficiently large section of the public as distinguished from specified individuals. Also if the beneficiaries of the trust are uncertain or fluctuating, then the fact that the beneficiaries belong to a certain religion/caste does not make any difference.
- 1.42 The first legislation on this subject was enacted by the then State of Bombay in 1950. Known as the Bombay Public Trusts Act, 1950, it was meant to deal with an express or constructive Trust for either public, religious or charitable purposes or both and included a temple, a math, a Wakf, or any other religious or charitable endowment and a Society formed either for a religious or a charitable purpose or for both and registered under the Societies Registration Act, 1860 – Section 2(13). The Charitable and Religious Trust Act, 1920
- 1.43 This is an Act to provide more effectual control over the administration of Charitable and Religious Trusts. It recognizes the existence of religious bodies as entities different from Endowment Trusts formed for social and charitable purposes. Trustees of such bodies were made accountable for disclosure of the income and the values of the Trust. Civil courts were given proactive powers with regard to management of the property. But any direct intervention of the government through its own functionaries viz. Deputy Commissioners/ Collectors and other officials was not allowed.
- 1.44 The scenario changed after 1947. With a view to preventing abuse of funds and to ensure uniform organisational framework for the management of such religious and charitable institutions, many State Governments enacted their own Endowments Acts and virtually took over their management installing government officials as Trustees and managers. The examples are the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951; the Travancore-Cochin Hindu Religious Institutions Act 1950; the Bodh Gaya Temple Act, 1949, the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions and Endowments Act,



- 1966; and the Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997.
- 1.45 Wakf implies the endowment of property, moveable or immovable, tangible or intangible to God by a Muslim, under the premise that the transfer will benefit the needy. As a legal transaction, the Waqif (settler) appoints himself or another trustworthy person as Mutawalli (manager) in an endowment deed (Waqfnamah) to administer the Wakf (charitable Trust).
- 1.46 There are several important legislations enacted on the subject between 1913 and 1995 such as Mussalman Wakf Act 1923, Central Wakf Act, 1954, The Wakf Act, 1995, etc.
- 1.47 The Wakf Act, 1995 is applicable throughout the country except for Jammu and Kashmir and Dargah Khwaja Saheb, Ajmer. The management structure under the Act consists of a Waqf Board as an apex body in each State. Every Wakf Board is a quasi-judicial body empowered to rule over Wakf-related disputes. At the national level, there is Central Wakf Council which acts in an advisory capacity.

#### **Private Limited Non Profit Companies under Section 25 of The Indian Companies Act, 1956**

- 1.48 Section 25 of the Companies Act, 1956 provides for a mechanism through which an Association can be registered as a Company with a limited liability, if such association is formed for promoting commerce, art, science, religion or any other useful object provided the profits, if any, or other income is applied for promoting only the objects of the company and no dividend is paid to its members. The objective of this provision is to provide corporate personality to such Associations but at the same time exempting them from some of the cumbersome legal requirements.

#### **Pilot Survey on NPISHs by National Sample Survey Organisation**

- 1.49 Though several attempts were made to get information on NPIs in the past, no such attempt was made to get data on NPISH's separately. An independent estimate of private final consumption expenditure is not separately available for NPISH and other important aggregates required to prepare separate accounts could not be compiled for this sector. The National Statistical Commission, in its report recommended that periodic surveys/type studies may be conducted to collect data on income and expenditure of NPISH's. The commission also recommended for preparation of a list frame for NPISHs.
- 1.50 Considering this growing need of data on NPISH's, the NSSO conducted a pilot survey of NPISH's during July-December 2004 in 11 districts in 6 States of India to understand the magnitude and problems of conducting a full fledged nationwide survey on NPISHs. A Working Group was formed to prepare the modalities of the survey procedures and instruments, laying particular stress on the methods of identifying the NPISH's among the NPI's. The Working Group while formulating survey methodology for the pilot survey, analysed the data of NSSO 57th round and pre-tested the proposed schedule of enquiry. On the basis of recommendations of the Working Group, the pilot survey was launched and the field-work was taken up during July – December 2004.
- 1.51 NPI's engaged mainly in non-market production and providing nonmarket goods and services to households, financed mainly by transfers from non-governmental sources - households, corporations or non-residents, are described as "NPI's serving households" (NPISH's) and treated as constituting the specific fifth institutional sector in the System of National Accounts (SNA).
- 1.52 In view of constraints of resources, the sample size of the Pilot Survey was kept small. A dual frame approach was adopted in the survey with a view to improving the reliability of the



overall estimates by considering apparently large units into one frame (list frame) and covering the entire gamut of remaining smaller units through the area frame. The list frame was constructed mainly from the frames maintained by FCRA division of Ministry of Home Affairs. The largest source of NPIs viz. those registered under the Societies Registration Act, 1860 could not be considered for preparation of the list frame because of the manually maintained list thereby curtailing the use of list frame in estimating the aggregate value addition. In the area frame, the sampling design was stratified multi-stage. Villages and UFS blocks were fsu's in rural and urban areas, respectively.

1.53 Two districts of a State in each FOD Zone were selected for the survey. The districts selected were Cachar and Kamrup (Assam), Delhi (Delhi Statutory Town), Indore and Jabalpur (Madhya Pradesh), Mumbai and Nagpur (Maharashtra), Trichur and Kannur (Kerala) and Kolkata and Medinipur (West Bengal).

Annexure-II

\*\*\*\*\*

**Government of India**  
**Ministry of Statistics and Programme Implementation**  
**Central Statistical Organization**  
**National Accounts Division**

Please read the instructions before filling up this

Running serial number of schedule

--	--	--	--	--	--	--	--

**IDENTIFICATION SCHEDULE 2.0: I**

All items must be filled in capital letters

(0)	descriptive identification of surveyed institute		
item no	item	description and code	
1	state /ut name and code  (to be printed on each schedule by state DES)		
2	location of registering office		
3	name of society		



4	registration no.													
5	year of registration													
6	location code of the society (rural-1, urban-2)													
7.1	complete address of society	house no.												
7.2		street / colony/ward												
7.3		city / village												
7.4		block /taluk												
7.5		district name and code												
7.6		PIN code												
8.1	telephone no. with STD code of society	STD code					telephone no.							
							-							
8.2	telephone no. of key contact person						-							
9	act under which society is registered (code) (societies registration act 1860-1, public trust act-2, both-3)													
10	activity / purpose and code		activity/purpose								code			
10.1	(maximum three main activities or purpose; item 'i' will be the major activity)	i												
10.2		ii												
10.3		iii												
11	serving which institution/sector govt - code 1, industries - code 2, household - code 3		code											
12	number of governing body members	12.1 male					12.2 female							
		12.3 total												
13	date of collection of information		d	d	m	m	y	y	y	y				
14	name & designation of informant/key contact person													
<b>codes for item 10:</b> culture and recreation-01, education and research-02, health-03, social services-04, environment-05, development and housing-06, law, advocacy and politics -07, philanthropic intermediaries & voluntarism promotion-08, international activities-09, religion-10, business and professional associations, unions-11, not elsewhere classified-12.														



<b>Details may be seen on page ii.</b>			
15	<b>accounting status</b>	code	specify code
	accounts are prepared and available	1	
	accounts prepared but not available/audited	2	
	accounts are not maintained	3	
<b>If accounting status is code 1: data may be collected in schedule 2.0: D - Detailed Data Schedule</b>			
<b>If accounting status is code 2 or 3: data may be collected in schedule 2.0: K - Key Data Schedule</b>			

## **Item 10 : Details of activities and codes**

### **culture and recreation** code 01

includes theaters, museums, zoos, aquariums, performing arts, historical and cultural societies sports clubs, social clubs, service clubs like the Lions, Rotary etc.

### **education and research** code 02

includes primary, elementary and secondary schools, higher education, vocational schools, adult and continuing education, research institutes.

### **health** code 03

includes hospitals, rehabilitation, nursing homes, mental health institutions, preventive health care, emergency medical services, volunteer ambulances.

### **social services** code 04

includes child welfare services, day care, youth welfare, family welfare, services for the handicapped, services for the elderly, assistance to refugees and homeless people, shelters, food distribution.

### **environment** code 05

includes environmental protection, conservation, cleanup and beautification, animal and wildlife protection, and veterinary services.

### **development and housing** code 06

includes community and neighborhood organizations, domestic economic and social development activities, housing associations and housing assistance

### **law, advocacy and politics** code 07

includes civic associations, civil liberty groups, human rights organizations, advocacy organizations, legal services, crime prevention and rehabilitation of offenders, consumer protection.

**philanthropic intermediaries & voluntarism promotion** code 08

includes foundations, volunteer bureaus, fund-raising organizations.

**international activities** code 09

includes exchange, friendship and cultural programs, international disaster and relief, international human rights and peace promotion, development assistance and aid.

**religion** code 10

includes churches, synagogues, mosques and other places of worship

**business and professional associations, unions** code 11

includes associations among businesses, business people, professionals, and unions

**not elsewhere classified** [please specify] .....code12.....

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DETAILED DATA SCHEDULE 2.0: D</b>
--------------------------------------

(1)	employment particulars of the society (as on date)		d	d	m	m	y	y	y	y
			male	female		total				
1	number of volunteers (including governing body members)	1.1 with honorarium								
		1.2 without honorarium								
		1.3 total								
2	number of employed persons	2.1 full time								
		2.2 part time								
		2.3 total								
3	total	3.1 total (1.3 + 2.3)								
		3.2 of which specialists, namely:								
		3.2.1 doctors								
		3.2.2 teachers								
		3.2.3 advocates								

(2)	financial information (in Rs.) about the society for the reference period (April 2007-March 2008) or for the period for which accounts are available (mention the period) _____ - _____ (yyyy- yy)			
1	income/receipts		amount (Rs.)	source of data
1.1	capital grants from	1.1.1 government bodies		Balance Sheet liabilities side Receipts & Payments account
		1.1.2 foreign bodies		Balance Sheet liabilities side Receipts & Payments account



--	--	--	--	--	--	--

		1.1.3 others		Balance Sheet liabilities side	Receipts & Payments account
1.2	current grants from	1.2.1 government bodies		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
		1.2.2 foreign bodies		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
		1.2.3 others		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
1.3	subsidies			Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
1.4	membership subscription			Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
1.5	donations and offerings			Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
1.6	value of goods and material received in kind			Income & Expenditure account	Oral enquiry
1.7	value of stock of goods	closing stock		Balance Sheet	Income & Expenditure account
1.8		opening stock			
1.9	income/receipts from operations (sale of goods and service produced by institution)			Income & Expenditure account	Receipts & Payments account

1.10	<b>income from investments/rent</b>	amount (Rs.)	source of data
------	-------------------------------------	--------------	----------------

--	--	--	--	--	--	--

1.10.1	interest, dividend, etc.		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
1.10.2	rent of buildings, land park, etc.		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
1.11	other incomes/receipts n.e.c.		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
	<b>total income/receipts</b> <b>[sum(1.2 to 1.7) – 1.8 + sum(1.9 to 1.11)]</b>			

2	<b>expenditure</b>	amount (Rs.)	source of data	
2.1	salary, wages and allowances (incl. PF, gratuity and welfare expenditure etc.)		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.2	honorarium paid		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.3	interest paid		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.4	rent paid		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.5	other operating expenses (goods and services purchased for current activities of institution)		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.6	grants given to other institutions		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.7	value of goods given free		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
2.8	provision for depreciation		Income & Expenditure	

Running serial number of schedule

--	--	--	--	--	--	--

				account	
2.9	taxes paid	2.9.1 indirect (service tax, vat, sales tax etc. )		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
		2.9.2 direct (income/ corporate tax /cess on income)		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
	<b>total expenditure - current (2.1 to 2.9)</b>				

3	investment in physical assets	amount (Rs.)		source of data	
		additions during the year	closing balance		
3.1	land			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.2	buildings			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.3	other construction and land development			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.4	plantation and garden development			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.5	machinery and equipments			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.6	transport equipment			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.7	other office equipment			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
3.8	other physical assets n.e.c.			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account

--	--	--	--	--	--	--

3.9	valuables			Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
	<b>total (3.1 to 3.9)</b>				
4	<b>investment in financial assets</b> (change during the accounting year)	amount (Rs.)	source of data		
4.1	government securities		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	
4.2	public sector securities		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	
4.3	private sector shares and debentures		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	
4.4	investment in bank fixed deposits		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	
4.5	other investments n.e.c.		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	
5	<b>cash in hand</b>		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	
6	<b>bank balance</b>		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account	

7	<b>other balance sheet items</b> (change during the accounting year)	amount (Rs.)			
7.1	funds (excluding item 7.4 and 7.7)		Balance sheet liabilities side		
7.2	loans and advances (received)		Balance sheet liabilities side		
7.3	other financial liabilities n.e.c.		Balance sheet liabilities side		

Running serial number of schedule

--	--	--	--	--	--	--

7.4	excess of income over expenditure		Balance sheet liabilities side
7.5	loans and advances (given)		Balance sheet assets side
7.6	other financial assets n.e.c.		Balance sheet assets side
7.7	excess of expenditure over income		Balance sheet assets side
8	<b>total funds (closing balance)</b>		Balance sheet liabilities side

<b>(3) remarks by investigator</b>			
name of person canvassing the schedule		telephone number	
remarks			
date of collecting information		signature	

<b>(4) remarks by supervisory officer</b>			
name of supervisory officer		telephone number	
remarks			
date of collecting information		signature	

## KEY DATA SCHEDULE 2.0: K

(1)	employment particulars of the society (as on date)	d	d	m	m	y	y	y	y
		total		male		female			
1	number of volunteers (including governing body members)								
2	number of employed persons								
3	total (1+ 2)								

(2)	financial information (in Rs.) about the society for the reference period (April 2007-March 2008) or for the period for which accounts are available (mention the period) _____ - _____ (yyyy-yy)			
	financial information	amount (Rs.)	source of data	
1	total funds (at the end of the financial year)		Balance Sheet liabilities side	
2	total fixed assets (at the end of the financial year)		Balance Sheet assets side	
expenditure during the reference period				
3	total expenditure including expenditure on purchase of fixed assets		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
<i>of which expenditure on</i>				
3.1	salary, wages and allowances (incl. PF, gratuity and welfare expenditure etc.)		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
3.2	honorarium		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
3.3	purchase of fixed assets		Balance Sheet assets side	Receipts & Payments account
income during the reference period				
4	total income including grants received for purchase/acquisition of fixed assets			Receipts & Payments account
<i>of which</i>				
4.1	total grants received including grants			Receipts &

--	--	--	--	--	--	--

	received for purchase/acquisition of fixed assets			Payments account
4.2	membership subscription		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
4.3	donations and offering		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
4.4	income received from operations (sale of goods and services)		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account
4.5	other incomes including income from interest and dividend, rent etc.		Income & Expenditure account	Receipts & Payments account

<b>(3) remarks by investigator</b>		<b>(4) remarks by supervisory officer</b>	
name		name	
remarks		remarks	
date	sign	date	sign
telephone number		telephone number	

<b>Annexure-III</b>
---------------------

**Government of India**

**Ministry of Statistics and Programme Implementation**

**Central Statistical Organisation**

**National Accounts Division**

**Compilation of Satellite Accounts in respect of Non-Profit Institutions in India**

**- Instructions for collection of data in Second Phase**

--	--	--	--	--	--	--

1. For collection of employment and financial parameters of the societies, one of the schedules **Detailed Data Schedule 2.0: D** or **Key Data Schedule 2.0: K** may be used. Schedule 2.0: D is to be used in case of those societies where accounts are prepared and are available whereas, Schedule 2.0: K may be used in case of those societies where accounts are prepared but not available or accounts are not maintained. However for identification particulars of societies, **Identification Schedule 2.0: I** is to be filled for all societies.

2. **Running serial number of schedule** is the same as that filled in the first phase of the NPI survey and will be used as a key to identify the society listed in the first phase. This is to be filled in the space provided on top of every page of Schedule 2.0: I, Schedule 2.0: D and Schedule 2.0: K.

### Instructions for filling information in Identification Schedule 2.0: I

3. **Schedule 2.0: I** contains Block 0: descriptive identification of surveyed institute. In block 0, items are to be filled in **capital letters** clearly without overwriting. The items of block 0 are same as in Schedule 1.0 of the first phase except items 8.2, 10, 11, 14 and 15, which are described below. In this block, all items may be re-filled correctly based on actual visit to the society.

- i) **Item 8.2: telephone no. of key contact person:** In this item, telephone number of a member of the institution, who can answer further queries if any, is to be recorded. Separate boxes have been provided for writing the STD code and telephone number of the key contact person in the institution. For example, 011-23345096 is to be written as

		0	1	1	-	2	3	3	4	5	0	9	6
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ii) **Items 10: activity/purpose and code:** Here the main activity of the society is to be decided based on the information given by the key informant of the society. A total of three such activities can be given in case multiple activities are undertaken by the society, in terms of the codes listed at the bottom of the block 0. Amongst these, the activity on which maximum expenditure has been incurred or maximum number of volunteers/workers is engaged in the reference year will come as activity 'i' then 'ii' and 'iii'.

- iii) **Item 11: serving which institutions/sectors:** govt-code 1, industries-code 2, household-code 3: Criteria for classification of societies into above three categories:

- a. The societies which are **mainly financing** their activities through government aid/grants may be classified as 'societies serving government' and code 1 may be given.



--	--	--	--	--	--	--

- b. The societies created by farmers, manufacturers, traders, professionals like doctors, lawyers, auditors, etc. **for the benefit of their respective businesses/industries** may be classified as 'societies serving industries'. They consist of chamber of commerce, trade associations, market associations, market federations, etc. and code 2 may be given.
- c. The 'societies serving households' consist of societies which **provide or sell goods or services to households and are not mainly financed by government**. These societies may include religious societies, social, cultural, recreational and sports clubs, trade unions, labour unions, consumers associations, resident welfare associations, parents teachers associations. These also include charities, relief and aid organizations financed by voluntary donations and offerings, in cash or in kind. Code 3 may be given to these societies.

*Only one of the three codes should be given depending upon the above-mentioned criteria.*

- iv) **Item 14: name & designation of informant/key contact person** is to be given in the space provided.
- v) **Item 15: Accounting status:** Societies may or may not be maintaining the financial statements in a standardized format. Accordingly the investigator may ascertain whether:
- a. accounts are prepared and available: Code 1
- b. accounts prepared but not available/audited: Code 2
- c. accounts are not maintained: Code 3

The code of accounting status is to be specified in the given box.

Note that:

**If accounting status is code 1: data may be collected in schedule 2.0: D - Detailed Data Schedule and if accounting status is code 2 or 3: data may be collected in schedule 2.0: K - Key Data Schedule**

#### **Instructions for filling information in Detailed Data Schedule 2.0: D: Employment and Financial Parameters of Societies**

4. Schedule 2.0: D contains the following blocks:
- Block 1: employment particulars of the society (as on date)
- Block 2: financial information (in Rs.) about the society
- Block 3: remarks by investigator
- Block 4: remarks by supervisory officer

--	--	--	--	--	--	--

5. **Items of Block 1:** Block 1 contains employment particulars of the society as on the date of collection of data and not in respect of reference year of the survey.

employment particulars of society			Description
1	number of volunteers (including governing body members)	1.1 with honorarium	Number of volunteers receiving honorarium, segregated into number of males and females, maybe recorded.
		1.2 without honorarium	Number of volunteers not receiving any honorarium, segregated into number of males and females, maybe recorded.
		1.3 total	Total (1.1 and 1.2)
2	number of employed persons	2.1 full time	Total number of persons employed i.e. receiving salaries/wages. Against this, first fill the last row i.e. 'total', then segregate into males and females, and if possible, further segregate into full time or part-time workers. In this respect, the information given by the informer may be treated as correct and need not be verified from records.
		2.2 part time	
		2.3 total	
3	total	3.1 total (1.3+2.3)	Total of persons working as volunteers or as employees.
		3.2 of which specialists, namely:	Item 3.1 is to be segregated into the following 3 categories of specialists, if available:
		3.2.1 doctors	Volunteers or employed worker providing medical services to the society
		3.2.2 teachers	Volunteers or employed worker providing teaching services to the society
		3.2.3 advocates	Volunteers or employed worker providing legal services to the society

6. **Items of Block 2:** Block 2 contains financial information about the society. Brief description of items 1 to 8 is given below. **Financial data in this block is to be given in rupees.**

**Reference period of the survey** is April 2007-March 2008. In case the financial information is not available for this year then this information may be collected for the latest year.

--	--	--	--	--	--	--

The data pertaining to income/receipts, expenditure and investment is to be collected from audited/unaudited financial statements of societies. The source of data for each item is specified in the schedule, priority may be given to the first data source mentioned against each item.

1	income/receipts		Description
1.1	capital grants from	1.1.1 government bodies	Financial aid that is received by an institution for acquisition of capital assets such as buildings, land, machinery and equipment etc.  The source of the grant i.e. government bodies, foreign bodies and others is to be identified and accordingly filled in the desired row.
		1.1.2 foreign bodies	
		1.1.3 others	
1.2	current grants from	1.2.1 government bodies	Financial aid that is received by an institution for meeting their current expenditure such as salaries, consumables etc.  The source of the grant i.e. government bodies, foreign bodies and others is to be identified and accordingly filled in the desired row.
		1.2.2 foreign bodies	
		1.2.3 others	
1.3	subsidies		Aid received from government, by an institution on the basis of per unit of goods or services produced maybe shown here. Subsidy should be taken only if it is clearly mentioned in the accounts.
1.4	membership subscription		As available in Income & Expenditure accounts.
1.5	donations and offerings		As available in Income & Expenditure accounts.
1.6	value of goods and material received in kind		As available in Income & Expenditure accounts.
1.7	value of stock of goods	closing stock	Closing stock of goods and opening stock of goods is to be filled up from either the Balance sheet or Income & Expenditure account.
1.8		opening stock	
1.9	income/receipts from operations (sale of goods and service produced by institution)		This item should include the income on account of goods or services provided by the institutions to others, such as sale of books or periodicals, medicines, food items, investigation charges, fees, registration charges, hostel charges, guest house charges, hall booking charges, theatre charges etc.
1.10	<b>income from investments/rent</b>		

--	--	--	--	--	--	--

1.10.1	interest, dividend, etc.	Receipts of income from financial investments in the form of interests, dividends etc. to be recorded here.
1.10.2	rent of buildings, land park, etc.	Receipt of income from rent of buildings, land, etc is to be recorded here.
1.11	other incomes/receipts n.e.c.	Any other items of income not elsewhere classified (n.e.c.) may be recorded here.
	<b>total income/receipts</b>	This item may be calculated as <b>[sum(1.2 to 1.7) – 1.8 + sum(1.9 to 1.11)]</b>

2	expenditure	Description
2.1	salary, wages and allowances (incl. PF, gratuity and welfare expenditure etc.)	Any emolument paid in cash or kind to the employed persons in lieu of services rendered to the society including any contribution made by society on behalf of employee, such as insurance, gratuities and provident fund, etc.
2.2	honorarium paid	As available in Income & Expenditure accounts.
2.3	interest paid	Includes interest paid on loans and advances etc.
2.4	rent paid	Rent paid on land, building, machinery etc.
2.5	other operating expenses (goods and services purchased for current activities of institution)	Sum of current expenditure on purchase of medicines, food articles, stationery, books, printing, advertisements, transportation, audit fees, repairs and maintenance, electricity, water & telephone charges and any other service charges made to outside agencies maybe recorded.
2.6	grants given to other institutions	Some of the societies may be giving grants or scholarships etc. to others and may be reporting in their income & expenditure account. Such expenditure may be recorded here.
2.7	value of goods given free	As available in Income & Expenditure accounts.
2.8	provision for depreciation	Depreciation provision as provided in books of accounts may be taken.
2.9	taxes	2.9.1 indirect
		Taxes in the form of service tax, VAT, sales tax,

--	--	--	--	--	--	--

	paid	(service tax, vat, sales tax etc. )	stamp duties may be recorded.
		2.9.2 direct (income/ corporate tax /cess on income)	Any income tax/cess paid by the institution other than the tax paid on behalf of employees may be noted.
	<b>total expenditure-current (2.1 to 2.9)</b>		Sum total of items 2.1 to 2.9.

--	--	--	--	--	--	--

3	investment in physical assets	Description
3.1	land	The value of acquisition of land during the year may be recorded in additions; and the value of land at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.2	buildings	The value of acquisition/construction of buildings during the year may be recorded in additions; and the value of buildings at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.3	other construction and land development	Any expenditure made on other construction such as roads, swimming pools, stadiums, stands, rope-ways, etc. and land development & improvement during the year may be recorded in additions and the value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.4	plantation and garden development	Any expenditure made on plantation and garden development during the year may be recorded in additions and the value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.5	machinery and equipments	The value of acquisition of machinery and equipments during the year may be recorded in additions; and the value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.6	transport equipment	The value of acquisition of transport equipment during the year may be recorded in additions; and value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.7	other office equipment	The value of acquisition of other office equipment such as computers, fax machines, printers, etc. during the year may be recorded in additions; and value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.

--	--	--	--	--	--	--

3.8	other physical assets n.e.c.	The value of acquisition of other physical assets n.e.c. during the year may be recorded in additions; and the value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
3.9	valuables	The value of acquisition of valuables such as paintings, sculptors, precious metals, antiques and other art objects during the year may be recorded in additions; and the value of these assets at the end of the reference period may be recorded in closing balance column.
	total (3.1 to 3.9)	Sum total of items 3.1 to 3.9.

4	investment in financial assets (change during accounting year)	Description
4.1	government securities	Investments made during the year by the society in the government securities such as National Saving Certificates, Kisan Vikas Patra, etc. may be recorded here.
4.2	public sector securities	Investments made during the year by the society in the public sector securities such as shares, bonds of public sector cooperations such as power finance cooperation, banks etc. may be recorded here.
4.3	private sector shares and debentures	Investments made during the year by the society in the private sector companies such as IDBI, ICICI, etc. may be recorded here.
4.4	investment in bank fixed deposits	Investment in fixed deposits in the banks during the year may be recorded here
4.5	other investments n.e.c.	Other investments not elsewhere classified

--	--	--	--	--	--	--

		during the year may be recorded here.
5	<b>cash in hand</b>	Here, change in the balance of cash in hand i.e. closing balance (-) opening balance may be recorded.
6	<b>bank balance</b>	Change in the bank balance i.e. closing balance (-) opening balance may be recorded.

7	<b>other balance sheet items</b> (change during the accounting year)	<b>Description</b>
7.1	funds (excluding item 7.4 and 7.7)	Change in all funds like general fund, capital fund, endowment fund, etc. Changes in these items during the year must exclude item 7.4 (excess of income over expenditure) and item 7.7 (excess of expenditure over income) if included in funds in the balance sheet.
7.2	loans and advances (received)	Change in the head 'loans and advances' secured as well as unsecured on the liability side of the balance sheet may be taken.
7.3	other financial liabilities n.e.c.	Change in 'other financial liabilities' such as sundry creditors, amounts payable, miscellaneous provisions, provisions for gratuity, etc. on the liability side of the balance sheet may be taken.
7.4	excess of income over expenditure	As available in Balance sheet (liabilities side).
7.5	loans and advances (given)	Change in the head 'loans and advances' made to other institutions/employees on the asset side of the balance sheet may be taken.
7.6	other financial assets n.e.c.	Change in 'other financial assets' such as sundry debtors, amounts receivable, etc. on asset side of the balance sheet may be taken.
7.7	excess of expenditure over income	As available in Balance sheet (assets side).
8	<b>total funds (closing balance)</b>	Total of all funds like general fund, capital fund, endowment fund, etc. at end of the reference



--	--	--	--	--	--	--

		period.
--	--	---------

**7. Items of Block 3:** The investigator may give his/her remarks regarding the following:

- i. partial data collection in the schedule and reasons thereof
- ii. difficulties faced by him in collection of data

**8. Items of Block 4:** The officer inspecting the work relating to this schedule may scrutinize the schedule keeping in view the general instructions and inter-block consistency and give his/her comments here.

### **Instructions for filling information in Key Data Schedule 2.0: K: Employment and Financial Parameters of Societies**

9. **Schedule 2.0: K** is to be used only for those societies where accounts are prepared but not available or accounts are not maintained. It requires data to be filled in only against 15 items. It contains the following blocks:

Block 1: employment particulars of the society (as on date)

Block 2: financial information (in Rs.) about the society

Block 3: remarks by investigator

Block 4: remarks by supervisory officer

10. **Items of Block 1:** Block 1 contains employment particulars of the society as on the date of collection of data and not in respect of reference year of the survey.

	<b>employment particulars of society</b>	<b>Description</b>
(1)		
1	number of volunteers (including governing body members)	Number of volunteers, segregated into number of males and females, maybe recorded.
2	number of employed persons	Total number of persons employed i.e. receiving salaries/wages. Against this, first fill the first column i.e. 'total', then segregate into males and females. In this respect, the information given by the informer may be treated as correct.

--	--	--	--	--	--	--

3	total (1+2)	Total number of persons working as volunteers or as employees.
---	-------------	--

11. **Items of Block 2:** Block 2 contains financial information about the society. Brief description of items 1 to 4 is given below. **Financial data in this block is to be given in rupees.**

**Reference period of the survey** is April 2007-March 2008. In case the financial information is not available for this year then this information may be collected for the latest year.

(2)	financial information	Description
1	total funds (at the end of the financial year)	Total of all funds like general fund, capital fund, endowment fund, etc. at the end of the reference period.
2	total fixed assets (at the end of the financial year)	Total value of all fixed assets like land, building, machinery and equipment etc. at the end of the financial year may be recorded.
expenditure during the reference period		
3	total expenditure including expenditure on purchase of fixed assets	Total operational expenditure incurred by the society and expenditure incurred on purchase of fixed assets like land, building, etc. may be recorded. It may be noted that this is not the total of items 3.1 to 3.3.
<i>of which expenditure on</i>		
3.1	salary, wages and allowances (incl. PF, gratuity and welfare expenditure etc.)	Any emolument paid in cash or kind to the employed persons in lieu of services rendered to the society including any contribution made by society on behalf of employee, such as insurance, gratuities and provident fund, etc.
3.2	honorarium	Any amount, in cash or kind, given to governing body members/volunteers or other workers, in lieu of work done for the society, which is not classified as salary, wages and allowances, may be recorded.
3.3	purchase of fixed assets	Expenditure incurred on purchase or development of assets like land, building, machinery, transport equipment and plantation etc. may be recorded.

--	--	--	--	--	--	--

income during the reference period		
4	total income including grants received for purchase/acquisition of fixed assets	Here, total income should be sum total of items 4.1 to 4.5.
of which		
4.1	total grants received including grants received for purchase/acquisition of fixed assets	This item should include financial aid received by an institution for meeting their current expenditure such as salaries, consumables etc. and financial aid received by an institution for acquisition of capital assets such as buildings, land, machines etc. from any other institution like government, corporations, foreign bodies, etc.
4.2	membership subscription	Any amount received as a membership fees or subscription may be recorded.
4.3	donations and offering	Any amount received as donations or offerings may be recorded.
4.4	income received from operations (sale of goods and services)	This item should include the income on account of goods or services provided by the institutions to others, such as sale of books or periodicals, medicines, food items, investigation charges, fees, registration charges, hostel charges, guest house charges, hall booking charges, theatre charges etc.
4.5	other incomes including income from interest and dividend, rent etc.	All other incomes including income from interest, dividend, rent etc. may be recorded.

**12. Items of Block 3:** The investigator may give his/her remarks regarding the following:

- i. partial data collection in the schedule and reasons thereof
- ii. difficulties faced by him in collection of data

**13. Items of Block 4:** The officer inspecting the work relating to this schedule may scrutinize the schedule keeping in view the general instructions and inter-block consistency and give his/her comments here.